रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एम.)—78

REGISTERED No. D. (D.N.)—78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 1982/अग्रहायण 27, 1904
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 1982/AGRAHAYANA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1982

आय-कर

का. आ. 4172.—सर्व साधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(1) यह कि कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इण्डिया, मद्रास प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि/पशु-पालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का प्रथक् लेखा रखेगा और जैसा कि उनके पत्र सं. 11/2/81 के एफ आई तारीख 13-3-1982 से निर्देशित है, उनको केवल सूक्ष्म संसाधित के अनुप्रयोग के लिए केन्द्र में अनुसंधान के लिए ही उपयोजन किया जाएगा ।

(2) यह कि उक्त फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाए ।

(3) यह कि उक्त फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष के लिए प्रवर्ग लेखाओं का वार्षिक सम्परीक्षित विवरण अपनी कुल आय और व्यय तथा अपनी तुलन-पत्र आस्तियों/दायित्वों को दर्शित करते हुए, विहित प्राधिकारी को प्रतिवर्ष 30 जून तक प्रस्तुत करेगा और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति सम्बद्ध आय-कर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इण्डिया, मद्रास ।

यह अधिसूचना 8-6-1982 से 7-6-1984 तक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं. 4788/पत्र सं. 203/169/80-आई. टी. ए. (2)]

एम. जी. सी. गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 7th July, 1982

INCOME TAX

S.O. 4172.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences, subject to the following conditions :—

(i) That the Krishnamurti Foundation India, Madras will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural and applied sciences and solely apply them for research in Centre for Application of Micro processors as outlined in their letter No. 11/2/81-KFI dated 13-3-1982.

(ii) That the said Foundation will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Foundation will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy each of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Krishnamurti Foundation India, Madras.

This notification is effective for a period of two years from 8-6-82 to 7-6-84.

[No. 4788[F. No. 203|169|80-ITA(II)]

M. G. C. GOYAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1982

आयकर

का०आ० 4173.—केन्द्रीय सरकार, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा (2)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री मार्तण्ड देव संस्थान, जेजुरी" को महाराष्ट्र राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

[सं० 4920/फा० सं० 176/48/82-आ०का० (ए-I)]

New Delhi, the 21st September, 1982

(INCOME-TAX)

S.O. 4173.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Martand Deo Stnsthan, Jejuri" to be a place of public worship of renown throughout the State of Maharashtra.

[No. 4920/F. No. 176/48/82-IT(AI)]

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1982

आयकर

का० आ० 4174.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, देवुनी गुड्डापाह" को, आन्ध्र प्रदेश राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1985-86 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए प्रभावी होगी ।

[सं० 4921/फा० सं० 176/45/81-आ०क० (ए-I)]

New Delhi the 22nd September, 1982

INCOME-TAX

S.O. 4174.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Lakshmi Venkateswaraswamy Temple, Devuni-Cuddapah" to be a place of public workship of renown throughout the State of Andhra Pradesh.

2. This notification shall have effect from the period covered by Assessment Year 1981-82 to 1985-86.

[No. 4921|F. No. 176|45|81-IT(AI)]

आयकर

का० आ० 4175.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "अरुलमिगु काशी विश्वनाथ स्वामी थिरुकोइल; टेन्कासी जिला तिरुनेलवेरी (तमिल नाडु)" को तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

[सं० 4922/फा० सं० 176/26/82 आ०क० (ए-I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 4175.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Arulmigu Kasiviswanathaswamy Thirukoil, Tenkasi, Tirunelveli Distt, (Tamil Nadu)" to be a place of public workship of renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 4922|F. No. 176|26|82-IT(AI)]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1982

(आयकर)

का० आ० 4176.—केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं० 679 तारीख 20-7-74 का निम्नलिखित संशोधन करता है ।

क्रम सं० 5-ङ के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

आयकर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
5-ङ (अन्वेषण), मुम्बई नगर।	मुम्बई	1. सर्वेक्षण सर्किल-I 2. सर्वेक्षण सर्किल-II 3. निर्धारण सर्किल-XI 4. निर्धारण सर्किल-XII

यह अधिसूचना 12 जुलाई, 1982 से प्रभावी होगी ।

[सं० 4786/फा० सं० 185/123/82-II (ए०आई०)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 7th July, 1982

(INCOME-TAX)

S. O. 4176 .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to its Notification No. 679 dated 20-7-74 as amended from time to time.

The existing entries against Sl. No. 5-L shall be substituted as follows:—

Commissioner of Income Tax	Headquarters	Jurisdiction
5-L (Investigation) Bombay City.	Bombay	1. Survey Circle-I. 2. Survey Circle-II. 3. Assessment Circle XI. 4. Assessment Circle XII.

This notification shall take effect from 12th July, 1982

[No. 4786 /F. No. 185/123/82—IT(AI)]

MILAP JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

Office of the Deputy Chief Controller of Imports & Exports

CANCELLATION ORDER

Jaipur, the 25th August, 1982

S.O. 4177.—M/s. Goel Cold Rolling Mill, A-95(B), Industrial Area, Bhiwadi, Distt. : Alwar (Raj.), were granted Import licence No. P|S|1865035|C|XX|78|80 dated 12-3-1981 for Rs. 5,00,000 only for import of All Seconds/Second Goods|Defective|Quittings|Circles in|Uncoated Condition of All grade of Carbon Steel Plates|Sheets|Strips coils in Any Form|Shape of Policy Book for AM 81 required for the manufacture of Agriculture Implements.

The applicant has filed an affidavit as required under para 358 of Hand Book of Import Export Procedure 1982-83 wherein they have stated that original Exchange Purposes Copy of Licence No. P/S/1865035 dated 12-3-1981 for Rs. 5,00,000 only for AM 81 period has been misplaced/lost without having registered with any Customs House and utilised partly for Rs. Nil.

I am satisfied that the original Exchange Purpose Copy of the said licence has been lost/misplaced.

In exercises of the powers conferred on me under section 9(cc) of Import Trade Control order, 1955 dated 7th Dec. 1955 as amended upto date the Exchange Purpose Copy of the Licence No. P/S/1865035 dated 12-3-1982 for Rs. 5,00,000 only is hereby cancelled.

The applicant is now being issued duplicate Exchange Purpose Copy of Import Licence No. P/S/1865035 dated 12-3-1982 for the CIF value of Rs. 5,00,000 only in accordance with the provision of para 352 to 354 of Hand Book of Import Export Procedures 1982-83.

[F. No. SSI/N/10|AM. 81|Sec. I|Raj|DCCI&E]

वाणिज्य मंत्रालय

(उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

निरस्त-आदेश

जयपुर, 25 अगस्त, 1982

का०आ० 4177.—मैसर्स गोयल कोल्ड रौलिंग मिल्स, ए-95(बी) इण्डस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी (जि० अलवर) राज को आयात ला० सं० पी/एस/1865035/सी/XX/78/Q/80 दि० 12-3-81 वास्ते 500,000/- रु० मात्र आल सेकन्ड्स/सैकन्ड ग्रेड्स/डिफेक्टिव/कोटिंग्स/सर्कल्स/अनकोटेड कन्डीशन्स आफ आल ग्रेडस आफ कार्बन स्टील प्लेट्स/शीट्स /स्ट्रिप्स/कायल्स किसी भी प्रकार की/शक्ल की अप्रैल-मार्च-81 की आयात-नीति के अनुसार, कृषि उपकरणों के उत्पाद हेतु जारी किया गया था।

आवेदक ने एक शपथ-पत्र आयात-निर्यात की कार्य विधि पुस्तिका 1982-83 के पैरा 358 के अन्तर्गत इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उनके लाइसेंस स० पी/एस/1865035 दि० 12-3-81 वास्ते 5,00,000 रु० मात्र अप्रैल-मार्च-81 अवधि के लिए की मूल एक्सचेंज हेतु कापी जो बिना किसी कास्टम पर पंजीकृत किए या इस्तेमाल किए ही खोई गई है।

मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल एक्सचेंज हेतु कापी खो गई है।

अतः आयात-व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दि० 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9(CC) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ला० स० पी०/एस/1865035 दि० 12-3-82 वास्ते 5,00,000 रु० की एक्सचेंज हेतु कापी निरस्त की जाती है।

आवेदक को अब ला० स० पी/एस/1865035 दि० 12-3-82 वास्ते 5,00,000 रु० मात्र की एक्सचेंज हेतु कापी की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) आयात-निर्यात की कार्य विधि पुस्तिका 1982-83 के पैरा 352 से 354 के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

[सं० एस/एस/आई/एन /10/ ए एम-81/सेक I/राज/डीसीसीआई एण्ड ई]

निरस्त आदेश

का०आ० 4178.—मैसर्स जे० जी० इन्जीनियरिंग एण्ड मेटल इन्डस्ट्रीज, प्लाट सं० ए-95 (ए) इन्डस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी अलवर (राज) को एक आयात लाइसेंस सं० / पी / एस 1865036/सी/XX/78/क्यू/80 दि० 12 3 81 वास्ते 5,00,000 रु० सभी सैकेण्ड्स/सैकण्ड गुड्स/डिफेक्टिव्स/कटिंग्स/सर्कल्स/बिना कोट किए हालत में सभी ग्रेडों के कार्बन/स्टील प्लास्ट्स/शीट्स/स्ट्रिप्स कायल्स किसी भी किस्म या शक्ल में अप्रैल-मार्च—81 की आयत नीति के अर्न्तगत कृषि उपकरणों के उत्पाद के हेतु जारी किया गया था।

आवेदक फर्म एक शपथ-पत्र आयात-निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1982-83 के पैरा 352 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके लाइसेंस पी/एस/1865036 दि० 12-3-81 वास्ते 5,00,000 रु० मात्र अप्रैल-मार्च—81 की अवधि के लिए की एक्सचेंज हेतु कापी बिना किसी कस्टम पर पंजीकृत किए या इस्तेमाल किए ही खो गई है। मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल एक्सचेंज हेतु कापी खो गई है।

अतः आयात निर्यात नियंत्रण आदेश, 1955 दि० 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9(CC) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाइसेंस संख्या पी/एस/1865036 दि० 12-3-81 वास्ते 5,00,000 रु० मात्र की एक्सचेंज कन्ट्रोल हेतु कापी निरस्त की जाती है।

आवेदक को अब ला० सं० पी/एस/1865036 दि० 12-3-81 वास्ते 5,00,000 की एक्सचेंज हेतु कापी की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) जारी की जा रही है जिसे आयात-निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1982-83 के पैरा 352 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

[एसएसआई/एन-11/ए एम-81/सेक्स-I/बी/सीसीआई एण्ड ई/राज]

एस० के० दत्ता, उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

CANCELLATION ORDER

S.O. 4178.—M/s. J. G. Engineering & Metal Industries, Plot No. A95 (A) Industrial Area, Bhiwadi-Alwar (Raj.) were granted Import Licence No. P/S/1865036|C|XX|78|Q| 80 dated 12-3-1981, for Rs. 5,00,000 only for import of All seconds|Second goods|Defectives|Quttings|Circles| un-coated condition of all grades of Carbon Steel Plates/ Sheets/Strips Coils in any form/Shape of Policy Book for AM 81 required for the manufacture of Agriculture Implements.

The applicant has filed an affidavit as required under para 352 of Hand Book of Import Export Procedure 1982-83, wherein they have stated that original Exchange purposes copy of Licence No. P/S/1865036 dated 12-3-1981 for Rs. 5,00,000 only for AM 81 period has been misplaced/ lost without having been registered with any Customs House and utilised partly for Rs. Nil.

I am satisfied that the original Exchange Purpose Copy of the said licence has been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on me under section 9(cc) of Import Trade Control Order 1955 dated 7th Dec., 1955 as amended upto date, the Exchange Purpose Copy of the licence No. P/S/1865036 dated 12-3-1981 for Rs. 5,00,000 is hereby cancelled.

The applicant is now being issued duplicate Exchange Purpose Copy of Import Licence No. P/S/1865036 dated 12-3-1981 for the CIF value of Rs. 5,00,000 only in accordance with the provision of para 352 to 354 of Hand Book of Import-Exprt Procedure 1982-83.

[F. No. SSI/N/11|AM. 81|Sec. I|DCCI&E|RAJ]

S. K. DUTTA, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1982

का. आ. 4179 :—केन्द्रीय सरकार, पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 152 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2), तारीख 30 अगस्त, 1975 के पृष्ठ संख्या 3160 से 3162 पर प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 2819 तारीख 29 जुलाई, 1975 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

"2 असम" शीर्षक के नीचे शिलांग से सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"वही—कुलपति, पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, लोअर लशोमियर, शिलांग, असम-793001 ।"

[फा. सं. 8(13)/81-पी पी एंड सी]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 10th November, 1982

S.O. 4179.—In exercise of the powers conferred by Section 152 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) S.O. No. 2819, dated the 29th July, 1975, published in the Gazette of India, Part II Section 3 Sub-section (ii), dated the 30th August, 1975 at pages 3160 to 3162; namely :—

In the said notification, under the heading "2. Assam"— after the existing entries relating to Shillong, the following shall be inserted, namely :—

"-do- The Vice Chancellor, North Eastern Hill University, Lower Lachaumiere, Shillong, Assam-793001.

[File No. 8(13)/81-PP&C]

का. आ. 4180 :—केन्द्रीय सरकार, पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 152 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2) तारीख 30 अगस्त, 1975 के पृष्ठ सं. 3160 से 3162 पर प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सख्या का. आ. 2819 तारीख 29 जुलाई, 1975 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

"8 केरल" शीर्षक के नीचे—त्रिवेन्द्रम से सम्बन्धित विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"कोचीन विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, कोचीन विश्वविद्यालय पुस्तकालय, कोचीन-682022 ।"

[फा. सं. 8(13)/81-पी. पी. एण्ड सी]

पी. आर. चन्द्रन, उप सचिव

S.O. 4180.—In exercise of the powers conferred by Section 152 of the Patents Act, 1970 (30 of 1970), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies, (Department of Industrial Development) S. O. No. 2819, dated the 29th July, 1975, published in the Gazette of India, Part II Section 3 Sub-section (ii) dated the 30th August, 1975 at pages 3160 to 3162 : namely :—

In the said notification, under the heading "8 Kerala" after the existing entries relating to Trivandrum, the following shall be inserted, namely :—

"Cochin.—University Librarian, Cochin University Library, Cochin-682022."

[File No. 8(13)/81-PP&C]

P. R. CHANDRAN, Dy. Secy.

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 23-11 1982

का० आ० 4181—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम 4 के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल०749765 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं लाइसेंसधारी के अनुरोध पर 1982-07 01 से रद्द कर दिया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम व पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी एम/एल-0749765	मैसर्स चित्रालय बनियान कं०, 55-ए, धरापुरम रोड, तिरुपुर-638604 (तमिलनाडु)	इंटरलॉक बुनाई वाली सूती बनियाने टाइप गोल गले वाली और गोल गले बाजू वाली साइज 75 से 100 से मी जाली 20 और 24	IS 4965 (भाग 2)—1975 इन्टर लॉक बुनाई वाली सूती बनियानों की विशिष्ट भाग 2 बनियाने (पहला पुनरीक्षण) .

[सी एम डी/55 0749765]

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 1982-11-17

S. O. 4181.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-0749765 particular of which are given below has been cancelled with effect from 82-07-01 at the request of the licensee :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name and Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licence Cancelled	Relevant Indian Standards
1	2	3	4	5
1.	CM/L-0749765	M/s. Chitralaya Banian Co., 55-A, Dharapuram Road, Tirupur-638604 (Tamil Nadu)	Interlock Knitted Cotton Vests Type : RN and RNS Size : 75 to 100 cm Gauge : 20 and 24	IS: 4965 (Part II)—1975 Specification for Interlock knitted cotton vests Part II Vests (First Revision)

[CMD/55 : 0749765]

नई दिल्ली, 1982-11-23

का० आ० 4182—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम 4 के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-0767464 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं लाइसेंसधारी के अनुरोध पर 1982-02-01 से रद्द कर दिया गया है क्योंकि फर्म अब लाइसेंस जारी रखने की इच्छुक नहीं है।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी एम/एल-0767464 1979-03-30	मैसर्स बंगलौर कॉटन राड मिल (ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लि० की इकाई) हवाइटफील्ड रोड महादेवपुरा डाकघर बंगलौर 560048	गढ़ी वस्तुओं के लिए कार्बन इस्पात की छड़े	IS 1975—1978 गढ़ी वस्तुओं के लिए कार्बन इस्पात के बिलेट, ब्लूम सिल्लियां और छड़ों की विशिष्ट (चतुर्थ पुनरीक्षण)

[सी एम डी/55 . 0767464]

New Delhi, the -198211-23

S.O. 4182. — In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-0767464 particulars of which are given in the Schedule below has been cancelled with effect from 1982-02-01 as the firm is not interested to operate the licence.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licence Cancelled	Relevant Indian Standards
1	2	3	4	5
1.	CM/L-0767464 1979-03-30	M/s. Bangalore Wire Rod Mill, (A unit of Transport Corpn of Indian Ltd)., Whitefield Road, Mahadevapura P.O., Bangalore-560048	Carbon steel bars for forgings	IS : 1875-1978 Specification for carbon steel billets, blooms, slabs and bars for forgings, (Fourth Revision)

[CMD/55 : 0767464]

नई दिल्ली, 1982-11-24

का०आ० 4183.—भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1981-05-16 में प्रकाशित नागरिक पूर्ति मंत्रालय (भारतीय मानक संस्था) अधिसूचना संख्या एस ओ 1499 दिनांक 1981-04-24 का आंशिक रूप में संशोधन करते हुए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कटाई और वेल्डिंग के लिए दाब रेग्युलेटरों और ब्लो पाइप के मानक चिन्ह में कुछ परिवर्तन किया गया है । मानक चिन्ह को ये संशोधित डिजाइन तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक और डिजाइन के शाब्दिक विवरण सहित नीचे अनुसूची में दी गई है ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952, और इसके अधीन बने नियमों और विनियमों के कार्यों के लिये ये मानक चिह्न 1980-12-16 से लागू होंगी :

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पादन की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	मानक चिह्न के डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		वेल्डिंग, कटाई में प्रयुक्त गैस सिलैण्डरों के दाब रेग्युलेटर	IS : 6901—1973 वेल्डिंग, कटाई और सम्बद्ध प्रक्रियाओं में प्रयुक्त गैस सिलैण्डरों के दाब रेग्युलेटरों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी गई है।
2.		वेल्डिंग और कटाई में प्रयुक्त हाथ वाले ब्लो पाइप	IS : 7653—1975 वेल्डिंग और कटाई में प्रयुक्त हाथ वाले ब्लो पाइप की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी गई है ।

[सं० सी एम डी/13.9]

New Delhi, the 1982-11-24

S.O. 4183. — In partial modification of the Ministry of Civil Supplies (Indian Standards Institution) notification number S.O 1499 dated 1981-04-24, published in the Gazette of India, Part—II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1981-05-16, the Indian Standards Institution, hereby notifies that the standard marks for pressure regulators and manual blow pipes for cutting and welding have been revised. The revised designs of the standard Marks together with the title of the relevant Indian Standards and verbal description of the designs are given in the following Schedule.

These Standard Marks, for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1980-12-16:

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal Description of the design of the Standard Mark
1	2	3	4	5
1.	IS : 6901	Pressure regulators for gas cylinders used in welding, cutting	IS : 6901 —1973Specification for pressure regulators for gas cylinders used in welding, cutting and related processes	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated is Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.
2.	IS : 7653	Manual blow pipes for welding and cutting	IS : 7653—1975 Specification for manual blowpipes for welding and cutting	The monogram of the India Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated is Col (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

का० आ० 4184.—भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 19-80-04-26 में प्रकाशित तत्कालीन वाणिज्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय (भारतीय मानक संस्था) अधिसूचना संख्या एस ओ 1155 दिनांक 1980-04-09 का आंशिक रूप से संशोधन करते हुए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ब्वायलर टेप डिबरी और कावसे के लिए आर्सेनिकीय ताम्बे की छड़ों के मानक चिह्न में कुछ संशोधन किया गया है। मानक चिह्न को संशोधित डिजाइन तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक और डिजाइन के शाब्दिक विवरण सहित नीचे अनुसूची में दिया गया है।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1953 और उसके अधीन बने नियम और विनियम के कार्यों के लिए यह मानक चिह्न 1982-02-01 से लागू होगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पादन की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	मानक चिह्न के डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS: 288—81	ब्वायलर टेक डिबरी और कावलों के लिए आर्सेनिकीय ताम्बे की छड़ें	IS : 288—1981 ब्वायलर टेक डिबरी और कावलों की विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार की गई है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक संस्था की पदसंख्या तथा वर्ष दिया गया है।

[सं० सी एम डी/13:9]

S.O. 4184.—In partial modification of the then Ministry of Commerce and Civil Supplies (Department of Civil Supplies) (Indian Standards Institution) notification number S.O. 1155 dated 1980-04-09 published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Subsection (ii) dated 1980-04-26, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the design of the Standard Mark for arsenical copper rods for boiler stay bolts and rivets has been revised. The revised design of the Standard Mark together with the title of the relevant Indian Standard and verbal description of the design is given in the following Schedule :

This Standard Mark for the purposes of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1982-02-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/class of Product	No. & Title of the Relevant Indian Standard	Verbal Description of the Design of the Standard Mark
1	2	3	4	5
1. IS : 288-81		Arsenical copper rods for boiler stay bolts and rivets	IS : 288-1981 Specification for arsenical copper rods for boiler stay bolts and rivets (second revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard, alongwith its year, being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

फा० आ० 4185.—भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1979-12-01 में प्रकाशित तत्कालीन वाणिज्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) (भारतीय मानक संस्था) अधिसूचना संख्या एस ओ 3880 दिनांक 1979-11-08 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि एलुमिनो-लौह का मानक चिह्न में कुछ संशोधन किया गया है मानक चिह्न की संशोधित डिजाइन तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक और डिजाइन के शाब्दिक विवरण सहित नीचे अनुसूची में दी गई है ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन) चिह्न अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बने नियम और विनियम के कार्यों के लिए यह मानक चिह्न 1981-06-01 से लागू होगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पादन की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	मानक चिह्न के डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. IS: 299—80		एलुमिनो लौह	IS: 299—1980 एलुमिनो लोह की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या तथा वर्ष दिया गया है।

[सी एम डी/13 : 9]

S. O. 4185 .—In supersession of the then Ministry of Commerce and Civil Supplies (Department of Civil Supplies) (Indian Standards Institution) notification number S.O. 3880 dated 1979-11-08 published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1979-12-01, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the design of the Standard Mark for alumino-ferric has been revised. The revised design of the Standard Mark together with the title of the relevant Indian Standard and verbal description of the design is given in the following Schedule.

This Standard Mark for the purposes of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1981-06-01 :

THE SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard	Product/Class of Product	No. & Title of the Relevant Indian Standard	Verbal Description of the Design of the Standard Mark
1	2	3	4	5
1. IS : 299—80		Alumino-ferric	IS : 299—1980 Specification for alumino-ferric (third revision)	The monogram of the Indian Standard Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard, alongwith its being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

का० आ० 4186.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 3 के उपविनियम 2 और विनियम 3 के अनुसार भारतीय मानक संस्था की अधिसूचना द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए भारतीय मानक 31 जनवरी 1980 को स्थापित हो गए हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	IS भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानकों की संख्या और शीर्षक	अभ्युक्ति विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IS 74—1979 रसायनिक मूल्यांकन के लिए खाद सूखा व (तरल) के परीक्षण और नमूने लेने की पद्धति (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS 74—1966 पटसन के लिए नमूने लेने और परीक्षण की पद्धति (प्रथम पुनरीक्षण)	—
2	IS 104—1979 तैयार मिश्रित रोगन बुरुश से लगाने वाला, जिंक क्रोम प्राइमर देने की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS 104—1962 तैयार मिश्रित रोगन बुरुश से लगाने वाला, जिंक क्रोम प्राइमर देने की विशिष्टि (पुनरीक्षण)	
3	IS 719—1979 हवाई स्थान कार्यों के लिए सूती प्रबलन टेपों की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS 719—1962 हवाई जहाज के लिए सूती प्रबलन टेप की विशिष्टि (पुनरीक्षण)	—
4	IS 808 (भाग 3)—1979 तप्त बेल्लित इस्पात की धरनें, चैनल व कोण सेक्शन के माप भाग 3 चैनल एम सी और एम सी पी श्रेणी (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS 808—1964 बेल्लित इस्पात की धरनें चैनल और कोण सेक्शन की विशिष्टि (पुनरीक्षण)	—
5	IS 1061—1980 कागज के आकारों की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS 1061—1961 कागज के आकारों की विशिष्टि (पुनरीक्षण)	—
6	IS 1109—1980 मुहरों की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS 1109—1968 मुहरों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	—
7	IS 1376—1979 हवाई स्थान के लिए सूती सिलाई धागों की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS 1376—1968 हवाई स्थान के वैमानिक के लिए सूती सिलाई धागों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	—
8	IS 1448 (भाग 3)—1979 पेट्रोलियम और उसके उत्पादों की परीक्षण पद्धति भाग 93 पेट्रोलियम मोम में सुई भेदन	—	—
9	IS 1651—1979 सीसा तेजाब वाली स्थिर (धनात्मक नली प्लेट के साथ) बैटरियों और स्थिर सैल की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS 1651—1970 सीसा अम्ल वाली धनात्मक नली प्लेट के साथ बैटरियां और स्थिर सेल की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	—
10	IS 1852—1979 उष्म बेल्लित इस्पात उत्पादों की बेल्लन और कटाई सम्बन्धी छूट (तृतीय पुनरीक्षण)	IS 1852—1973 उष्म बेल्लित इस्पात उत्पादों का बेल्लन और कटाई सम्बन्धी छूट (द्वितीय पुनरीक्षण)	— —
11	IS 2032 (भाग XXIII)(1978) विद्युत प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त लेखी चिह्न भाग XXIII प्रक्रम माप व नियंत्रण सम्बन्धी औजार।	—	—
12	IS 2279—1980 अच्छी चांदी की छड़ें, चादर, तार, कणी तथा टोका की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS 2279—1963 अच्छे चांदी की छड़ें, चादर तार कणी और टोका (मोहर व लगदी) की विशिष्टि	—
13	IS 2560—1979 ट्यूब के लिए न पकने वाले रबड़ से बने टेप की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS 2560—1963 टायर व ट्यूब के लिए रबड़ से बने न पकने वाले टेप की विशिष्टि	—
14	IS 2562—1979 टायर व ट्यूब के लिए रबड़ से बने पकने वाले टेप की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS 2562—1963 टायर व ट्यूब के लिए रबड़ से बने पकने वाले टेप की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	—
15	IS 2417—1979 काचाभ मीना वर्तन और मृत्तिका शिल्प धातु प्रणाली से सम्बन्धित शब्दावली (प्रथम पुनरीक्षण)	IS 2717—1964 काचाभ मीना वर्तन उद्योग में प्रयुक्त शब्दों वाली	—
16	IS 3347—(भाग 1, खंड 2)—1979 सामान्य और हल्के प्रदूषित वातावरण में प्रयुक्त पोर्सलेन ट्रांसफार्मर बुशबर्दे के माप भाग 1 1 किवा तक खण्ड 2 धातु के भाग (प्रथम पुनरीक्षण)	IS 3347—(भाग 1 खण्ड 2)—1967 पोर्सलेन ट्रांसफार्मर बुशबर्दे के माप भाग 1 1 किलोवा बुशबर्दे तक खण्ड 2 धातु के भाग	—

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	IS : 3347 (भाग II—खण्ड 2)—1979 सामान्य व हल्के प्रदूषित वातावरण में प्रयुक्त पोसिलेन ट्रांसफार्मर बुशबंदी के माप भाग 1. कि वो तक खण्ड 2 धातुर्क भाग (प्र० पुनरीक्षण)	IS : 3347 (भाग II/खंड 2)—1967 पोर्सिलेन ट्रांसफार्मर बुशबंदी भाग 1 1.1 कि वी बुशबंदी की खण्ड 2 धातु के भाग	—
18.	IS : 3607—1979 रसायन उद्योग के लिए मैरनीसाइट की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS . 3607—1966 रसायन उद्योग के लिए मैरनीसाइट की विशिष्टि	
19.	IS 3607—1979 चिनाई वाले लैटराइट पत्थर के चौकों की विशिष्ट (प्रथम पुनरीक्षण)	IS: 3620—1966 चिनाई वाले लैटराइट पत्थर के चौकों की विशिष्ट	—
20.	IS 4491—1979 उच्च चुम्बकीय प्रवेश्यता वाली इस्पात की ढली वस्तुओं को विशिष्ट (प्रथम पुनरीक्षण)	IS 4491—1968 उच्च चुम्बकीय प्रवेश्यता वाली इस्पात की ढली वस्तुओं की विशिष्टि	
21.	IS: 4651 (भाग 4)—1979 बन्दरगाहों और गोदियों की डिजाइन व आयोजना की रीति संहिता भाग 4 सामान्य डिजाइन सम्बन्धी बातें (प्रथम पुनरीक्षण)	IS: 4651(भाग 4)—1969 बन्दरगाहों और गोदियों की डिजाइन व योजना की रीति संहिता भाग 4 पाइल की चादर की प्रतिधारक दीवार	—
22.	IS : 4659—1980 अंतः स्थलीय जलयानों के लिए तार की रील की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS: 9659—1968 अंतः स्थलीय जलयान के लिए तार की रील की विशिष्टि	—
23.	IS : 4738—1980 प्लास्टर आफ पैरिस की पट्टी की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 9738—1968 प्लास्टर आफ पेरिस की पट्टी की विशिष्ट	—
24.	IS : 4903—1979 चीनी उद्योग निःस्राव के उपचार और निपटान की संदर्शिका (प० पु०)	IS : 4903—1968 चीनी उद्योग की निःस्राव के उपचार और निपटान की संदर्शिका	—
25.	IS : 5405—1980 सेसीटरी नैपकिन की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS: 5405—1969 सैमेनेटरी नैपकिन की विशिष्ट	—
26.	IS : 5733—1979 सेब की कलमो की उत्पादन संहिता (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 5733—1969 सेबों की कलमें	—
27.	IS: 7022 (भाग 2)—1979 मलजल और औद्योगिक निःस्राव सम्बन्धी शब्दावली भाग 2	—	—
28.	IS : 7290—1979 छतों के जल रोक बनाने के लिए पोलीइथाइलीन फिल्म के प्रयोग संबंधी सिफारिशें (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 7290—1973 छतों के जल रोक बनाने के लिए पोलीइथाइलीन फिल्म के प्रयोग संबंधी सिफारिशें	—
29.	IS : 8252 (भाग 4)—1980 विमान उपकरणों के वातावरणीय परीक्षण भाग 4 बर्फ निर्माण		
30.	IS : 8252 (भाग 14)—1979 विमान उपकरणों के वातारणीय परीक्षण भाग 14 झटका	—	—
31.	IS : 8886 (भाग 4)—1980 जलयान की साधारण, आयताकार, खिड़कियों की विशिष्ट भाग 4 ढांचे पर कब्जों के कान, स्विंग काबलों और जड़ने के छेदों की स्थिति के ब्यौरे	—	—,
32.	IS : 8886 (भाग 5)—1980 जलयान की साधारण आयताकार खिड़कियों की विशिष्टि भाग 5 भीतर खुलने वाली बगल से कब्जे जड़ी ढांचे के फ्रेम भारी प्रकार की काबलेदार खिड़कियों के ब्यौरे ।	—	—
33.	IS : 8886(भाग 6)—1980का जलयान साधारण आयताकार खिड़कियों की विशिष्ट भाग 6 भीतर खुलने वाली बगल से कब्जे जड़ी हलकी प्रकार की काबलेदार खिड़कियों के ढांचे के फ्रेम के ब्यौरे	—	—
34	IS : 8886 (भाग 7)—1980 जलयान साधारण आयताकार खिड़कियों की विशिष्ट भाग 6 भीतर खुलने वाली बगल से कब्जे जड़ी भारी व हल्की प्रकार की वेल्डकृत खिड़कियों के ढांचे के ब्यौरे	—	—,

(1)	(2)	(3)	(4)
35.	IS : 8886 (भाग 8)—1980 जलयान की साधारण आयताकार खिड़कियों की विशिष्टि भाग 8 अन्दर का खुलने वाली ऊपर के कब्जे जड़ी भारी प्रकार की कावलेदार खिड़कियों के ढांचे के ब्यौरे	—	—
36.	IS : 8886 (भाग 9)—1980 साधारण आयताकार खिड़कियों की विशिष्टि भाग 9 अन्दर की ओर खुलने वाली ऊपर से कब्जे जड़ी हल्की प्रकार की बोल्ट दार खिड़कियों के ढांचे के ब्यौरे	—	—
37.	IS : 8886 (भाग 10)—1980 साधारण, आयताकार खिड़कियों की विशिष्टि भाग 10 अन्दर की खुलने वाली ऊपर से कब्जे जड़ी भारी व हल्की वेल्डकृत खिड़कियों के ढांचे के ब्यौरे	—	
38	IS : 8886 (भाग 11)—1980 साधारण आयताकार खिड़कियों की विशिष्टि भाग 11 न खुलने वाली भारी प्रकार की कावलेदार खिड़कियों के ढांचे के ब्यौरे		
39.	IS : 8886 (भाग 12)—1980 साधारण, आयताकार खिड़कियों की विशिष्टि भाग 12 न खुलने वाली, हल्की प्रकार की कावलेदार खिड़कियों के ढांचे के ब्यौरे		
40.	IS : 8886 (भाग 13)—1980 साधारण आयताकार खिड़कियों की विशिष्टि भाग 13 न खुलने वाली, भारी वेल्डकृत के ढांचे के ब्यौरे		
41.	IS : 8886 (भाग 14)—1980 साधारण आयताकार खिड़कियों की विशिष्ट भाग 14 बाहर को खुलने वाली एक ओर कब्जे जड़ी भारी प्रकार की खिड़कियों के ढाचे के ब्यौरे		
42.	IS : 8886 (भाग 16)—1980 साधारण आयताकार खिड़कियों की विशिष्टि भाग 16 ढाचे का विस्तृत विवरण बाहर के खुलने वाली एक तरफ हल्की कावलेदार खिड़कियों के ढांचे के ब्यौरे		
43.	IS : 8886 (भाग 18) साधारण आयताकार खिड़कियों की विशिष्टि भाग 18 अन्दर खुलने वाली एक तरफ कब्जे जड़ी भारी व हल्की बोल्टदार खिड़कियों के कांच धारक के ब्यौरे		
44.	IS : 8886 (भाग 19)—साधारण आयताकार खिड़कियों की विशिष्टि भाग 19 बाहर को खुलने वाली एक तरफ कब्जे जड़ी भारी व हल्की कावलेदार वेल्डकृत खिड़कियों के बीच कांच धारक के ब्यौरे		
45.	IS : 8886 (भाग 20)—1980 साधारण, आयताकार खिड़कियों की विशिष्टि भाग 20 ऊपर से कब्जे जड़ी भारी व हल्की कब्जेदार व वेल्डकृत खिड़कियों के कांच धारक के ब्यौरे		
46.	IS : 8886 (भाग 22)—1980 साधारण आयताकार खिड़कियों की विशिष्टि भाग 22 स्प्रिंग कावला और पिन ढिबरी के ब्यौरे		
47.	IS : 91363—1978 कैल्शियम मिश्रित ग्रीज की विशिष्टि		

(1)	(2)	(3)	(4)
48.	IS : 9214—1979 खेतों में मृत्तिका उपयोग अभिक्रिया (के-मान) का मापांक ज्ञात करने की पद्धति		
49	IS : 9224 (भाग 2)—1979 अल्प वोल्टता फ्यूज की विशिष्टि भाग 2 औद्योगिक उपयोग के उच्च विच्छेद क्षमता वाले फ्यूजों की पूरक अपेक्षाएं	IS : 2208—1962 650 वोल्ट तक के एच आर सी कारतूस फ्यूज लिंक की विशिष्टि	
50.	IS : 9243 (भाग 2)—1979 कलाई घड़ियों की परीक्षण पद्धति भाग 2 झटका रोधी		
51.	IS : 9259—1979 मिट्टी के लिए तरल सीमा उपकरण की विशिष्टि		
52.	IS : 9328—1979 मिष्ठान्न उद्योग से संबंधित शब्दावली		
53.	IS : 9350—1980 ताप रोधी सीमेंट (ताप 950) की विशिष्टि		
54.	IS : 9365—1980 केन्द्रापसारी दाबों की विशिष्टि		
55	IS : 9381—1979 तारकोल व बिटुमनी पदार्थों की परीक्षण पद्धतियाँ : बिटुमेन का भाग भंजन अंक		
56	IS : 9384—1979 माल वाहक कंटेनरों की संभरित आंकड़ा पट्टी की विशिष्टि		
57.	IS : 9386—1979 रॉक फास्फेट की रासायनिक विश्लेषण पद्धति		
58.	IS : 9393—1979 वर्स्टेड अर्ध वर्स्टेड और ऊनी धागे बनाने की संहिता तथा छूटें		
59.	IS : 9400—1980 तकनीकी रिपोर्ट के लिए ग्रंथ सूची वर्णन पत्रक की तैयारी की मार्गदर्शिका		
60.	IS : 9405—1980 कनवेयर पट्टे के बंधों (फैस्टनरों आदि) की परीक्षण पद्धति		
61	IS : 9427—1980 विद्यायनीकारी स्तम्भों की रख रखाव के और परिचालन की रीति संहिता		
62.	IS : 9555—1980 विद्युत गुणधर्मों पर आधारित श्वेत-अभ्रक के पतर फिल्म और ब्लाक की विशिष्टि		
63.	IS : 9956—1980 शकुनुमा और हाइपरबोलीय पैराबोलाइडल नुमा शैल नींव की डिजाइन व निर्माण की रीति संहिता		

इन भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002 में और उसकी शाखाओं में भी अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, पटना व त्रिवेन्द्रम स्थित शाखा कार्यालयों में प्राप्त की जा सकती है।

[सं०सी०एम०डी०/13 : 2]

S.O. 4186.—In pursuance of sub rule (2) of Rule 3 and sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard(s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on 1980-05-31 :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standards Established	No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard	Remarks, if any
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 74—1979 Methods of sampling and test for drying oils for paints (second revision)	IS : 74—1966 Methods of sampling and test for drying oils for paints (first revision)	—

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	IS : 104—1979 Specification for ready mixed paint, brushing, zinc chrome, priming (second revision)	IS : 104—1962 Specification for ready mixed paint, brushing, zinc chrome, priming (revised)	—
3.	IS : 714—1979 Specification for cotton reinforcing tape aerospace purposes) (second revision)	IS : 714—1962 Specification for cotton reinforcing tape for aircraft (revised)	—
4.	IS : 808 (Part III)—1979 Dimensions for hotrolled steel beam, channel and angle sections : Part III Channel, MC and MCP series (second revision)	IS : 808—1964 Specification for rolled steel beam, channel and angle sections (revised)	—
5.	IS : 1064—1980 Specification for paper sizes (second revision)	IS : 1064—1961 Specification for paper sizes (revised)	—
6.	IS : 1109—1980 Specification for borax (second revision)	IS : 1109—1968 Specification for borax (first revision)	—
7.	IS : 1376—1979 Specification for cotton sewing threads for aerospace purposes (second revision)	IS : 1376—1968 Specification for cotton sewing thread for aeronautical purposes (first revision)	—
8.	IS : 1448 (P : 93) —1979 Methods of test for petroleum and its products : P : 93 Needle penetration of petroleum waxes	—	—
9.	IS : 1651—1979 Specification for stationary cells and batteries, lead-acid type (with tubular positive plates) (second revision)	IS : 1651—1970 Specification for stationary cells and batteries, lead-acid type (with tubular positive plates) (first revision)	—
10.	IS : 1852—1979 Rolling and cutting tolerances for hot-rolledsteel products (third revision)	IS : 1852—1973 Rolling and cutting tolerances for hot-rolled steel products (second revision)	—
11.	IS : 2032 (Part XXIII)—1978 Graphical symbols used in electrotechnology : Part XXIII Instruments for process measurement and control	—	—
12.	IS : 2279—1980 Specification for fine silver bar, sheet, wire, granules and token (first revision)	IS : 2279—1963 Specification for fine silver bar, sheet, wire, granules and token (LAGDI or MOHUR)	—
		IS : 5320—1969 Specification for fine silver ingot.	—
13.	IS : 2560—1979 Specification for rubber-based adhesives for tubes, non-curing (first revision)	IS : 2560—1963 Specification for rubber-base adhesives for tyres an tubes non-curing	—
14.	IS : 2562—1979 Specification for rubber-based adhesives for tyres an tubes, curing (first revision)	IS : 2562—1963 Specification for rubber-base adhesive for tyres and tubes, curing	—
15.	IS : 2717 —1979 Glossary of terms relating to vitreous enamelware and ceramic metal systems (first revision)	IS : 2717—1964 Glossary of terms used in vitreous enamelware industry	
16.	IS : 3347 (Part I/Sec. 2) 1979—Dimensions for procelain transformer bushing for use in normal and lightly by polluted atmospheres : Part I up to and including 1 kV : Section 2 Metal parts (first revision)	IS : 3347 (Part I/Sec. 2) 1967 Dimensions for porcelain transformer bushings : Part I up to 1.1 kV bushings: Section 2 Metal parts	—
17.	IS : 3347 (Part II/Sec 2)—1979 Dimensions for porcelain transformer bushing for use in normal and lightly polluted atmospheres : Part II 3.6 kV bushings : Section 2 Metal parts (first revision)	IS : 3347 (Part II/Sec 2) —1967 Dimensions for porcelain transformer bushing : Part II 3.6 kV bushings, Section 2 Metal parts	—

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	IS : 3607—1979 Specification for magnesite for chemical industry (first revision)	IS : 3607—1966 Specification for magnesite for chemical industries	—
19.	IS : 3620—1979 Specification for laterite stone block for masonry (first revision)	IS : 3620—1966 Specification for laterite stone block for masonry	—
20.	IS : 4491—1979 Specification for steel castings of high magnetic permeability (first revision)	IS : 4491—1968 Specification for steel castings of high magnetic permeability	—
21.	IS : 4651. (Part IV)—1979 Code of practice for planning and design of ports and harbours : Part IV General design considerations (first revision)	IS : 4651 (Part IV)—1969 Code of practice for planning and design of ports and harbours : Part IV Sheet pile retaining walls	—
22.	IS : 4659—1980 Specification for wire rope reel for inland vessels (first revision)	IS : 4659—1968 Specification for wire reel for inland vessels	—
23.	IS : 4738—1980 Specification for plaster of paris bandage (first revision)	IS : 4738—1968 Specification for plaster of paris bandage	—
24.	IS : 4903—1979 Guide for treatment and disposal of effluents of cane sugar industry (first revision)	IS : 4903—1968 Guide for treatment of effluents of canesugar industry	—
25.	IS : 5405—1980 Specification for sanitary napkins (first revision)	IS : 5405—1969 Specification for sanitary towels	—
26.	IS : 5733—1979 Code for production of grafts of apples (first revision)	IS : 5733—1969 Grafts of apples	—
27.	IS : 7022 (Part II)—1979 Glossary of terms relating to water, sewage and industrial effluents Part II	—	—
28.	IS : 7290—1979 Recommendations for use of polyethylene film for waterproofing of roofs (first revision)	IS :7290—1973 Recommendation for use of polyethylene film for waterproofing of roofs	—
29.	IS : 8252 (Part IV)—1980 Environmental tests for aircraft equipment : Part IV Ice formation	—	—
30.	IS : 8252 (Part XVI)—1979 Environmental tests for aircraft equipment : Part XVI Shock	—	—
31.	IS : 8886 (Part IV)—1980 Specification for ship's ordinary rectangular windows Part IV Details of position of lugs for hinges and swing bolts and securing holes on the frame	—	—
32.	IS : 8886 (Part V)—1980 Specification for ships' ordinary rectangular windows Part V Details of frame, inward opening, side hinged, heavy type bolted windows	—	—
33.	IS : 8886 (Part VI)—1980 Specification for ships' ordinary rectangular windows Part VI Details of frame, inward opening, side hinged, light type bolted windows	—	—
34.	IS : 8886 (Part VII)—1980 Specification for ships' ordinary rectangular windows: Part VII Details of frame, inward opening, side hinged heavy and light type welded windows	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)
35.	IS : 8886 (Part VIII)—1980 Specification for ships' ordinary rectangular windows: Part VIII Details of frame, inward opening, top hinged, heavy type bolted windows	—	—
36.	IS : 8886 (Part IX)—1980 Specification for ships' ordinary rectangular windows: Part IX Details of frame, inward opening, top hinged, light type bolted windows	—	—
37.	IS : 8886 (Part X)—1980 Specification for ships' ordinary rectangular windows: Part X Details of frame, inward opening, top hinged, heavy and light type welded windows	—	—
38.	IS : 8886 (Part XI)—1980 Specification for ships' ordinary rectangular windows: Part XI Details of frame, non-opening heavy type bolted windows	—	—
39.	IS : 8886 (Part XII)—1980 Specification for ships' ordinary rectangular windows: Part XII Details of frame, non-opening, light type bolted windows	—	—
40.	IS : 8886 (Part XIII)—1980 Specification for ships' ordinary rectangular windows: Part XIII Details of frame, non-opening heavy type welded windows	—	—
41.	IS : 8886 (Part XV)—1980 Specification for ships' ordinary rectangular windows: Part XV Details of frame, outward opening, side hinged, heavy type bolted windows	—	—
42.	IS : 8886 (Part XVI)—1980 Specification for ships' ordinary rectangular windows: Part XVI Details of frame, outward opening, side hinged light type bolted windows	—	—
43.	IS : 8886 (Part XVIII)—1980 Specification for ships' ordinary rectangular windows: Part XVIII Details of glass holder, inward opening, side hinged, heavy and light type bolted and welded windows	—	—
44.	IS : 8886 (Part XIX)—1980 Specification for ships' ordinary rectangular windows: Part XIX Details of glass holder, outward opening, side hinged, heavy and light type bolted and welded windows	—	—
45.	IS : 8886 (Part XX)—1980 Specification for ships' ordinary rectangular windows: Part XX Details of glass holder, top hinged, heavy and light type bolted and welded windows	—	—
46.	IS : 8886 (Part XXII)—1980 Specification for ships' ordinary rectangular windows: Part XXII Details of swing bolts and wing nuts	—	—
47.	IS : 9136—1978 Specification for calcium complex grease	—	—
48.	IS : 9214—1979 Method of determination of modulus of subgrade reaction (*k*-value)	—	—

1	2	3	4
	of soils in field		
49.	IS : 9224 (Part II)—1979 Specification for low voltage fuses : Part II Supplementary requirements for fuses with high breaking capacity for industrial application	IS : 2208—1962 Specification for HRC cartridge fuse links upto 650 V	—
50.	IS : 9243 (Part II)—1979 Methods of test for wrist watches : Part II Shock-resistant	—	—
51.	IS : 9259—1979 Specification for liquid limit apparatus for soils	—	—
52.	IS : 9328—1979 Glossary of terms relating to confectionery industry	—	—
53.	IS : 9350—1980 Specification for thermal insulating cement (type 950)	—	—
54.	IS : 9365—1980 Specification for fenitrothion granules	—	—
55.	IS : 9381—1979 Methods for testing tar and bituminous materials : Determination of fraass breaking point of bitumen	—	—
56.	IS : 9384—1979 Specification for consolidated data plate for freight containers	—	—
57.	IS : 9386—1979 Methods for chemical analysis of rock phosphate	—	—
58.	IS : 9393—1979 Code of manufacturing worsted, semiworsted and woollen yarns and tolerances	—	—
59.	IS : 9400—1980 Guide for the preparation of bibliographic description sheet for technical reports	—	—
60.	IS : 9405—1980 Method of test for conveyor belt fasteners	—	—
61.	IS : 9427—1980 Code of practice for operation and maintenance of deionizing columns	—	—
62.	IS : 9455—1980 Classification of muscovite mica blocks, thins and films based on electrical properties	—	—
63.	IS : 9456—1980 Code of practice for design and construction of conical and hyperbolic paraboloidal types of shell foundations	—	—

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also from its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13:2]

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1982

का आ० —समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या 1000712 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, 31 जनवरी 1982 से रद्द कर दिया गया है :—

अनुसूची

क्रम सं०	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
1	सी एम/एल-1000712 1981-09-30	मैसर्स रैलिस इंडिया लि०, बेलापुर यूनिट, ठाणे–बेलापुर रोड, ठाणे— बम्बई (महाराष्ट्र) (कार्यालय .. कापूरबावड़ी निकट नाम्बूर रेलवे स्टेशन)	फेनीट्रोथियान पायसनीय सान्द्र (पुन: भराई के लिए)	IS: 5281—1980 फेनीथियान पायसनीय सान्द्र की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)

[सी एम डी / 55 : 1000712]

New Delhi, 1982-10-13

S.O. 4187.—In pursuance of sub-regulation(4) of Regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No. 1000712 particulars of which are given in the schedule below has been cancelled with effect from Thirty first January, One thousand Nine Hundred and Eighty two.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. & Date	Name & Address of the licensee	Article/Process Covered by the licence cancelled	Relevant Indian Standard
1.	CM/L-1000712 81-09-30	M/s. Rallis India Ltd., Belapur Unit, Thane-Belapur Road, Thane, Bombay (Maharashtra) (Office : Koppuravuru, near Nambur R.S.)	Fenitrothion EC (Repacking)	IS : 5281—1980 Specification for Fenitrothion Emulsifiable Concentrates (First Revision)

[CMD/55 : 1000712]

नई दिल्ली, 82-10-14

फा० आ० 4188—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल—5796* जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिये गए हैं लाइसेंसधारी के अनुरोध पर 82-03-16 से रद्द कर दिया गया है।

अनुसूची

क्रम सं०	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किये गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
1.	सी एम/एल—5796* 1977-01-11	सर्वश्री अम्बरपेट 2—3/761 अम्बरपेट हैदराबाद-500013 (आंध्र प्रदेश)	निम्न प्रकार के बिस्कुट. ग्लूकोज—ऑरेंज क्रीम, मेरी, मसाला, बाउंसर साल्टेड	IS : 1011—1981 बिस्कुटों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)

*नया लाइसेंस संख्या सी एम/एल—0579665

[सी एम डी/55.0579665]
ए० पी० बनर्जी, अपर महानिदेशक

New Delhi, 82-10-14

S.O. 4188.—In pursuance of Sub-regulation (4) of Regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notified that the Licence No. CM/L-5796* particulars of which are given below has been cancelled with effect from 82-03-16 at the request of the licensee.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensee Cancelled	Relevant Indian Standards
1	2	3	4	5
1.	CM/L-5796* 1977-01-11	M/s Amber Foods, 2-3-761, Amberpet, Hyderabad-500013 (A.P.)	Biscuits of the following varieties Glucose, Orange cream, Marie, Masala and Bouncer Salted	IS : 1011-1981 Specification for biscuits (second revision)

*New licence No. CM/L-0579665

[CMD/55 : 0579665]
A.P. BANERJI, Additional Director General

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1982

फा० आ० 4189—यत: दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 16) की धारा 3 के खण्ड (घ) के अनुसरण में इन्दौर विश्वविद्यालय परिषद के सदस्यों ने डा० वाई० एन० मक्सेना, लेक्चरार, दंत चिकित्सा कालेज, इन्दौर को 29 मार्च, 1982 से डा० ए० के० दास के स्थान पर भारतीय दन्त परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की 9 फरवरी, 1978 की अधिसूचना सं० फा० आ० 533 में पुन: प्रकाशित भारत सरकार के पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय की 12 अप्रैल, 1949 की अधिसूचना संख्या 10-10/48-एम-1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 के खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचित"

शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 12 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

12.	डा० वाई० एन सक्सेना, लेक्चरार, दंत चिकित्सा कालेज, इन्दौर	इन्दौर विश्वविद्यालय	29-3-82

[संख्या वी० 12013/4/82-पी एम एच]
एम० पी० पाठक अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health)

New Delhi, the 30th November, 1981

S.O. 4189.—Whereas in pursuance of clause (a) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (Act 16 of 1948) Dr. Y. N. Saxena, Lecturer, College of Dentistry, Indore, has been elected to be a member of the Dental Council of India by the members of the Council of University of Indore in place of Dr. A.K. Dass with effect from 29-3-1982.

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 10-10/48-MI, dated the 12th April, 1949, as republished by the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. S.O. 533, dated the 9th February, 1978, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (c) of section 3", for serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"12.	Dr. Y.N. Saxena, Lecturer, College of Dentistry, Indore.	Indore University	29-3-82".

[No. V. 12013/4/82-PMS]
S.P. Pathak, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1982

का० आ० 4190.—यतः भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का 16 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या वी० 11016/-34/77-एमपी/एम०ई० (नीति) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने यह निर्देश दिया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अर्हता "एम०बी० बी० एस० (यूनिवर्सिटी आव न्यू साऊथ वेल्ज), आस्ट्रेलिया, एक मान्य चिकित्सा अर्हता होगी ;

और यतः डा० (श्रीमती) क्लारिक मैकमोहन जिनके पास उक्त अर्हता है, धर्मार्थकार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल दिल्ली राष्ट्रमण्डल महिला संघ, नई दिल्ली के साथ सम्बद्ध है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के परन्तुक के खण्ड (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

(1) 30 सितम्बर, 1983 तक की अवधि या

(2) उस अवधि को जब तक डा० (श्रीमती) क्लारिक मैकमोहन दिल्ली राष्ट्रमण्डल महिला संघ, नई दिल्ली के साथ सम्बद्ध रहती है, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डाक्टर मैडिकल प्रेक्टिस कर सकेंगी ।

[संख्या वी० 11016/8/82-एम०ई० (नीति)]
प्रकाश चन्द जैना, अवर सचिव

ORDER

New Delhi ,the 24th November, 1982

S.O. 4190.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Health No V. 11016/34/77-MPI/M.E. (Policy) dated the 16th June, 1978, the Central Government has directed that the medical qualification, M.B.B.S. (University of New South Wales) Australia, shall be recognised medical qualification for the purpose of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. (Mrs.) Claric Mac Mahon, who possesses the said qualification is for the time-being attached to the Delhi Commonwealth Women's Association, New Delhi for the purposes of charitable work.

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a period upto 30th September, 1983 or

(ii) the period during which Dr. (Mrs.) Claric Mac Mahon attached to the said Delhi Commonwealth Women's Association, New Delhi whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/8/82-M E.(Policy)]
P C. JAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1982

का० आ० 4191.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य स्थान, कलकत्ता (समूह ग और घ पद) भर्ती नियम, 1959 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता (समूह ग और घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1982 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि को प्रवृत्त होंगे ।

2. अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता (समूह ग और घ पद) भर्ती नियम, 1959 में,

(क) नियम (1) के उप-नियम (1) में शब्द और अक्षर "और समूह घ" का लोप किया जाए,

(ख) अनुसूची में समूह "घ" पदों से संबंधित क्रम संख्या और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए ।

[सं० ए० 12018/4/81-जी०]
शिवदयाल, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 1982

S.O. 4191.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group C and D posts) Recruitment Rules, 1959, namely :

1. (1) These rules may be called the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group C and D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group C and D posts) Recruitment Rules, 1959,

(a) in sub rule (1) of rule 1, the word and letter "and group D" shall be omitted;

(b) in the schedule, serial number 1 to 22 relating to group D posts and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. A. 12018/4/81-G]
SHIVDAYAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1982

का० आ० 4192—औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री मलय मित्रा को 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में सम्पूर्ण भारत के लिए औषध-निरीक्षक [राजपत्रित समूह (ख)] के रूप में 15 अक्तूबर, 1982 पूर्वाह्न से अस्थाई आधार पर नियुक्त करती है।

[सं० ए० 12025/1/81-डी० (डी एम० एस० एण्ड पी० एफ० ए०]
जी० पंचापकेशन, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 1982

S.O. 4192.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby appoints Shri Malay Mitra as Drugs Inspector (Gazetted Group 'B') in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in the Central Drugs Standards Control Organisation for whole of India, on temporary basis with effect from the forenoon of 15th October, 1982.

[No. A. 12025/1/81-D.(DMS&PFA]
G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1982

का० आ० 4193—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3256 तारीख 5-11-81 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

के० एल० एफ० से जी० जी० एस VI तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात, जिला : मेहसाना, तालुका : कडी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	आर	सेंटीयर
चडासन	232	0	05	25
	235	0	11	25
	236	0	01	20
	204	0	47	25
	306	0	05	50
	310	0	12	60
	309	0	06	90
	312	0	08	55
	313	0	09	00
	359/1	0	03	50

[सं० 12016/39/81-प्राज०)]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 24th November, 1982

S.O. 4193.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, (Department of Petroleum) S.O. 3256 dated 5-11-81 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline From KLF to GGS VI

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Chadasan	232	0	05	25
	235	0	11	25
	236	0	01	20

1	2	3	4	5
	204	0	47	25
	306	0	08	50
	310	0	12	60
	309	0	06	10
	312	0	03	55
	313	0	09	00
	359/1	0	03	50

[No. 120 6/39/31-Prod.]

का० आ० 4194.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस० डब्लू० एम० जी० से एम० टी० एफ० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० एस० डब्लू० एम० जी० से एम० टी० एफ० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात — जिला : भरूच — तालुका : हांसोट

गांव	स० नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
रोहित	55	0	03	58
	26	0	14	30
	558	0	02	86
	19	0	07	80
	18	0	04	29
	16	0	16	25

[सं० Q 12016/52/82-प्रोड०]

S.O. 4194.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SWMG to MTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Mineral pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares it intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. SWMG to Well No. MTF

State : Gujarat — District : Bharuch — Taluka : Hansot

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Rohid	55	0	03	58
	26	0	14	30
	558	0	02	86
	19	0	07	80
	18	0	04	29
	16	0	16	25

[No. Q-12016/52/82-Prod.]

का० आ० 4195.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस० डी० एल० से एस० डी० एल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है :

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० एस० डी० एल० से एस० डी० एल० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात — जिला : भरूच — तालुका : अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
पारडी-इन्द्रेस	311	0	10	40
	310	0	09	36
	309	0	07	54
	303	0	10	40
	304/ए	0	13	65
	306	0	24	70
	297	0	04	16
	143	0	39	00
	141	0	85	80

[सं० Q-12016/36/82 प्रो०]

S.O. 4195.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SDL to SDN in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Naturtl Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. SDL to SDN

State : Gujarat District : Broach Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Pardi Idris	311	0	10	40
	310	0	09	36
	309	0	07	54
	308	0	10	40
	304/A	0	13	65
	306	0	24	70
	297	0	04	16
	143	0	39	00
	141	0	85	80

[No. 0-12016/52/82-Prod.]

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1982

का० आ० 4196—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि उसकी संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में बाधन स्थल सं० एस० डी० बी० से मोटवान तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उपर्युक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 25-9-81 से समाप्त कर दिया गया है ;

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते है।

अनुसूची

एस० डी० बी० से मोटवान तक पाइप लाइन का कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	मेलवा	356	31-1-81	25-9-81

[सं० 12016/39/82/प्रोड०-II]

New Delhi, the 26th, November, 1982

S.O. 4196.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerls Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s SDB to Motwan in Ankleshwar oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 25-9-81.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquistion of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D. S. SDB to Motwan

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Telwa	356	31-1-81	25-9-81

[No. 12016/39/82-Prod- II]

का० आ० 4197.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1666 तारीख 8-3-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ज० ए० ए० से जा लोरा जी० जी० एस० I तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कडी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए० आर०	सेंटीयर
बोरीसना	519	0	22	00
	514/1	0	21	23
	515/1	0	16	65
	543	0	11	10
	545	0	01	88

[सं० 12016/66/81]
एल० एम० गोयल, निदेशक

S.O. 4197.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, (Department of Petroleum) S.O. 1666 dated 8-3-82 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acqisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying of pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from JAA to Jhalora GGS I

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Borisana	519	0	22	00
	514/1	0	21	23
	515/1	0	16	65
	543	0	11	10
	545	0	01	88

[No. 12016/66/81-Prod.]
L.M. GOYAL, Director

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1982

का. आ. 4198 —:कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14(2) के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं जो भारत के राजपत्र में 19 मई, 1979 को तारीख 1 मई, 1979 के का. आ. 1601 से का. आ. 1687 तक के द्वारा श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायालय रांची के पक्ष में प्रकाशित की गई थी, जब श्री धर्मपाल सिन्हा, अपर न्यायिक आयुक्त, रांची के पक्ष में जारी की गई समझी जाए।

[सं. 13/4/82-सी. एल.]
पी. सरकार, निदेशक

(Department of Coal)

New Delhi, the 25th November, 1982

S.O. 4198.—The notifications issued under section 14(2) of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 vide S. O. 1601 to S.O. 1687 dated 1st May, 1979, published in the Gazette of India on 19th May, 1979 in favour of Sri Chandra Shekar Singh, Additional District and Session Judge, Ranchi may now be treated to have been issued in favour of Sri Dharampal Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi.

[No. 13/4/82-CL]
P. SARKAR, Director

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर 1982

का० आ० 4199.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी को जो कानूनी प्राधिकारी का अधिकारी होते हुए पंक्ति में सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट स्थानों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग के और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
उप-महाप्रबंधक ((कार्मिक), बामर लारी एण्ड कंपनी लिमिटेड 21—नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता—700001.	कलकत्ता शहर, पश्चिमी बंगाल की नगरपालिक सीमाओं के भीतर बामर लारी एण्ड कंपनी लिमिटेड से संबंधित अथवा उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए या अधिग्रहीत किए गए स्थान (जिनके अंतर्गत वे स्थान नहीं हैं जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं)।

[फा० सं० पी-44020/33/82-विपणन]
कुलदीप सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 30th November, 1982

S.O. 4199.— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer of a statutory authority, equivalent in rank to a gazetted officer of Government, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, in respect of the premises specified in column (2) of the said table:—

TABLE

Designation of the officer	Categories of Public Premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Deputy General Manager (Personnel), Balmer Lawrie and Company Limited, 21-Notaji Subhas Road, Calcutta-700 001.	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Balmer Lawrie and Company Limited, within the municipal limits of the City of Calcutta, West Bengal, (except such of them as are under the administrative control of the other Estate Officers).

[F. No.P-44020/33/82-MKT]

KULDIP SINGH, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1982

का० आ० 4200.—इस विभाग के आदेश संख्या 52/21/68 (ई० जेड)/एफ० सी० III/वाल्यूम-4 दिनांक 7-8-74 में निम्नलिखित शुद्धि की जाएं :-

आदेश में क्रम संख्या	की जाने वाली शुद्धियां
132	कालम 2 में "श्री हीरामय नन्द" के स्थान पर "श्री हिरण्मय नन्दी" पढ़ें ।

[संख्या 52/2/82/एफ० सी०-III]

आर० के० सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th November, 1982

S.O. 4200.—In this Department's Order No. 52/21/68 (EZ)/FCIII/Vol. IV dated 7-8-74, the followig correction shall be carried out :

S. No. in the Order	Correction to be carried out
132	For the words "Shri Hiramoy Nand" in Col. 2, read "Shri Hiranmoy Nandy."

[No. 52/2/82/FCIII]

R.K. SINGH, Dy. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1982

का०आ० 4201.—केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियम) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उप धारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यातायात प्रबंधक मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट मुरगांव को उक्त बोर्ड में सदस्य नियुक्त करती है और पुनः निदेश देती है कि नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) में भारत सरकार की अधिसूचना सं० का० आ० 2969, दिनांक 10 अगस्त 1982, जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 (ii) में दिनांक 21 अगस्त 1982 को हुआ था, उसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में "केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य" शीर्षक के मद सं० 4 में "यातायात प्रबंधक मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट, मुरगांव" रहेगा ।

[फाईल सं० एल डी जी/6/82-यू एस (एल)]

थामस मेथ्यू, अवर सचिव,

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 30th November, 1982

S.O. 4201.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints the Traffic Manager, Mormugao, Port Trust, Mormugao, as a member of the said Board and further directs that the following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2969 dated the 10th August, 1982 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii) dated the 21st August, 1982, namely :—

In the said notification, under the heading "Members representing the Central Government", for the entry against item No. (4), the entry "Traffic Manager, Mormugao Port Trust, Mormugao" shall be substituted.

[File No. LDG/6/82-US(L)]

THOMAS MATHEW, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1982

का. आ. 4202.—राष्ट्रपति, मूल नियम के नियम 45 के अनुसरण में, सरकारी निवास-स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी निवास-स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) द्वितीय संशोधन नियम, 1982 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सरकारी निवास स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 में अनुपूरक नियम, 317 ख-2 के पश्चात् शीर्षक और अनुपूरक नियम 317 ख-3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

जिन अधिकारियों के अपने मकान हैं उन्हें आबंटन

अनुपूरक नियम, 317 ख-3

(1) इस नियम में :—

(क) "लगी हुई नगर पालिका" से कोई ऐसी नगर पालिका अभिप्रेत है जो किसी स्थानीय नगर पालिका से लगी हुई है ।

(ख) किसी अधिकारी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के सम्बन्ध में "मकान" से ऐसा भवन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है, जिसका उपयोग निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, और जो किसी स्थानीय नगर पालिका या किसी लगी हुई नगर-पालिका की अधिकारिता के भीतर स्थित है ।

स्पष्टीकरण :—किसी भवन का कोई भाग जिसका प्रयोग निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इस बात के होते हुए भी कि उसका कोई भाग अनिवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए मकान समझा जाएगा ;

(ग) किसी अधिकारी के सम्बन्ध में "स्थानीय नगर-पालिका" से वह नगर पालिका अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर उसका कार्यालय अवस्थित है ;

(घ) किसी अधिकारी के सम्बन्ध में "कुटुम्ब के सदस्य" से यथास्थिति पति-पत्नी या अधिकारी की उस पर आश्रित सन्तान अभिप्रेत है ;

(ङ) "नगर पालिका" के अन्तर्गत नगर निगम, नगर-पालिका समिति या बोर्ड ; टाउन एरिया समिति नोटीफाइड एरिया समिति, और छावनी बोर्ड है ।

(2) ऐसा अधिकारी जो अपने नाम से या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अपने कार्य स्थल में या लगी हुई नगर पालिका में किसी मकान का स्वामी है, उसको आबंटित सरकारी वास सुविधा के लिए उस दर पर जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए अनुज्ञप्ति शुल्क का संदाय करने पर सरकारी निवास के आबंटन का पात्र होगा ।

(3) जहां किसी अधिकारी को सरकारी निवास स्थान का आबंटन हो चुकने के पश्चात् वह स्वयं या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य उसके कार्य स्थल में या लगी हुई नगर पालिका में मकान का स्वामी बन जाता है वहां ऐसा अधिकारी, मकान को भाड़े पर देने या अधिभोग में लेने या उसके पूरा होने की तारीख से, जो भी पूर्वतर हो, एक मास की अवधि के भीतर, सम्पदा निदेशक को अधिसूचित करेगा ।"

[फा. सं. 12033 (6)/75-नी. 2]

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

(Directorate of Estates)

New Delhi, the 22nd November, 1982

S.O. 4202.—In pursuance of rule 45 of the Fundamental Rules the President hereby makes the following rules further to amend the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Allotment of Government Residences (Genral Pool in Delhi) Second Amendment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, after Supplementrary Rule 317-B-2, for the heading and Supplementary Rule 317-B-3, the following shall be substituted namely :—

"Allotment to house owning officers"

Supplementary Rule 317-B-3:

(1) In this rule :—

(a) "adjoining municiality" means any municipality Contiguous to a local municipality;

(b) 'house" in relation to an officer or member of his family means a building or part there of used for residential purposes and situated within the jurisdiction of a local municipality or of any adjoining municipality.

Explanation :—A building, part of which is used for residential purposes, shall be deemed to be a house for the purposes of this clause notwithstanding that any part of it is used for non-residential purpose;

(c) "local municipality" in relation to an officer means the municipality within whose jurisdiction his office is located;

(d) "member of family" in relation to an officer means the wife or husband, as the case may be, or a dependent child of the officer;

(e) "municipality" includes municipal corporation a municipal committee or board, a town area committee, a notified area committee, and a cantonment board.

(2) An officer owning a house either in his own name or in the name of any member of his family at the place of his duty or in an adjoining municipality shall be eligible for allotment of Government residence on payment of licence fee for the Government accommodation allotted to him at such rate as may be determined from time to time by the Government.

(3) When after a Government residence has been allotted to an officer, he or any member of his family becomes owner of a house at the place of his duty or in an adjoining municipality, such officer shall notify the fact to the Director of Estates within a period of one month from the date the house is let out or occupied, or the date of completion, whichever is earlier."

[File No. 12033(6)/75-Pol. II (Vol. II]

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1982

का० आ० 4203—केन्द्रीय सरकार सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर

उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सौंपे गए अधिकारों की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
कार्यपालक इंजिनियर गंगटोक सेंट्रल डिविजन गंगटोक	गंगटोक की सीमाओं के भीतर केन्द्रीय सरकार के या उसके द्वारा और उनकी ओर से पट्टे पर लिए गए स्थान ।

[एफ सं० 21012/2/82-नि० IV]
आर० एस० सूद, उपनिदेशक संपदा

(Directorate of Estates)

New Delhi, the 24th November, 1982

S.O. 4203.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the table below, being a gazetted officer of Government to be Estate Officer for the purposes of the said Act and the said officer, shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said act with in the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
Executive Engineer, Gangtok Central Division Gangtok.	Premises belonging to or taken on lease by or on behalf of Central Government within the limits of Gangtok.

[F. No. 21012/2/82-Pol IV]
R.S. SOOD, Dy. Director of Estates

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982

का० आ० 4204.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने मनिमला टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-12-82 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-10/82-पी० एण्ड० बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 4204.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16-12-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Manimala Telephone Exchange, Kerala Circle.

[No. 5-10/82-PHB]

का० आ० 4205.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 6-12-82 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक तार महानिदेशक ने यरागटंला टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-12-82 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-6/81-पी एण्ड० बी०]

S.O. 4205.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16-12-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Yerraguntla Telephone Exchange, A.P. Circle.

[No. 5-6/81-PHB]

का० आ० 4206.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने सुरण्य टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-12-82 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-4/82-पी० एण्ड० बी०]
आर० सी० कटारिया, सहायक महानिदेशक

S.O. 4206.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16-12-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Sirandai Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle

[No. 5-4/82-PHB]
R. C. KATARIA, Asstt. Director General

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1982

का० आ० 4207.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 की 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, तमिलनाडु राज्य के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव (पुनर्वास) और उप सचिव (पुनर्वास), जैसा भी मामला हो, को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त, तमिलनाडु राज्य में निष्क्रान्त सम्पत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए, अतिरिक्त अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में नियुक्त करती है ।

2. इससे दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना सं० 27-(2)/73-एम० एस० II का अधिक्रमण किया जाता है ।

[सं० 1(19)/वि०से०/82-एस० एस० II(क)]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O. 4207.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government appoints Joint Secretary (Rehabilitation and Deputy Secretary (Rehabilitation), as the case may be, in the Revenue Department, Government of Tamil Nadu as Additional Custodian of Evacuee Property, in addition to his own duties for the purpose of discharging the duties imposed on the Custodian by or under the said Act in respect of evacuee properties in the State of Tamil Nadu.

2. This supersedes Notification No. 27(2)/73-SS. II, dated the 24th December, 1977.

[No. 1(19)/Spl. Cell./82-SS. II (a)]

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1982

का० आ० 4208.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, गुजरात सरकार के राजस्व विभाग के उप सचिव (पुनर्वास) को, उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त का सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए, उनके अपने कार्य-भार के अतिरिक्त, तत्काल प्रभाव से गुजरात राज्य में उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है ।

2 इसके दिनांक 8-1-1982 अधिसूचना सं (1) (3) विशेष सैल/79-एस० एस० II (क) का अधिक्रमण किया जाता है ।

[सं० 1(21)/विशेष सैल/82-एस० एस० II(क)]

New Delhi, the 22nd November, 1982

S.O. 4208.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints the Deputy Secretary (Rehabilitation), Government of Gujarat, Revenue Department, as Deputy Chief Settlement Commissioner in the State of Gujarat for the purpose of performing, in addition to his own duties, the functions assigned to a Deputy Chief Settlement Commissioner by or under the said Act, with immediate effect.

2. This supersedes Notification No. 1(3)/Spl. Cell/79-SS. II(A) dated 8-1-1982.

[No. 1(21)/Spl. Cell/82-SS. II(A)]

का० आ० 4209.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा, गुजरात सरकार, राजस्व विभाग के उप-सचिव (पुनर्वास) को तत्काल प्रभाव से उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन उप महानिरीक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए, उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है ।

2. इससे दिनांक 8-1-1982 की अधिसूचना सं० 1(3)/विशेष सैल/79-एस० एस० II(ङ) का अधिक्रमण किया जाता है ।

[सं० 1(21)/विशेष सैल/82-एस० एस० II(ङ)]

S.O. 4209.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (XXXI of 1950), the Central Government hereby appoints the Deputy Secretary (Rehabilitation), Government of Gujarat, Revenue Department, as Deputy Custodian General for the purpose of discharging the duties imposed on such Deputy Custodian General by or under the said Act, with immediate effect.

2. This supersedes Notification No. 1(3)/Spl. Cell/79-SS. II.(E) dated the 8th January, 1982.

[No 1(21)/Spl. Cell/82-SS. II(E)]

का० आ० 4210—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा, गुजरात राज्य सरकार के राजस्व विभाग में अवर सचिव (पुनर्वास) को गुजरात राज्य के लिए उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन अतिरिक्त महाभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए, तत्काल, प्रभाव से अतिरिक्त महाभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति, के रूप में नियुक्त करती है ।

2. इससे दिनांक 17 जुलाई, 1979 की अधिसूचना सं० 1(3) वि० सै०/79-एस० एस० II का अधिक्रमण किया जाता है ।

[सं० 1(21)/वि० सै० /82-एस०एस० II(छ)]
महेन्द्र कुमार बंसल, अवर सचिव

S.O. 4210.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (XXXI of 1950), the Central Government hereby appoints for the State of Gujarat the Under Secretary (Rehabilitation) In the Revenue Department of the State Government of Gujarat as Additional Custodian of Evacuee Property for the purpose of discharging the duties imposed on such Additional Custodian by or under the said Act with immediate effect.

2. This supersedes Notification No. 1(3)/Spl Cell/79-SS. II. dated the 17th July, 1979.

[No 1(21)/Spl. Cell/82-SS. II(G)]
M. K KANSAL, Under Secy.

(Department of Labour)

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 4211.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby pubilshes the following award of the Central Government industrial Tribunal Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th November, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 28 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta

AND

Their Workmen

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh, Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Shri D. K. Mukherjee, Industrial Relations Officer.

On behalf of Workmen—Shri Satyen Das, Secretary of the Union.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Coal Mines

AWARD

The following dispute was sent to this Tribunal for adjudication by the Government of India, Ministry of Labour vide Order No. L-32011/6/81-D.IV(A) dated 23rd June, 1981

"Whether the management in relation to Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in allowing Sarvashri Bankim Sarkar, Anil Mukherjee, Anil Kumar Debnath Sudhir Mandal, Santi Ranjan Bapari and others employed as L.R. Fireman-II under the Engineer Superintendent in October 1977 to supersede Sarvashri Monoranjan Bera, Ranajit Bag, Jausen Seal, Anil Kumar Sarma, Purna Chandra Koley and others employed as LR Fireman-II in September, 1977. If not, to what relief are the concerned workmen entitled?"

2. The dispute relates to a claim of inter se seniority between two groups of workmen of CPT—one group claiming seniority over the other in the Engineer Superintendent's

Section of the Marine Department. Forty-four leave reserve posts of Fireman II under the Engineer Superintendent in the Marine Department were filled by persons from two sources, (i) 14 by promotion from existing permanent Bhandaris and (ii) 30 by direct recruitment from the ex-CPT (briefly, the Board) lascars. These ex-CPT lascars were not workmen of the Board but their names were maintained in a list by the Director of the Marine department for the purpose of filling casual vacancies in the post of lascars. The ex-CPT lascars Monoranjan Bera and 29 others joined the post of Fireman II (L/R) on 19-9-77. The permanent Bhandaries Bankim Chandra Sarkar and 13 others could not be released from their parent section due to the fear in the dis-location of work in several operational points and they could join only in October 1977 under the Engineer Superintendent in the Marine Department.

3. The Union argues that the seniority of an employee is counted from the date of appointment in a particular rank or grade as per seniority Rules of the CPT (vide Ext. M. 12 dated 2nd June, 1958) but the management has made a departure from this rule. Reference is made to rule (i) of the Seniority Rules which provide "The Seniority of a man in a grade should be determined on the basis of total length of his service in that grade or in an equivalent grade". In my opinion, the argument of the Union is misconceived. A Selection Committee consisting of M. P. S. Sodhi, Assistant Engineer Superintendent, P.R. Bhawmik, Junior Marine Engineer and S. K. Mukherjee Personnel Officer was admittedly constituted in the year 1977. They admittedly interviewed the candidates in September of that year, namely, the Bhandaries and the ex-CPT lascars. The Committee adjudge the merit of the candidates and it was in the order of merit that the position of the 44 selected candidates (14 Bhandaries and 30 ex-CPT lascers) were fixed. Their inter se seniority, therefore, was determined in accordance with the place obtained by them in the interview irrespective of time taken by them in joining the post. The management has in their written statement, paragraph 8, mentioned the seniority position of the 44 selected candidates. There is no conflict between the seniority rules and the merit list prepared by the Selection Committee. The seniority rules do not provide for a situation when the recruitment is made from two sources, that is, by promotion from existing staff and by direct recruitment from outside. Even the Das Gupta Tribunal Award of 1958 in Reference No. 1 of 1956 does not provide for such a situation.

4. Mr. Mukherjee, appearing for the management, is right in contending that the seniority of the slected candidates in the instant case for the post of L/R Fireman II was determined on the basis of their performance in the selection interview and that the same is not open to challenge. The management has examined S. K. Asthana, Assistant Engineer Superintendent, to say that the Selection Committee considered the inter se seniority and formulated seniority. In my opinion, his evidence is reliable and it is supported by materials on record. The management has filed several documents showing the terms of settlement between the parties, issue of circulars and letters in connection with the appointment in the post of L|R Fireman II. I think that it is not necessary to discuss them because of the view expressed above. I am of definite opinion that the seniority in the present case is to be determined according to the merit list prepared by the Selection Committee.

5. Before I conclude this case I would like to mention that the seniority list prepared by the Engineer Superintendent in accordance with the merit list of the Selection Committee was placed on the Notice Board on 8th December, 1977 for information of all concerned, but no objection was received from any quarter. This also goes to indicate that the list became final not to be challenged later.

6. In the result, my award is that the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in employing Bankim Sarkar and 13 others (the Bhandaries) as L|R Foreman II under the Engineer Superintendent in October, 1977 and in allowing them to supersede Monoranjan Bera and 29 others ex-CPT lascars as L/R Fireman II. The concerned workmen, therefore, are not entitled to any relief.

Dated, Calcutta,

The 16th November, 1982

M. P. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-32011/6/81/D-IV(A)]

S.O. 4212.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th November, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 8 of 1981

PARTIES:

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta.

AND

Their Workmen

PRESENT:

Mr. Justice M. P. Singh—Presiding Officer

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Mr. D. K. Mukherjee, Industrial Relations Officer.

On behalf of Workmen—Mr. R. N. Chandra, Assistant General Secretary with Mr. Paresh Bose, Assistant Secretary of the Union.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Port & Dock.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by their Order No. L-32012/13/80-D. IV(A) dated 17th February, 1981 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

> "Whether the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in ignoring the claim of Shri Shyam Charan Mitra, Tracer, for promotion to the post of Junior Draftsman in the River Training Wing? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The reference must be answered in affirmative and so the concerned workman is not entitled to any relief. No employee has a right to be promoted. Promotion is a management's function. Mr. Shyam Charan Mitra could not claim to be promoted as a matter of right to the post of Junior Draftsman in the River Training Wing. His whole case is that the management acted illegally in bringing D.P. Bhattacharya from some other unit and to promote him to the post of Junior Draftsman in the River Training Wing (unit) in the year 1979 ignoring his claim. The workman submitted that the post of Junior Draftsman in the River Training Wing fell vacant in 1979, that it was to be filled up by promotion of a senior and suitable workman from the establishment of the River Training Wing and Mr. Mitra being the seniormost tracer in that wing was eligible for promotion to that post. The workmen say that Mr. Mitra applied for that post several times but his claim was wrongfully ignored by the management and that the management illegally brought another tracer D. P. Bhattacharya from a separate unit by transfer only to defeat the right of Mr. Mitra and promoted him to the post which is an imposition on the workmen of the River Training Wing and to blur their future and certain their rights to promotion to the higher post in their own heirarchy. Sri R. N. Chandra, Assistant General Secretary of the Union has vehemently contended that no employee of the CPT could be transferred from one department to another department in the same cadre and this is a rule existing for 112 years. Mr. Mukherjee for the management submits that there is no such rule.

3. In my opinion the contention of Sri R. N. Chandra is incorrect and misplaced. It is not a case of promotion of D. P. Bhattacharya in supersession of the claim of Mr.

Mitra. Mr. D. P. Bhattacharya was already a Junior Draftsman from before. He was initially appointed as a tracer in the Marine Department of CPT on 18th April, 1962. He joined the Hydraulic Study Department as a tracer with effect from 8th April, 1965. On 5th August 1968 he joined the Project as a tracer and was placed under the Junior Executive Engineer, Krishnanagar that is under the Deputy Chief Engineer of the River Wing. It may be mentioned here that in 1968 when Farakka Barrage Project was nearing completion, a River Improvement Project, namely, 'The Hooghly and the Bhagirathi Improvement Project', hereinafter referred to as "the Project", was undertaken by the Board for improvement of the River Bhagirathi-Hooghly from the Ganga off take to the sea. The Chief Hydraulic Engineer was made overall incharge of the Project apart from being the overall incharge of the Hydraulic Study Department. Two schemes were taken up under the Project—(i) Corrective Works and River Training Works in the river Bhagirathi-Hooghly and (ii) Corrective Works and River Training Works in the Estuary below Diamond Harbour. For execution of the work of the Project four temporary posts of Junior Draftsman and six temporary posts of tracers were created in same year 1968. Mr. D. P. Bhattacharya was promoted to the post of Junior Draftsman in the Project with effect from 1st September, 1975. I have already said that he was a tracer in that very Project from 5th August, 1968. He worked in Calcutta as a Junior Draftsman having been promoted in 1975 under the Engineer on Spot Duty at the Project establishment a 20, Garden Reach Road, Calcutta. Thus it is clear that Mr. Bhattacharya was working in the Project right from the year 1968 and while posted there was promoted to the post of Junior Draftsman in the Project in the year 1975. At that time he was, therefore, a staff of the Project and not of the Hydraulic Study Department. It appears that the Depuy Chief Engineer, River Training i.e., one of the principal officers of the Project, proposed to fill up a post of Junior Draftsman in the Project, which was originally created under Board's Resolution No. 1140 dated 30th July, 1968 and for that purpose he sent a letter bearing No. RT|XII|E|2|2001 dated 22nd January, 1979. Since the total work load of the Project was not adequate for the existing four Junior Draftsman, it was felt that instead of filling up another post, it would be desirable to redistribute and reallocate the work of these personnel to achieve efficiency and economy. With this object in view Shri D. P. Bhattacharya, Junior Draftsman of the Project was proposed to be placed under the Deputy Chief Engineer, River Training with effect from 15th February, 1979 under an Office Order bearing No. HSD/64/11/321 dated 7th February, 1979. Ultimately, however, Sri Bhattacharyay could not be placed under the Deputy Chief Engineer, River Training. He remains in the same office, where he was sitting since 1st September, 1975. His duties included the work in connection with Civil and Structural Drawings forwarded by the Deputy Chief Engineer, River Training. The Union opposed the arrangement of redistribution of reallocation of the work of Draftsman of the Project which had been mentioned in the office order dated 7th February, 1979 on the impression that D. P. Bhattacharyay was the staff of the Hydraulic Study department and not of the Project. This impression of the Union was wrong and certainly a misplaced one. In fact Mr. Bhattacharyay was working continuously in the Project since 5th August, 1968 against the post created by the management under Resolution dated 30th July, 1968. It is the right of the management, I think, to redistribute and reallocate the work and its staff under the Project for the purpose of achieving efficiency and economy. Mr. Bhattacharyay became Junior Draftsman in 1975. Mr. Mitra who has made a grievance in the present case joined the Project as a tracer with effect from 12th April, 1976 on his transfer from Haldia Dock Project. The post which he joined had also been created in the same resolution dated 30th July, 1968. So there is no question of ignoring his claim. Even if it be, he can have no grievance in the circumstances stated above. There is no malice, no malafide, no victimisation on the part of the management in promoting Mr. Bhattacharyay to the post of Junior Draftsman. Mr. Mitra was even in existence as a tracer in the River Training Wing when Mr. Bhattacharyay was promoted as Junior Draftsman in the year 1975. Furthermore, it will appear from the written statement of the workman himself that the River Training Wing is not a separate department. In paragraph 1 of their written statement the workman stated that Hydrulic Study Department is one of the department of the CPT and that the River Training Wing is a section of the Hydraulic Study department in which the disputant workman Shyam Charan Mitra is employed. It is thus clear that River Training Wing is not a department separate from Hydraulic Study department as has been argued by the workmen before this Tribunal. My concluded opinion is that the workman has no case.

4. For the reasons given above, my award is that the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in ignoring the claim of Sri Shyam Charan Mitra, Tracer for promotion to the post of Junior Draftsman in the River Training Wing. It follows that the concerned workman is not entitled to any relief.

Dated :
Calcutta 11-11-82.

M.P. SINGH, Presiding Officer
[No. L-32012/13/80/D-IV (A)]
T.B. SITARAMAN, Desk Officer

New Delhi, the 21st November, 1982

S.O. 4213.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Nichitpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sijua, District Dhanbad and their workmen.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 44 of 1982

Dhanbad, the 3rd November, 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Nichitpur Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Sijua, Dist. Dhanbad.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri G. Prasad, Advocate.

For the Workmen—None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

The present reference arises out of Order No. L-20012(3)/82-D.III(A), dated, New Delhi, the 30th April/3rd May, 1982 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :

"Whether the demand of the workman of Nichitpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sijua, District Dhanbad for reinstatement of Shri Jagarnath Mahato, Timber Mazdoor is justified ? If so, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement dated 15-9-1982 has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly. The meforandum of settlement shall form part of the award.

Reference No. 44 of 1982

3. Let a copy of the award be sent to the Ministry as required under Sec. 15 of the Industrial Disputes Act 1947.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II, DHANBAD

Reference No. 44 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Nichitpur Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen represented by RCMS.

The parties as mentioned above beg to submit as hereunder :—

That, the parties have agreed to settle the matter pending before the Tribunal in the matter of reference mentioned above on the following terms and conditions :—

(A) That, Shri Jagarnath Mahato, the concerned workman, who was suffering from eye cataract, has been operated upon and his visibility has been restored.

(B) That, it is agreed that the concerned workman will be taken back into employment in case he is found medically fit.

(C) That, the concerned workman shall be offered employment on a job suited to his physical fitness.

(D) That, the concerned workman shall not be entitled to any wages or monetary relief by way of compensation or otherwise for the period of his idleness.

(E) That, in case the concerned workman is still not found fit to work in a Colliery by the Medical Board, the son of Shri Jagarnath Mahato shall be offered employment as a special case to work as miner, subject to his medical fitness by the Board.

(F) That, the terms of settlement mentioned hereinabove shall be implemented as early as possible but not later than 45 days from the date.

(G) That, the settlement mentioned hereinabove shall not be cited as precedent since this has been agreed to as a special case on compassionate ground.

(H) That, the terms of the settlement mentioned hereinabove are agreeable to both the parties and hence it is Prayed that an Award can be passed in terms of the settlement mentioned hereinabove.

That, for act of this kindness, the above parties shall ever pray.

(P. R. Sinha)
General Manager.
(D. B. Pandey)
Personnel Manager.

Secretary R.C.M.S.
L.T.I. of Sri Jagarnath Mahato.
Workman concerned

Witnesses :

1. Mahadev Singh
2. Shrikant Chobey.

L.T.I. of Sri Triloki Mahato.

Part of the Award

[No. L-20012/3/82-D.III(A)]

श्रम विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1982

का० आ० 4214.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में राजस्थान स्टेट मिनरल डवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है :

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० बरोट होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या अनुलग्नक में दिए हुए 23 कर्मचारियों से तथाकथित सीमाधिक भुगतान को वापस लेने के सम्बन्ध में श्री एन० एन० टंखा, चीफ आफ पर्सनल एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान स्टेट मिनरल डवलमेंट कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर द्वारा जारी किया गया आदेश संख्या एम. एम. एडी/यूनियन/जी एफ पी जे/ 5/76/2140 दिनांक 2 मार्च, 1981 कानूनी रूप से न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कामगार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

(1) श्री ओ० पी० दत्त
(2) श्री जाय जोसेफ
(3) श्री रशीद खान
(4) श्री राधाकिशन शर्मा
(5) श्री मदन सिंह
(6) श्री बी० एस० कमल
(7) श्री रान सिंह
(8) श्री पेमा राम
(9) श्री हुदा राम
(10) श्री हुकमा राम
(11) श्री होशियारा
(12) श्री पन्ना राम
(13) श्री बद्री नारायण
(14) श्री मोटा राम
(15) श्री शंकला राम
(16) श्री खेमा राम
(17) श्री पटा राम
(18) श्री नारायण/बाग्ताजी
(19) श्री नारायण रामाजी
(20) श्री गणेश राम
(21) श्री सतीश कुमार दुबे
(22) श्री मागो राम
(23) श्री पूसा राम

[एल-29011/27/82-डी 3 बी]

(Department of Labour)

ORDER

New Delhi, the 23rd Nivember, 1982

S.O. 4214.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employees in relation to the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the office order No. MMAD/Union/GFPJ/5/76/2140 dated the 2nd March, 1981 issued by Shri N. N. Tankha Chief of personnel and Administration, Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited Jaipur ordering to recover the

alleged excess payment made to 23 employees mentioned in annexure A is legal, proper and justified? If not, to what relief is the workmen entitled?"

ANNEXURE

Sl. No.	Name of the employee
1.	Shri O. P. Tank
2.	Shri Joy Joseph
3.	Shri Rashid Khan
4.	Shri Radhakishna Sharma
5.	Shri Madan Singh
6.	Shri B. S. Kamal
7.	Shri Ran Singh
8.	Shri Pema Ram
9.	Shri Hoota Ram
10.	Shri Hukka Ram
11.	Shri Hogia
12.	Shri Padma Ram
13.	Shri Badri Narauan
14.	Shri Meeta Ram
15.	Shri Shankla Ram
16.	Shri Khema Ram
17.	Shri Pata Ram
18.	Shri Narayan/Vagtaji
19.	Shri Narayan/Ramaji
20.	Shri Ganehsa Ram.
21.	Shri Satish Kumar Dave
22.	Shri Maga Ram
23.	Shri Puna Ram.

[No. L-29011/27/81-D.III(B)]

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 4215.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputts Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Limestone Quarry of Sone Valley Port Land Cement Company Limited and their workmen, which was received by this Ministry on 24th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 32 of 1977

PARTIES:

Employers in relation to the management of the Limestone Quarry of Sone Valley Port Land Cement Company Limited, Post Office Baulia, District Rohtas.

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.), Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers—Shri N. C. Ganguly, Advocate.

For the Baulia Quarry Rashtriya Mazdoor Sewa Sangh—Shri Sati Shankar Sharma, Vice-President.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Limestone.

Dhanbad, the 18th November, 1982

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-29011/57/74-LRIV, dated, the 13th January, 1975, passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order which runs as fillows:

"Whether the following demands of the workmen of the Limestone Quarry of the Sone Valley Portland Cement Company Limited, Post Office Baulia, District Rohtas are justified? If so, to what relief and from what date are the workmen entitled?

Demands

(a) Workmen who have put in six months or more of continuous service be made permanent.

(b) Re-designation and grading of the workmen according to the nature of work performed.

(c) Payment of bonus under the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965) for the years 1968, 1969, 1970 and 1973".

2. The above dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement arrived at on 17th December, 1977 had been filed in this Court jointly signed by the General Manager and the Quarry Superintendent on behalf of the management and the General Secretary and Vice President on behalf of the sponsoring union, Baulia Quarries Mazdoor Sangh. This settlement was, however, initially objected to by the intervener union, the Baulia Quarry Rashtriya Mazdoor Sewa Sangh. But subsequently a petition dated 25th June, 1982 had been filed on behalf of the management alongwith a petition signed by the President of the intervener union, the Bauha Quarry Rashtriya Mazdoor Sewa Sangh which has also subsequently been signed by its Vice-President, to the effect that the dispute has been amicably settled by the intervener union also with the management on the same terms and conditions as contained in the aforesaid settlement arrived at on 17th December, 1977 between the management and the sponsoring union, the Baulia Quarries Mazdoor Sangh, and that an award may be made in terms thereof. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable and there is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement arrived at on 17th December, 1977 between the management and the Baulia Quarries Mazdoor Sangh as well as the petition dated 26th June, 1982 of the management alongwith the petition filed on behalf of the Baulia Quarries Rashtriya Mazdoor Sewa Sangh adopting and accepting the aforesaid settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

MANROJAN PRASAD, Presiding Officer

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

Reference Case No. 32 of 1977

BETWEEN

The Management of Baulia Limestone Quarries of Messrs. Sone Valley Portland Cement Co. Ltd.,

AND

Their workmen

The humble petition on behalf of the Management.

Most respectfully sheweth:

1. That the above mentioned case is fixed for hearing on the 5th July, 1982.

That the dispute between management and Baulia quarries Rashtriya Mazdoor Seva Sangh, have amicably settled their dispute outside the court as per agreement enclosed herewith.

It is therefore prayed that the case be fixed for hearing on 22nd, June, 1982 and order may kindly be passed in presence of the parties.

And for this the petitioner shall ever pray.

For and on behalf of the management

Sd/- Illegible
Designation
25-6-82.
Personal Manager.
Part of the award.

Sd/-
Advocate
for
25-6-1982.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

Reference No. 32 of 1977

BETWEEN

The Management of Baulia Limestone Quarries of Messrs Sone Valley Portland Cement Co. Ltd.

AND

Their workmen.

The humble petition on behalf of the Baulia Quarry Rashtriya Mazdoor Seva Sangh represented by President Jaganarain Pathak.

Most respectfully sheweth :

1. That the instant reference was made at the instance of Baulia Quarry Mazdoor Sangh represented by Sri Yadubansh Singh, General Secretary.

2. That during the pendency of the said reference there was a settlement between the management of Sone Valley Portland Cement Co. Ltd., and Baulia Quarries Mazdoor Sangh on 17th December, 1977. The management has carried out the obligation under the said agreement and all the workmen have been benefited.

3. That the Baulia Quarries Rashtriya Mazdoor Seva Sangh was not a party to the reference but having come to learn that the matter has been settled, it filed an application for being impleaded as a party in order to examine the efficacy of the said settlement.

4. That this Hon'ble Tribunal was pleased to implead the said union as a party to the proceeding and it has been represented through its Vice President Shri Sati Shanker Sharma, and the question of acceptance of the settlement is pending for final decision as to whether an award should be made in accordance with the said terms.

5. That there have been some disputes with respect to contract labour in the establishment which have been satisfactorily settled between the management and the workmen represented by the Baulia Quarry Mazdoor Sangh as well as Baulia Quarry Rashtriya Mazdoor Seva Sangh.

6. That this has brought a complete industrial peace in the establishment in view of the good gesture of the management and the union wants to fully cooperate with the management to raise its production keeping in view its financial condition and its ability to shoulder additional burden.

7. That in view of cordial relationship and keeping in view the interest of the management as well as the workmen, the petitioner union accepts the agreement made with Baulia Quarry Mazdoor Sangh on 17th December, 1977 as acceptable to it as well. It does not want to raise objection to its being adopted as an award of the Court, there being no dispute between the parties.

8. That the petitioner, therefore, joined hands with the other union of the establishment, namely, Baulia Quarry Mazdoor Sangh, by petition dated 6th March, 1978 by which petition the agreement made was filed before this Hon'ble Tribunal.

It is therefore, prayed that your Lordship may be pleased to let an award be made in terms of the agreement dated 17th December, 1977 or your lordship may pass such other order or orders as to your Lordship may appear fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.
Sd/- Sati Shanker Sharma
Up-Sabhapati, 18-11-82
Baulia Quarries Rashtriya
Mazdoor Seva Sangh.

Memorandum of settlement arrived at between the Management of Sone Valley Portland Cement Company Limited, Baulia Quarries, Baulia and their workmen represented by Baulia Quarries Mazdoor Sangh on Saturday, the 17th December, 1977 at Japla Cement Factory.

Representing Employer

1. Shri P. C. Jain,
General Manager.

2. Shri R. K. Agarwal,
Quarry Superintendent.

Representing Workmen

Shri Jadubans Singh,
General Secretary,
Baulia Quarries Mazdoor Sangh.

Shri Suraj Singh,
Vice President,
Baulia Quarries Mazdoor Sangh.

SHORT RECITAL OF THE CASE

Whereas Baulia Quarries Mazdoor Sangh submitted a charter of demands vide their letter dated 1st October, 1974.

And whereas the Government of India, vide its order No. I-29011/57/74/LRIV dated 17th April, 1975 referred the above demands of the Union for an adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947 and the same is pending adjudication before the Presiding Officer, Central Government, Industrial Tribunal No. 1 at Dhanbad and the disputes has been numbered as Ref. No. 3 of 1975 (Old)/No. 32 of 1977 (New).

And whereas in the interest of maintaining peace, harmony and amity between the Management and the workmen represented by Baulia Quarries Mazdoor Sangh it is expedient to settle the dispute amicably by mutual negotiations out of Court on the terms and conditions as mentioned below:—

(1) It has been agreed to give one ad-hoc increment to such employees only who have already reached the maximum of their grades w.e.f. 1st January, 1978.

(2) The grades and fitment of the employees were duly reviewed and it has been agreed to revise the grades and fitment in the manner as per list attached which is marked as Annexure-I. This will be w.e.f. 1st January, 1978.

(3) Though the Company is not in a position to bear the additional burden, but in the interest of long-term peace and better production, harmony and co-operation, it has been agreed to take 200 persons on permanent roll w.e.f. 1st January, 1978. The list of such persons is attached and marked as Annexure-II.

(4) It has been agreed to pay minimum bonus of 4 per cent only for the years 1968, 1969, 1970 and 1973 in the manner as stated below :

The bonus for the above years will be paid in a phased manner i.e. during every quarter of 1978, one year's minimum bonus will be paid in three instalments.

(5) It has been further agreed to file this settlement before the Industrial Tribunal with a request to dispose off the Reference on the above disputes as per terms of this settlement and incorporate the same in the award.

(6) This agreement will hold good subject to the Award.

Representing Employer.

(1) Sd/- P. C. Jain,
General Manager.
(2) Sd/- R. K. Agarwal
Quarry Superintendent

Representing Workmen :
Sd/- Jadubansh Singh, 17-12-1977,
General Secretary,
Baulia Quarries Mazdoor Sangh.
Sd/- Suraj Singh,
Vice-President,
Baulia Quarries Mazdoor Sangh.

WITNESSES :

(1) Khan Gul Khan

(2) T. P. Sinha.

Part of the Award

ANNE

SONE VALLEY PORTLAND CEMENT LTD.,

Statement showing Re-designation

PRESENT

E. No.	Name	Designation	Grade	Rate of Pay					
				Basic	D.A.	A.D.A.	P.A.	H.A.	Total
Staff	Sri Gopal Ram	Mech. Foreman	VII	299.78	96.00	29.98	—	19 50	445.26
Staff	Sri Anjani Kumar	Foreman	VI	353.78	96.00	35.38	—	18.20	503.36
Staff	Sri B.D. Agrawal	Sr. Asstt. Acctt.	VI	434.33	96.00	43.43	—	18.20	591.96
Staff	Sri R.N. Tiwary	Asstt. Acctt./PFC	V	328.05	96.00	32.81	—	18.20	475.06
Staff	Sri P.N. Chakarbarty	Clerk/Asstt. Cashier	I	156.65	96.00	15.67	—	13.00	281.32
Staff	Sri P.K. Jain	Assistant	III	183.05	96.00	18.31	—	15.60	312.98
Staff	Sri B.K. Chattaraj	Clerk	III	181.51	96.00	18.15	—	15.60	311.26
Staff	Sri Baliram Mishra	,,	II	162.00	96.00	16.20	—	15.60	289.80
Staff	Sri J.K. Bhattacharji	,,	I	152.97	96.00	15.30	—	13.00	277.27
Staff	Sri Ram Hari Ram	,,	I	117.95	96.00	11.80	—	13.00	283.75
Staff	Sri Khangul Khan	,,	T.C.	114.31	96.00	11.43	—	13.00	234·74
Staff	Sri Loknath Mishra	,,	T.C.	115.00	96.00	11.50	—	13.00	235.50
Staff	Sri Rajkishre Singh	,,	T.C.	100.00	96.00	10.00	—	13.00	219.00
1691	Sri Banarsi Mishra	Munshi	C	92.56	87.50	9.26	—	13.00	202.32
1662	Sri Ram Sunder Kolh	,,	C	107.40	87.50	10.74	—	13.00	218.64
114	Sri Ram Bahadur Ram	Splicer		99.09	87.50	9.91	—	13.00	209.50
1713	Sri Sheo Kumar	Munshi	C	92.56	87.50	9.26	—	13.00	202.32
Staff	Sri S.P. Sinha	Compounder/ Storekeeper.	IV	292.05	96.00	29.21	—	15.60	432.86
W/W	Sri Setu Lall	Havildar	C	106.89 5.00 Rifle Allow. 9.00 Ration A. cont.	87.50	10.69	—	13.00	232.08
1766	Sri H.P. Shukla	Mate	C	92.56	87.50	9.26	—	13.00	202.32
214	Sri Ram Lakhan Mishra	,,	A	162.25	87.50	16.23	—	15.60	281.58
381	Sri Damodar Tiwary	,,	A	163.98	87.50	16.40	—	15.60	283.48
593	Sri Sobaram Singh	,,	A	176.98	87.50	17.70	—	15.60	297.78
667	Sri Shariff Shaikh	,,	B	132.36	87.50	13.24	—	15.60	248.70
WATCH & WARD.									
	Sri Ram Lagan Ram	Sentry	E	76.70 9.00	87.50	—	1.82	13.00	188.02
	Sri Haribansh Singh	,,	E	76.70 9.00	87.50	—	—	13.00	188.02
ELECTRIC & WATER SUPPLY									
241	Sri Ram Pd. Chaudhary	Elec. Mech. Fitter/Wireman/ Armature winder	B	158.35	87.50	15.84	—	15.60	277.29
251	Sri Nasiruddin Sk.	Fitter	C	110.78	87.50	11.08	—	13.00	222.36
242	Sri Krishna Lohar	Fitter	C	118.49	87.50	11.85	—	13.00	230.84
1695	Sri Sheo Pd. Pandey	P. Attendant/ Khalasi	D	77.00	87.50	3.85	—	13.00	181.35
1697	Sri Inam Khan	P. Attd./B.D.F. Khalasi.	D	77.00	87.50	3.85	—	13.00	181.35
MAINT. & CIVIL									
181	Sri Azimuddin Khan	Turner/Welder	B	160.08	87.50	16.01	—	15.60	279.19
169	Sri Suresh Ch. Roy	Asstt. Welder	D	91.33	87.50	4.56	—	13.00	196.39
1698	Sri Ganesh Pathak	A. Welder/Lhalasi	D	77.00	87.50	3.85	—	13.00	181.35
1706	Sri Ab. Rasid	Khalasi	E	71.28	87.50	—	—	13.00	171.78
HOSPITAL									
339	Sri Ramchandra Mester	Helper Dresser/ Sweeper	E	76.70	87.50	—	1.82	13.00	179.02
TRANSPORT									
257	Sri Keshwar Kahar	Fitter	B	156.00	87.50	15.60	—	15.60	274.70
258	Sri Ramkeshwar Nai	Fitter	B	156.00	87.50	15.60	—	15.60	274.70
1702	Sri Md. Khalil	B.D.F./Khalasi	D	77.00	87.50	3.85	—	13.00	181.35
MISC.									
1759	Sri Jitendra Pd. Sinha	Munshi	D	71.15	87.50	3.55	—	13.00	175.20

XURE. 1
LIMESTONE QUARRY, BAULIA.
and Change of Grade.

Designation	Grade	REVISED Rate of Pay Basic	D.A.	A.D.A.	P.A.	H.A.	Total	Remarks
Mech. Foreman	VII	315.00	96.00	31.50	—	19.50	462.00	
Foreman	VII	375.00	06.00	37.50		19.50	528.00	
Sr. Asstt. Acctt.	VII	455.00	96.00	45.50	—	19.50	616.00	
A.A./P.F.C.	V	343.00	96.00	34.30	—	18.20	491.50	
Clerk/Asstt. Cashier	II	162.00	96.00	16.20	15.60	—	289.80	
Stores Asstt.	III	190.00	96.00	19.00	—	15.60	320.60	
Clerk	III	190 00	96.00	19.00	—	15.60	320.60	
,,	III	166.00	96.00	16.60	—	15.60	294.20	
,,	II	155.00	96.00	15.50	—	15.60	282.10	
,,	II	119.00	96.00	11.90	—	15.60	242.50	
,,	II	119.00	96.00	11.90	-	15.60	242.50	
,,	I	117.00	96.00	11.70	—	13.00	237.70	
,,	I	102.00	96.00	10.20	—	13.00	221.20	
Typist/Clerk	I	97.00	96.00	9.70	—	13.00	215.70	
Ropeway Clerk	I	112.00	96.00	11.20	—	13.00	232.20	
Asstt. Foreman	I	102.00	96.00	10.20	—	13.00	221.20	
,,	I	97.00	96.00	9.70	—	13.00	215.70	
Compounder/Storekeeper.	V	313.00	96.00	31.30	—	18.20	458.50	
W/Ward Supervisor	I	5.00 112.00 9.00	96.00	11.20	—	13.00	246.20	
Foreman	III	200.00	96.00	20.00	—	15.60	331.60	
Mate	II	169.00	96.00	16.90	—	15.60	297.50	
Mate	II	169.00	96.00	16.90	—	15.60	297.50	
Mate	II	183.00	96.00	18.30	—	15.60	312.90	
Mate	II	137.00	96.00	13.70	—	15.60	262.30	
Asstt. Havildar.	D	78.00 9.00	87.50	3.90	—	13.00	191.40	R.A. Con.
,,	D	78.00 9.00	87.50	3.90	—	13.00	191.40	
Elec. Mech. Fitter/Wireman/ Armature Winder	A	170.30	87.50	17.03	—	15.60	290.43	
Elect. Fitter	B	117.00	87.50	11.70	—	15.60	231.80	
Fitter	C	125.32	87.50	12.53	—	13.00	238.35	
Pump Attendant	D	77.00	87.50	3.85	—	13.00	181.35	
Pump Attendant.	D	77.00	87.50	3.85	—	13.00	181.35	
Turner	B	162.50	87.50	16.25	—	15.60	281.85	
Welder	D	93.60	87.50	4.68	—	13.00	198.78	
Welder	D	80.60	87.50	4.03	—	13.00	185.13	
Mason	D	72.80	87.50	3.64	—	13.00	176.94	
Dresser	D	78.00	87.50	3.90	—	13.00	182.40	
Fitter	B	169.00	87.50	16.90	—	15.60	289.00	
Fitter	B	169.00	87.50	16.90	—	15.60	289.00	
Asstt. Fitter/Khalasi.	D	80.60	87.50	4.03	—	13.00	185.13	
Munshi	D	75.40	87.50	3.77	—	13.00	179.67	

E. No.	Name	Designation	Grade	PRESENT Rate of Pay					
				Basic	D.A.	A.D.A.	P.A.	H.A.	Total
MATES & MUNSHIS :									
442	Sri Madan Pd.		B	127.15	87.50	12.71	—	15.60	242.96
439	Sri Chandrama Singh		B	122.23	87.50	12.22	—	15.60	237.55
388	Sri Fulan Lall		C	110.79	87.50	11.08	—	13.00	222 37
601	Sri Nanhakoo Nonia		C	103.55	87.50	10.36	—	13.00	214.41
205	Sri Badri Pathak		B	127.15	87.50	12.72	—	15.60	242.97
820	Sri Bishwanath Pd.		B	127.15	87.50	12.72	—	15.60	242 97
1489	Sri Rajeshwar Lall		B	132.35	87.50	13.24	—	15.60	248.69
598	Sri Ramdeo Nonia		D	91.91	87.50	4.60	—	13.00	197.01
1213	Sri Banarashi Singh		B	142.75	87.50	14.28	—	15.60	260.13
960	Sri Jagadish Lall		B	127.15	87.50	12.72	—	15.60	242.97
754	Sri Jagarnath Pansari		E	76.70	87.50	—	1.82	13.00	179.02
C5	Sri Madan Mohan Pathak		E	61.10	87.50	—	—	13.00	161.60
BLASTERS:									
1711	Sri Mundrika Yadav	Khalasi	E	71.28	87.50	—	—	13.00	171.78
1714	Sri Chandradeo Ram	,,	E	71.28	87.50	—	—	13.00	171.78
B.C. ROPEWAY									
172	Sri Nanhai Ahir	B.D.F./Khalasi	D	93.60	87.50	4.68	0.60	13.00	199.38
409	Sri Ayodhya Kahar	,,	D	93.33	87.50	4.67	—	13.00	198.50
75	Sri Mukhdeo Ahir	,,	D	89.17	87.50	4.46	—	13.00	194.13
83	Sri Sarjoo Chaudhary	,,	D	88.22	87.50	4.41	—	13.00	193.13
1674	Kishun Mahto	Khalasi	E	71.28	87.50	—	—	13.00	171.78
1668	Sri Gulab Chand Mahto	,,	E	71.28	87.50	—	—	13.00	171.78
82	Sri Banshi Kahar	,,	E	76.70	87.50	—	—	13.00	177.20
1671	Sri Gobardhan Mahto	Munshi	D	81.16	87.50	4.06	—	13.00	185.72
M.C. ROPEWAY									
158	Sri Ramchandra Mistry	Khalasi	E	76.70	87.50	—	—	13.00	177.20
119	Sri Anirudh Pathak	Helper	E	76.70	87.50	—	1.82	13.00	179.02
1670	Sri Meghnath Mahto	Khalasi	E	71.28	87.50	—	—	13.00	171.78
1687	Sri Mundrika Ahir	,,	E	71.28	87.50	—	—	13.00	171.78
1673	Sri Kameshwar Suri	Asstt. Splicer/ B.D.F./Khalasi	D	77.00	87 50	3.85	—	13.00	181.35
113	Sri Gurudayal Ahir	Sarang/Splicer	C	99.09	87.50	9.91	—	13.00	209.50
126	Sri Karamdeo Mishra	Asstt. Operator	D	93.60	87.50	4.68	—	13.00	198.78
406	Sri Bandhoo Ahir	B.D.F./Khalasi	D	93.33	87.50	4.67	—	13.00	198.50
505	Sri Ganesh Singh	Asstt. Splicer/ B.D.F./Khalasi.	D	82.65	87.50	4.13	—	13.00	187.28
482	Sri Ram Sumer Dubey	Asstt. Opr.	D	93.33	87.50	4.67	—	13.00	198.50
477	Sri Maheshar Ahir	B.D.F./Khalasi	D	93.60	87.50	4.68	0.60	13.00	199.38
77	Sri Sri Ram Pati Ahir	,,	D	83.60	87.50	4.18	—	13.00	188.28
1749	Sri Sahdeo Singh Yadav	Khalasi	E	71.28	87.50	—	—	13.00	171.78
1685	Sri Sheonath Dusadh (Ram)	,,	E	71.28	87.50	—	—	13.00	171.78
122	Sri Mathura Dhobi	,,	E	76.70	87.50	—	—	13.00	177 20
489	Sri Ram Das Ahir	Khalasi	E	76.70	87.50	—	—	13.00	177.20
325	Sri Sukhdeo Koiri	,,	E	76.70	87.50	—	1.82	13.00	179.02
413	Sri Sarfudd in Nawa	,,	E	76.70	87.50	—	—	13.00	177.20
1747	Sri Matar Chaudhary	,,	E	71.28	87.50	—	—	13.00	171.78
1724	Sri Lachhuman Chaudhary	Munshi	D	81.16	87.50	4.06	—	13.00	185.72
DRILLERS :									
218	Sri Ram Brichh Nawa	Driller	D	93.60	87.50	4.68	0.60	13.00	199.38
1692	Sri Jitan Nonia	,,	D	83.40	87.50	4.17	..	13.00	188.07
677	Sri Guljar Sheikh	,,	D	93.60	87.50	4.68	1.48	13.00	200.26
624	Sri Kesho Koeri	,,	D	93.45	87.50	4.67	..	13.00	198.62
1728	Sri Dharmoo Ram	,,	D	83.40	87.50	4.17	..	13.00	188.07
1729	Sri Jamuna Kurmi	,,	D	83.40	87.50	4.17	..	13.00	188.07
1730	Sri Kedarnath Ram	,,	D	83.40	87.50	4.17	..	13.00	188.07
833	Sri Bandhan Kandoo	,,	D	88.94	87.50	4.45	..	13.00	193.89
962	Sri Rafique Sheikh	,,	D	93.60	87.50	5.68	1.48	13.00	200.26
1011	Sri Sita Ram Dhobi	,,	D	93.45	87.50	4.67	..	13.00	198.62
1170	Sri Dil Md. Sheikh	,,	D	93.45	87.50	4.67	..	13.00	198.62

REVISED

Designation	Grade	Rate of Pay						Remarks
		Basic	D.A.	A.D A.	P.A.	H.A.	Total	
Mate	A	143.00	87.50	14.30	—	15.60	260.40	
Mate	B	130.00	87.50	13.00	—	15.60	246.10	
Mate	B	117.00	87.50	11.70	—	15.60	231.80	
Mate	B	110.50	87.50	11.05	—	15.60	224.65	
Mate	B	130.00	87.50	13.00	—	15.60	246.10	
Mate	B	130.00	87.50	13.00	—	15.60	246.10	
Mate	B	136.50	87.50	13.65	—	15 60	253.25	
Mate	C	92.56	87.50	9.26	—	13.00	202.32	
Munshi	B	143.00	87.50	14.30	—	15.60	260.40	
Munshi	B	130 00	87.50	13.00	—	15.60	246.10	
Mate	C	83.20	87.50	8.32	—	13.00	192.02	
Mate	C	83.20	87.50	8.32	—	13.00	192.02	
Blaster	C	83.20	87.50	8.32	—	13.00	192.02	
Blaster	C	83.30	87.50	8.32	—	13.00	192.02	
H.I. Operator	C	97.24	87.50	9.72	—	13.00	207.46	
Asstt. Operator/B.D.F.	D	93.33	87.50	4.67	—	13.00	198.50	
,,	D	89.17	87.50	4.46	—	13.00	194.13	
,,	D	88.22	87.50	4.41	—	13 00	193.13	
B D.F./Khalasi	D	72.80	87.50	3.64	—	13.00	176.94	
,,	D	72.80	87.50	3.64	—	13.00	176.94	
,,	D	78.00	87.50	3.90	—	13.00	182.40	
Munshi	B	110.50	87.50	11.05	—	15.60	224.65	
Black-smith	D	78.00	87.50	3.90	—	13.00	182.40	
B Smith/H. Man/Khalasi	D	78.00	87.50	3.90	—	13.00	182.40	
,,	D	72.80	87.50	3.64	—	13.00	176.94	
,,	D	72.80	87.50	3.64	—	13.00	176.94	
Splicer/B.D.F.	C	83.20	87.50	8.32	—	13.00	192.02	
H.I. Operator/Spli.	C	101.92	87.50	10.19	—	13.00	212.61	
Hd. Operator	C	97.24	87.50	9.72	—	13.00	207.46	
H.I. Operator	C	97.24	87.50	9.72	—	13.00	207.46	
H.I. Operator	C	87.88	87.50	8.79	—	13.00	197.17	
H.I. Operator	C	97.24	87.50	9.72	—	13.00	207.46	
Hd. Operator	C	97.24	87.50	9.72	—	13.00	207.46	
Asstt. Opr/B.D.F.	D	83.60	87.50	4.18	—	13.00	188.28	
B.D.F./Khalasi	D	72.80	87.50	3.64	—	13.00	176.94	
,,	D	72.80	87.50	3.64	—	13.00	176.94	
,,	D	78 00	87.50	3.90	—	13.00	182.40	
Line Guard	E	76.70	87.50	—	—	13.00	177.20	
,,	E	76.70	87.50	—	1.82	13.00	179.02	
,,	E	76.70	87.50	—	—	13.00	177.20	
,,	E	71.28	87.50	—	—	13.00	171.78	
Munshi	B	110 50	87.50	11.05	—	15.60	224.65	
Driller	C	92.56	87.50	9.26	..	13.00	202.32	
,,	C	83.20	87.50	8.32	..	13.00	192.02	
,,	C	92 56	87.50	9.26	..	13.00	202.32	
,,	C	92.56	87.50	9.26	..	13.00	202.32	
,,	C	83.20	87.50	8.32	..	13.00	192.02	
,,	C	83.20	87.50	8.32	..	13.00	192.02	
,,	C	83.20	87.50	8.32	..	13.00	192.02	
,,	C	87.88	87 50	8.79	..	13.00	197.17	
,,	C	92 56	87.50	9.26	..	13.00	202.32	
,,	C	92.56	87 50	9.26	..	13.00	202.32	
,,	C	92.56	87.50	9.26	..	13.00	202.32	

SONE VALLEY PORTLAND CEMENT CO. LTD., LIMESTONE QUARRY.

E.No.	Name	Designation	Grade	PRESENT Rate of Pay					
				Basic	D.A.	A.D.A.	P.A.	H.A.	Total
507	Sri Sita Ram Dhobi	Driller	D	93.60	87.50	4.68	0.60	13 00	199.38
508	Sri Bechan Dhanger	,,	D	93.60	87.50	4.68	0.60	13 00	199.38
1590	Sri Atal Bihari Singh	,,	D	93.60	87.50	4.68	1.48	13.00	200.26
1472	Sri Jagoo Dhobi	,,	D	85.20	87.50	4.26	..	13 00	189.96
1650	Sri Ram Hari Dusadh	,,	D	79.01	87 50	3.95	..	13.00	183.46
1648	Sri Surajan Kurmi	,,	D	79.01	87 50	3.95	..	13.00	183.46
1613	Sri Immuddin Sheikh	,,	D	74.91	87.50	3.75	..	13 00	179.16
	HELPER DRILLERS								
635	Sri Narayan Koeri	Loader Carrier	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
798	Sri Nanhkoo Koeri	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1108	Sri Bahori Koelh	L/C	E	76 70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1114	Sri Bishwanath Dhanger	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1353	Sri Md. Hussen Khan	L/C	E	73.88	87.50	.	..	13.00	174.38
1474	Sri Ram Chandra Kahar	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1644	Sri Sobarati Bhuia	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1542	Sri Nirmal Ahir	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
989	Sri Bilash Dusadh	L/C	E	76.70	87.50	..	1 82	13.00	179.02
1222	Sri Halkani Kahar	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13 00	179.02
1250	Sri Jagan Kahar	L/C	E	76.70	87.50	..	0.52	13.00	177 72
1261	Sri Khakhan Kahar	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174 38
1264	Shri Budhan Kahar	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1268	Sri Nagdeo Kahar	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1291	Sri Aziz Shaikh	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1296	Sri Tulsh Koiri	L/C	E	76.70	87.50	..	..	13.00	177.20
1297	Sri Gugul Ahir	L/C	E	76.70	87.50	..	0.52	13.00	177.72
1308	Sri Ganesh Ahir	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1312	Sri Ram Bachan Mallah	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1330	Sri Halkani Bhuia	L/C	E	76.70	87.50	..	1 82	13.00	179.02
1338	Sri Sukhdeo Bhuia	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1342	Sri Bifan Bhuia	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1352	Sri Tapeshwari Dhobi	L/C	E	72.58	87.50	..	..	13.00	173.08
1356	Sri Ram Brichh Dhobi	L/C	E	73.88	87.50	..	.	13.00	174.38
1366	Sri Basropan Ahir	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1396	Sri Sudhoo Bhuia	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179 02
1399	Sri Ganauri Kandoo	L/C	E	76.70	87.50	....	1.82	13.00	179.02
1400	Sri Neyazuddin Shaikh	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1405	Sri Radhey Lohar	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1415	Sri Neyamuddin Shaikh	L/C	E	76.70	87.50	..	..	13.00	177.20
1427	Sri Dhanesher Chamar	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1433	Sri Budhan Kahar	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1436	Sri Ram Lakhan Koiri	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1466	Sri Ram eChandra Nonia	L/C	E	76.70	78.50	..	1.82	13.00	179.02
1489	Sri Baudh Koiri	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179 02
1475	Sri Ram Hari Kahar	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1476	Sri Bandhoo Dhanager	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1480	Sri Amirka Kahar	L/C	E	73 88	87.50	..	..	13.00	174.38
1481	Sri Sheo Nath Kahar	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1512	Sri Bhuneshwar Dubey	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1513	Sri Ram Jit Ahir	L/C	E	76.70	87 50	..	1.82	13.00	179.02
1516	Sri Dwarika Ahir	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13 00	179.02
1520	Sri Jagrup Chamar	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1529	Sri Balkesher Ahir	L/C	E	76.70	87.50	..	..	13.00	177.20
1535	Sri Ram Ashray Bhuia	L/C	E	76.70	87 50	..	.	13 00	177.20
1562	Sri Prit Singh	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179 02
1538	Sri Sarjoo Tirwari	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1568	Sri Suresh Kurmi	L/C	E	72.58	87.50	..	..	13.00	173.08
1601	Sri Gafoor Shaikh	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1625	Sri Budhoo Bhuia	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1631	Sri Kalicharan Dhanger	L/C	E	76 70	87.50	..	1.82	13.00	179.02

Designation	Grade	REVISED Rate of Pay					Remarks
		Basic	D.A.	A D.A.	P.A.	H.A.	Total
Driller	C	92.56	87.50	9.26	..	13.00	202.32
"	C	92.56	87.50	9.26	.	13.00	202.32
"	C	92.56	87.50	9.26	.	13.00	202.32
"	C	83.20	87.50	8.32	..	13.00	192.02
"	C	83.20	87 50	8.32	..	13.00	192.02
"	C	83.20	87.50	8.32	..	13.00	192.02
"	C	83.20	87.50	8.32	..	13.00	192.02
Drilling Helper. L.C.	E	76 70	87.50	.	1.82	13.00	179.02
"	E	73.88	87.50	.	..	13.00	174.38
"	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
"	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
"	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
"	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
"	E	73.88	87.50	.	..	13.00	174.38
"	E	73.88	87.50	..	.	13.00	174.38
"	E	76.70	87.50	.	1.82	13.00	179.02
"	E	76.70	87.50	..	1 82	13.00	179.02
T.M./L.C.	E	76.70	87.50	.	0 52	13.00	177.72
"	E	73.88	87.50	.	..	13.00	174.38
"	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
"	E	73.88	87.50	.	..	13.00	174 38
"	E	87.70	87 50	.	1.82	13.00	179.02
"	E	76.70	87 50	..	..	13.00	177.20
"	E	76.70	87.50	..	0.52	13.00	177.72
"	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
"	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
"	E	76 70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
"	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
"	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
"	E	72.58	87.50	..	..	13.00	173.08
"	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
"	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
"	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
"	E	76.70	87.50	.	1.82	13 00	179.02
"	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
"	E	76.70	87.50	..	1.82	13 00	179.02
"	E	76.70	87.50	..	..	13.00	177.20
"	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
"	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
"	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
"	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
"	E	76.70	87 50	..	1.82	13 00	179.02
"	E	73.88	87.50	..	..	13 00	174.38
"	E	73 88	87.50	..	.	13,00	174.38
"	E	73.88	87.50	..	.	13.00	174.38
"	E	73.88	87 50	..	..	13.00	174.38
"	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179 02
"	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179..02
"	E	76.70	87.50	..	1.82	13 00	179.02
"	E	76.70	87.50	..	1 82	13.00	179.02
"	E	76.70	87.50	..	..	13.00	177 20
"	E	76 70	87.50	..	.	13.00	177.20
"	E	76.70	87 50	..	1.82	13.00	179.02
"	E	76.70	87.50	..	..	13.00	174.38
"	E	72.58	87.50	..	..	13.00	173.08
"	E	76.70	87 50	..	1.82	13.00	179.02
"	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
"	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02

E. No.	Name	Designation	Grade	PRESENT Rate of Pay					
				Basic	D.A.	A.D.A.	P.A.	H.A.	Total
1649	Sri Ram Sunder Bhuia	L/C	E	73 88	87.50	..	..	13.00	174.38
1172	Sri Hanif Shaikh	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1173	Sri Ismail Dhobi	L/C	E	76.70	87.50	..	1 82	13 00	179.02
859	Sri Tapeshwari Chamar	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
879	Sri Dhandeo Nonia	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
994	Sri Jahir Hussain	L/C	E	76.70	87.50	..	0.52	13.00	177.72
835	Sri Ram Chandra Nonia	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1007	Sri Sita Kahar	L/C	E	76.70	87.50	..	1 82	13.00	179.02
1041	Sri Ramu Ram Kahar	L/C	E	72 58	87.50	..	..	13.00	173.08
1134	Sri Anwar Khan	L/C	E	76.70	87.50	..	..	13.00	177.20
1112	Sri Latif Shaikh	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
930	Sri Ram Adhar Dusadh	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
842	Sri Karim Shaikh	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1111	Sri Brichh Dusadh	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
684	Sri Sarjoo Dhanger	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
686	Sri Ram Deni Rajwar	L/C	E	76.70	87.50	..	1 82	13.00	179.02
565	Sri Karim Shaikh	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
629	Sri Raj Kumar Dusadh	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
692	Sri Halkan Dusadh	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
685	Sri Hamid Shaikh	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
795	Sri Modi Dusadh	L/C	E	76.70	87.50	..	..	13.00	174.38
756	Sri Ram Deni Dhanger	L/C	E	76.70	87.50	..	..	13.00	177.20
764	Sri Mangaroo Ahir	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
749	Sri Sheodayal Koiri	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
746	Sri Jangi Dusadh	L/C	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
805	Sri Ram Jee Kori	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
721	Sri Hanif Shaikh	L/C	E	72 58	87.50	..	..	13 00	173.08
850	Sri Ram Sevak Nonia	L/C	E	73 88	87.50	.	..	13.00	174.38
880	Sri Ram Autar Mallah	L/C	E	73.88	87 50	..	..	13.00	174.38
806	Sri Ram Autar Koiri	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
797	Sri Nabi Ahmed Khan	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
646	Sri Bishwanath Dusadh	L/C	E	76.70	87.50	..	..	13.00	177.20
652	Sri Bishwanath Kahar	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
791	Sri Kail Nonia	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
792	Sri Kesher Dusadh	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13 00	174.38
799	Sri Rojmohmed Sheikh	L/C	E	83.88	87.50	..	..	13 00	174.38
1117	Sri Lachhu Kahar	L/C	E	76.70	87.50	..	1 82	13.00	179.02
C4	Sri Ram Bilas Nonia	L/C	E	61.10	87.50	..	..	13.00	171.60
C7	Sri Wakil M. D. Khan	L/C	E	61.10	87.50	..	..	13.00	161.60
C24	Sri Gupteshwar Ram	L/C	E	61.10	87.50	..	..	13.00	161.60
C41	Sri Hanbar Koiri	L/C	E	61.10	87.50	..	..	13.00	161.60
1479	Gulabchand Dhobi	L/C	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
TRAM LINE :									
1731	Sri Tribeni Ram	Khalasi	E	71.28	87.50	..	..	13.00	171.78
854	Sri Chhote Kolh	L.C.	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1537	Sri Jagpat Kandoo	L/C	E	72.58	87.50	..	..	13.00	173.08
1577	Sri Ramgati Naua	L.C.	E	73 88	87.50	..	..	13.00	174.38
HAULAGE DRIVER									
1343	Sri Brichh Bhuia	L.C.	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38
1380	Sri Dukhi Ahir	H.M.	F	76.70	87.50	..	10.16	13.00	187.36
1514	Sri Ram Kishun Ahir	L.C.	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1508	Sri Meghu Chero	L.C.	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
1595	Sri Mahesh Singh	L.C.	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02
612	Sri Jamalu Sheikh	L.C.	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02

REVISED

Designation	Grade	Rate of Pay						Remarks
		Basic	D.A.	A.D.A.	P.A.	H.A.	Total	
T.M./L.C.	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38	
,,	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38	
,,	E	76.70	87.50	..	0.52	13.00	177.72	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	76.70	87.50	—	1.82	13.00	179.02	
,,	E	72.58	87.50	..	..	13.00	173.08	
,,	E	76.70	87.50	..	..	13.00	177.20	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	76.70	87.50	..	1 82	13.00	174.38	
,,	E	76.70	87.50	..	..	13 00	177.20	
,,	E	73.88	87 50	..	..	13.00	174.38	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38	
,,	E	72.58	87.50	..	..	13.00	173.08	
,,	E	73.88	87.50	..	.	13.00	174.38	
,,	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38	
,,	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38	
,,	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38	
,,	E	76.70	87.50	..	..	13.00	177.20	
,,	E	73.88	87.50	.	..	13.00	174.38	
,,	F	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38	
,,	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38	
,,	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38	
,,	E	76.70	87.50	..	1.82	13.00	179.02	
,,	E	61.10	87.50	..	..	13.00	161.60	
,,	E	61.10	87.50	..	.	13.00	161.60	
,,	L	61.10	87.50	..	..	13.00	161.60	
,,	E	61.10	87.50	..	.	13.00	161.60	
,,	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38	
T.L. Mate/Khalasi	D	70.20	87.50	3.51	..	13.00	174.21	
Tramline Khalasi	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38	
,,	E	72.58	87.50	..	..	13.00	173.08	
,,	E	73.88	87.50	..	..	13.00	174.38	
Haulage Driver	D	72.80	87.50	3.64	..	13.00	176.94	
,,	D	83.20	87.50	4.16	.	13.00	187.86	
,,	D	75.40	87.50	3.77	..	13.00	179.67	
,,	D	75.40	87.50	3.77	..	13.00	179.67	
,,	D	75.40	87.50	3.77	..	13.00	179.67	
,,	D	75.40	87.50	3.77	..	13.00	179.67	

Annexure 2

Statement of persons to be taken on permanent roll w.e.f 1-1-78

Sl. No.	Name	Father's name
1	2	3
1.	Shankar Nath Chattaraj	Bholanath Chattaraj
2.	D.K. Sukla	B.N. Sukla
3	Rajkumar Ram	Badri Ram
4.	Kameshwar Pd. Sinha	Ambika Pd.
5.	Rajkumar Ram	Ram Naresh Ram
6.	Manohar Sharma	Laxmi Sharma
7.	Nirmal Yadav	Gurudayal Ahir
8.	Ram Subash Yadav	Balrul Ahir
9.	Sattar Sheikh	Sakoor Sheikh
10	Mohiuddin Khan	Hidayat Khan
11.	Laxuman Kahar	Jhulen Kahar
12	Bigan Lohar	Charitar Lohar
13.	Laxuman Dusadh	Ramdhani Dusadh
14.	Charitar Nonia	Raghunandan Nonia
15	Ghoghan Kahar	Mahadeo Kahar
16	Tribhuwan Mishra	Dasarath Mishra
17	Nanhkoo Mishra	Raja Mishra
18.	Gopal Ram	Rupdeo Dusadh
19.	Sahadat Khan	Hedayat Khan
20.	Ganauri Rajwar	Lochi Rajwar
21	Karamdeo Kahar	Khaderan Kahar
22.	Mohd. Nasim Khan	Wahab Khan
23.	Sirfuddin Hussain	Amil Hussain
24.	Suleman Ansari	Sahmir Ansari
25.	Ganauri Nai	Dukhan Nai
26	Ram Subhag Ahir	Matar Ahir
27.	Bharat Kahar	Raghunandan Kahar
28.	Ganauri Kandu	Ramkhelawan Kandu
29	Hukam Ahir	Bhadai Ahir
30	Charitar Dhobi	Ramdeo Dhobi
31.	Ramchander Dusadh	Jawahir Ram
32.	Brichh Ahir	Janu Ahir
33.	Fakira Ahir	Jaduni Ahir
34.	Nand Ahir	Jeduni Ahir
35.	Belash Ahir	Sukhdeo Ahir
36.	Bandhan Dhobi	Dina Baitha
37.	Achhaibar Ram	Dhanukdhari Ram
38.	Bhola Kandu	Ganauri Sah
39.	Kutubuddin Dafali	Dargahi Mian
40.	Hazarat Gulkhan	Mohd. Gulkhan
41.	Rambriksh Ram	Tapeshari Dusadh
42.	Jaigobind Ram	Kesho Thakur
43.	Mohd. Rasool Sheikh	Kabeddin Sheikh
44.	Jagdish Dhangar	Banshi Dhangar
45.	Balakhan Yadav	Ramsaran Yadav
46.	Bindesari Chamar	Gariban Chamar
47.	Indradeo Ram	Ram Sewak Ram
48.	Suleman Ansari	Roj Mohd, Mian
49.	Tribeni Thakur	Mahang Thakur
50.	Saraju Thakur	Muneshar Thakur
51.	Deodhari Mahato	Ghinahu Mahato
52.	Dewa Singh	Keshwar Singh
53.	Ramsundar Yadav	Balrup Yadav
54.	Uma Kant Dubey	Girja Dubey
55.	Gopal Ram	Ramasaran Yadav
56.	Ayodhya Singh	Ramgrihi Singh
57.	Sri Kishore Singh	Muneshwar Singh
58.	Tek Bahadur	Dor Bahadur
59.	Yam Bahadur	Pagbir Gurung
60.	Rajendra Nonia	Parmesar Nonia
61.	Nasiruddin Sheikh	Gulzar Sheikh
62.	Ramji Ahir	Dukhan Ahir
63.	Krishna Choudhry	Deonandan Choudhry
64.	Balkishun Koiri	Ramdeni Koiri
65.	Gangia Nonia	Bhikhari Nonia
66.	Mukhdeeo Dusadh	Tula Dusadh
67.	Mangaru Ahir	Firangi Ahir
68	Hanif Sheikh	Abdul Sheikh
69	Kasarat Kumhar	Sheodhani Kumhar
70.	Laxman Teli	Keshwar Teli
71.	Sitaram Dhobi	Sunder Dhobi
72.	Sheo Nonia	Teni Nonia
73.	Lepa Dhanger	Legan Dhanger
74.	Samundri Bhuin	Nirpat Bhuian
75.	Deosaran Dhangar	Bihari Dhangar
76.	Ramdas Kumhar	Seodhani Kumhar
77.	Mansoor Khan	Wali Khan
78.	Chhathu Dhangar	Sukhai Dhangar
79.	Chandrika Ahir	Dhanpat Ahir
80.	Sarfu Khan	Zarif Khan
81.	Balkesar Dhangar	Deo Dhangar
82.	Ramlagan Nonia	Anantu Nonia
83.	Dhurbhikshan Koiri	Jagdeo Koiri
84.	Charitar Nonia	Pragash Nonia
85.	Rajia Dhangrin	Kalicharan Dhanga
86.	Suraju Chamar	Kesar Chamar
87.	Ramjit Kahar	Mehang Kahar
88.	Chhathu Chamar	Khelawan Chamar
89.	Kawalpati Cherin	Sabhikhan Chero
90.	Kesar Chamar	Langatu Chamar
91.	Mohan Ahir	Dewan Ahir
92.	Ramchela Yadav	Ramdas Ahir
93.	Rajia Bhuin	Mangru Bhuian
94	Narain Ahir	Dhanuiki Ahir
95.	Kutubuddin Ansari	Janabu Ansari
96.	Jagdish Teli	Ramdas Teli
97.	Deobans Kumhar	Bahadur Kumhar
98.	Kawlapatia Bhuin	Janan Bhuian
99.	Kabutri Bhuin	Ram Pd. Bhuian
100.	Nazir Sheikh	Nimma Sheikh
101.	Bigan Rajwar	Sewak Rajwar
102.	Sitaram Dusadh	Tulsi Dusadh
103.	Koloiya Dhangrin	Janki Dhangar
104.	Parmesar Ahir	Tulsi Ahir
105.	Bageshar Kahar	Baldeo Kahar
106.	Ramkisun Kahar	Seotahal Kahar
107.	Jaishri Dhobi	Akalu Dhobi
108.	Ghuman Rajwar	Nanhai Rajwar
109.	Raghuram Bhiuan	Bhagelu Bhuian
110.	Kesar Dhangar	Jhari Dhangar
111.	Deonarain Lal	Saraju Lal
112.	Sahdeo Ahir	Jokhan Ahir
113.	Lechhuman Chamar	Deonath Chamar
114.	Bipat Chamar	Nanhak Chamar
115.	Babulal Dusadh	Chandri Dusadh
116.	Bibhan Dhangar	Mahabir Dhangar
117.	Saudagar Gareri	Ramjatan Gareri
118.	Rambriksh Kahar	Jaisri Kahar
119.	Shyambihar Chamar	Basudeo Chamar
120.	Rambelas Dhangar	Ramjit Dhangar
121.	Parmesar Dusadh	Lakhpat Dusadh
122.	Ramjanam Bhuian	Bhagan Bhuian
123.	Alimuddin Sheikh	Chheda Sheikh
124.	Abdul Khalique	Istahak Khan
125.	Sheonath Pandey	Bonimadho Pandey
126	Raman Ahir	Bhuletan Ahir
127.	Ram Pd. Dhangar	Sukar Dhangar

1	2	3
128.	Naurang Kahar	Balkesar Kahar
129.	Jirmania Dhangrin	Bechan Dhangar
130.	Ghura Chamar	Sobnath Chamar
131.	Ramkirit Dhangar	Lagan Dhangar
132.	Matukhdhari Nonia	Ramprit Nonia
133.	Birbal Kandu	Nathuni Kendu
134.	Lachhuman Koiri	Bhajan Koiri
135.	Bhagirathi Ahir	Jhulani Ahir
136.	Nageshar Dhangar	Ramdhani Dhangar
137.	Radheshyam Kumhar	Raghunandam Kumhar
138.	Jagdish Chamar	Manger Chamar
139.	Nizaimuddin Sheikh	Rahmat Sheikh
140.	Pargas Ahir	Aniwas Ahir
141.	Mundrika Ahir	Laldhani Ahir
142.	Arjun Koiri	Brichh Koiri
143.	Bisnath Sahu	Jaga Sahu
144.	Baleshwar Kolh	Janki Kolh
145.	Ramnath Koiri	Sukhari Koiri
146.	Dasarath Thakur	Ramdeni Thakur
147.	Mukhlal Koiri	Fakira Koiri
148.	Ramprawesh Tewari	Damodar Tewari
149.	Kamaldeo Koiri	Sukhari Mahto
150.	Pargas Koiri	Dukei Koiri
151.	Sukhlal Koiri	Fakira Koiri
152.	Satyanarain Ram	Ramkisun Ram
153.	Chandradip Ram	Munshi Ram
154.	Jasodwa Bhuin	Ramsunder Bhuian
155.	Dhomuks Dusadh	Ramdni Dusadh
156.	Bajia Dhangar	Ramdhani Dhangar
157.	Sheo Koiri	Jagroop Koiri
158.	Binod Bihari	Jagnarain Ram
159.	Sudama Ram	Dhanukdhari Ram
160.	Ramkrit Ahir	Dukhi Ahir
161.	Kail Bhuian	Sukhdeo Bhuian
162.	Rambriksh Kahar	Chhakauri Kahar
163.	Patia Dusadhin	Bisunath Dusadh
164.	Kailash Dusadh	Sahdeo Dusadh
165.	Tilakdhari Dhangar	Mangar Dhangar
166.	Ramsewak Ram	Sita Dusadh
167.	Rajmohan Koiri	Sadhuni Koiri
168.	Ramjanam Koiri	Rupu Koiri
169.	Harihar Mahto	Ramdas Koiri
170.	Jibasia Bhuin	Sukan Bhuian
171.	Tikhuri Nonlain	Akalu Nonia
172.	Roj Mohd. Sheikh	Sarfud in Sheikh
173.	Ramlakhan Nonia	Sunder Nonia
174.	Prithwi Ram	Kail Ram
175.	Motichand Dhobi	Girdhari Dhobi
176.	Nathuni Sheikh	Kasim Sheikh
177.	Mohd. Hassan	Abdul Sheikh
178.	Rambelash Nonia	Basudeo Nonia
179.	Madan Mohan Pathak	Bhola Pathak
180.	Ramchander Nonia	Budhu Nonia
181.	Wakil Mohd. Khan	Gulam Rasul Khan
182.	Jirwa Bhangrin	Karamdeo Dhangar
183.	Budhia Chamain	Chanderdeo Chamar
184.	Ganesh Bhuian	Sohrai Bhuian
185.	Ramchander Bhuian	Jethu Bhuian
186.	Manmatia Dhangrin	Dasarath Dhangar
187.	Karami Dhangrin	Balesar Dhangar
188.	Rajkumar Chero	Sabhikhan Chero
189.	Ramjanam Rajwar	Hari Rajwar
190.	Panu Dhangar	Kesar Dhangar
191.	Budhan Dusadh	Brichh Dusadh
192.	Ramadhar Kandu	Sita Kandu
193.	Kapildeo Singh	Janki Singh
194.	Gupteshwar Ram	Amirchand Kahar
195.	Srinath Kahar	Ghura Kahar
196.	Moti Lal	Jagarnath Lal
197.	Sadamir Khan	Hajrat Mir Khan
198.	Jamuna Thakur	Ramkeshwar Thakur
199.	Rajmohan Sharma	Jaisri Mistri
200.	Dilip Kumar	Krishna Lohar

[No. L-29011/57/74—L.R. IV/D. III (B)]

KANWAR RAJINDER SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 1st December, 1982

S.O. 4216.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the National Industrial Tribunal, Bombay on a complaint from the workman under section 33(A) of the said Act, which was received by the Central Government on the 24th November, 1982.

BEFORE THE NATIONAL INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

Complaint No. NTB-5 of 1980

(Arising out of Reference No. NTB-1 of 1980)

PARTIES :

Ramsagar Shivlal Harijan,
Bindu Bangla,
S. V. Road, Ville Parle (West)
Bombay-400056. ...Complainant.

Versus

Air-India,
Air-India Building,
Nariman Point,
Bombay-400021. ...Opposite Party.

APPEARANCES :

For the complainant—Mr. M. B. Anchan, Advocate.

For the opposite party—Mr. B. P. Israni, Advocate.

INDUSTRY : Airlines. STATE : Maharashtra

Bombay, the 14th day of October, 1982

AWARD

This is a complaint filed by the complainant under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947, against the opposite party, Air-India, Bombay.

2. The complainant alleged that he was employed as a loader in the Cargo Department of the opposite party since January, 1973 at Santa Cruz Airport. On 18th October, 1976 he was charged for the alleged stealing of a parcel containing some solution worth Rs. 5 from the mail bag at Mail Section. A complaint was lodged with the Police and the Police filed a criminal case against him in the Court of the Metropolitan Magistrate, 22nd Court at Andheri, Bombay. The learned Magistrate by his order dated 21st June, 1977 convicted the complainant under Section 381 of the I.P.C. and sentenced him to suffer simple imprisonment till the rising of the Court and to pay a fine of Rs. 200. The complainant preferred criminal revision application in the Court of Sessions, Greater Bombay. This application was dismissed and the conviction was confirmed.

3. The complainant alleged that when he was charged for the alleged theft he was told by the Departmental Head that he will be taken back on duty if he succeeded in the criminal case. The complainant approached the officer after his conviction in the criminal court. He was told that since he has been convinced he will not be taken back on duty. The complainant submitted that opposite party has not charged him for the said misconduct under the Service Regulations nor a show-cause notice was issued to him as required under rules. His removal from service is therefore against the principles of natural Justice, mala fide and illegal. At the time of his illegal removal Reference No. NTB-1 of 1980 was pending before this Tribunal and the complainant was concerned in that dispute. The complainant therefore alleged that the opposite party has committed breach of

Section 33 of the Idustrial Disputes Act. The complaiant therefore prayed that this Tribunal be pleased to decide the complaint and pass orders thereon reinstating him with full back wages and continuity of service.

4. The opposite party, Air-India, filed its written statement on 31st March, 1982, pleading as follows. The complainant was a casual worker doing work of a casual nature in the cargo section of the opposite party at Santa Cruz, Bombay. He used to work only on such days when his services were required by the opposite party and that too only if he made himself available for work on those days. There was no obligation on him to prevent himself for work on any particular day or days. Similarly, there was no obligation on the opposite party to engaged him for duty on any day or days on which he might present himself for work. On 18th October, 1976 he was arrested by the Police on a charge of theft. The opposite party therefore decided not to engage him thereafter for casual work. The opposite party was not bound or liable to given any work to the complainant. Thus, there has been no removal from service as alleged by the complainant. There was no reference pending before this Tribunal on 19th October, 1976, from which date the complainant was not given work. In these circumstances, there was no question of applying for approval under Section 33(2)(b) of the Industrial Disputes Act. There was no breach of the provisions of Section 33 and consequently no complaint can lie under Section 33A. The opposite party pointed out that the order of reference pertaining to Reference No. NTB-1 of 1980 was made on 29th January, 1980, and the alleged action of removal from service took place before the said reference was made by the Central Government to this Tribunal. Consequently, there was no question of making an approval application. It was denied that the complainant was employed as a loader as alleged by him. There was no question of taking him back on duty since he was only a casual worker. There was also, according to the opposite party, no question of the opposite party having charged him with misconduct. The complainant being a casual worker it was at the option of the opposite party to assign to him or not to asign to him duties on any particular day or days. His not being assigned duties after 18th October, 1976, does not according to the opposite party amount to his removal from service.

5. The complainant had engaged the services of an Advocate. On 14th October, 1982 which was the date of hearing of this complaint, Mr. Anchan, the learned counsel for the complainant, informed this Tribunal in writing that the complainant did not want to prosecute further this complaint and that he be allowed to withdraw the same. It was prayed that an award may be made accordingly disposing of this complaint.

6. According to the complainant, the complaint arose out of reference No. NTB-1 of 1980. The opposite party has pointed out that the order of reference pertaining to the said reference is dated 29th January, 1980. Even on the admission of the complainant he was not given work from 18th October, 1976 or thereabout. On that day, he was charged for the alleged theft of the article mentioned in the complaint. He was convicted by the learned Magistrate on 21st June, 1977. It is the contention of the opposite part that the complainant was a casual labourer, and that the opposite party was not bound or liable to give any work to the complainant. No work was given to him after he was found to have committed theft of some article from the mail bag at Mail Section. The Reference No. NTB-1 of 1980 was obviously not pending when the complainant according to him was removed from the service. According to the opposite party, as he was a casual labourer there was no question of removal. For all these reasons there is no merit in this complaint. The complaint is therefore liable to be rejected.

7. My award accordingly. No order as to costs.

M. D. KAMBLI, Presiding Officer
[No. L-11014(1)/82-D.II(B)]

S. S. PRASHER, Desk Officer

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1982

का० आ० 4217:- केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में अपना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2194 तारीख 27-5-82 द्वारा लोह अयस्क उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 4-6-1982 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ: मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 4-12-82 से छ: मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस-11017/8/81-डी -1 (ए)]

नन्द लाल, अवर सचिव

New Delhi, the 1st December, 1982

S.O. 4217.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 2194 dated the 27-5-1982 the iron ore mining industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 4-6-1982;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 4-12-1982.

[No. S-11017(8)/81-D. I (A)]

NAND LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982

का० आ० :—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री तारा शंकर मुखर्जी को मुख्य खान निरीक्षक के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या ए० 12025/1/81 एम-1]

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 4218.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri Tara Sankar Mukherjee as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines.

[F. No. A-12025/1/81-MI]

का० आ० 4219.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री आर० रामा चन्द्रन को मुख्य खान निरीक्षक के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० ए० -12025/4/81 एम० 1]

जे०के० जैन, अवर सचिव

S.O. 4219.—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri R. Ramachandran as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines.

[F. No. A-12025/4/81-MI]

J. K. JAIN, Under Secy.

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 4220.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Ahmedabad in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Baroda, Ahmedabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 27-11-82.

BEFORE SHRI G. S. BAROT, PRESIDING OFFICER,

INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT

AHMEDABAD.

Reference (ITC) No. 3 of 1982

Adjudication

BETWEEN

The Management of Bank of Baroda, Ahmedabad

AND

Their workmen.

In the matter termination of services of Shri I G. Shah.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, have, vide their Order No. L-12012/160/80-L II(A) dated February, 1982, referred for my adjudication the industrial dispute between the management of Bank of Baroda and their workmen, under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947. The dispute relates to the matter specified in the Schedule appended to the said Order, viz :—

"Whether the action of the management of Bank of Baroda, Regional Office, Ahmedabad, in terminating the services of Shri I. G. Shah with effect from 7-6-73 is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled and from what date ?"

2. It appears that usual notices were issued to the parties. Shri I. G. Shah, the workman concerned, filed his statement in support of his case for reinstatement in service with full back wages, and the matter was pending for filing of the statement by the management of Bank of Baroda. However, on 29-10-82, the parties stated that they had arrived at an amicable settlement in this matter, and that therefore this reference be disposed of in terms of their settlement Going through the settlement submitted by the parties, it appears to me that it is just, fair and reasonable and in the interest of the workman concerned. I, therefore, take the settlement on record at Ex. 8 and make award in terms of Ex 8 which is annexed hereto and marked Annexure 'A'. Considering the circumstances of this case, I direct the management of Bank of Baroda to pay Rs. 75 by way of costs of this matter.

G. S. BAROT, Presiding Officer

ANNEXURE 'A'

FORM-H

Name of parties :

Representing Employer.—Mr. A. J. Menezes, Regional Manager, Bank of Baroda, Kaira Region, Opp. Income Tax Office, Ahmedabad-380014.

Representing the workman.—Mr. K. R. Mehta, Authorised Representative, Manapor Chakla, Gamdhi Sheri, Dabhoi-391110,

SHORT RECITAL OF CASE

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, vide its order No. L 12012/160/80-D II(A), dated 8th February 1982 referred the Industrial Dispute over alleged illegal termination of services of Shri I. G. Shah w.e.f. 7th June 1973 before the Industrial Tribunal, Ahmedabad-I. The concerned workman Shri I G. Shah filed his statement of claim before the Hon'ble Industrial Tribunal, Ahmedabad. During the pendency of the claim before the court, negotiations were going on between both the parties mentioned above for amicable settlement of aforesaid Industrial Dispute. The parties have now settled the dispute as follows :

TERMS OF SETTLEMENT

1. The Management of Bank of Baroda will reinstate Shri I. G. Shah residing at Baroda as an confirmed employee on starting basic salary of Rs. 580 p.m. as per the Third Bipartite Settlement with continuity of service with effect from 12-5-1972.

2. The terms of the Settlement will be implemented/ come into operation on completion of one month from the date of signing of this Settlement subject to the following :

(a) Shri I. G. Shah is found medically fit;

(b) Shri I. G. Shah agrees that his absorption as stated above is in full and final settlement of all his claims against the Bank.

(c) Shri I. G. Shah will not claim any back wages and other consequential benefits like leave, medical aid etc.

(d) Shri I. G. Shah gives an undertaking not to claim any special allowance for a period of five years from the date of his absorption.

(e) Shri I. G. Shah agrees to withdraw all his representations in the matter made to the various authorities under the Law.

Representing Workman	
(K. R. MEHTA)	Representing Employer.
Authorised Representative	(A. J. Menezes)
Witnesses :	
1. Shri S. M. Nayak,	Regional Manager
2. Miss S. B. Arya	Kaira Region
Date.—29th October 1982.	Ahmedabad.
Place.—Ahmedabad.	

[No. L 12012/160/80-D. II (A)]

S.O. 4221.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab and Sind Bank, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 2, BOMBAY.

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande, Presiding Officer

Reference No. CGIT-2/9 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Punjab & Sind Bank.

AND

Their Workman

APPEARANCES :

For the Employer.—Shri D. O. Sanghvi, Advocate (2) Shri Ranjit Singh, Officer.

For the workman—(1) Shri Surinder Singh Bali, President Punjab & Sindh Bank Employees' Union, (2) Shri Gopal Sharma (Workman in person).

INDUSTRY : Banking

STATE : Maharashtra

Bombay, the 11th November, 1982

AWARD

By their order No. L-12012/214/81-D. II(A) dated 25-1-1982 the Central Government have referred the following dispute for adjudicaidon under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of the management of Punjab & Sind Bank in relation to their Masjid Bunder Branch, Bombay in terminating the services of Shri G. B. Sharma, Peon with effect from the 2nd May, 1979 is justified ? If not to what relief is the workman concerned entitltd to ?"

2. As is evident from the order of reference, the reference relates to the termination of the services of Shri G. D. Sharma, peon with effect from 2-5-1979. What is referred is to find out whether the said termination order is justified and if not what relief can be extended to the workman. The matter has been espoused by the Union on behalf of the workman and the Union as well as the management have reached at a settlement whereby on making a fresh application for appointment on probation as a Peon, the Bank has assured to consider the prayer and in fact it has been already given. It is true that had the matter been contested and had the matter been decided in favour of the workman he would have got far more than the reliefs which he is getting under the settlement. Yet the parties it seems have decided that instead of leaving the matter to the vagaries of law better come to the terms of settlement. The Union has cerified the terms of settlement as just, fair and reasonable with which endorsement I fully agree on going through the relief offered to the cashiered peon. The settlement is reasonable, fair and proper and order can be passed in terms thereof. Award is made accordingly. No order as to costs.

Sd/-

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

Dated the, 17-11-82.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II, BOMBAY.

Reference (CGIT No. 2/9 of 1982

BETWEEN

Management of Punjab & Sind Bank

AND

Their Workmen

Memorandum of Settlement on behalf of Punjab & Sind Bank in response to the proposal received from the workmen.

May it please the Honourable Tribunal—

SHORT RECITAL OF THE CASE

Whereas Sh. Gopal Dutt Sharma was given a appointment of a Temporary Peon at B/o Masjid Bunder, Bombay for the period 27-5-1978 to 26-6-1978, 29-6-78 to 28-8-78 & 1-9-78 to 31-10-78.

And whereas Sh. Gopal Dutt Sharma was taken on probation into the service of the bank at its Musjid Bunder branch w.e.f. 3-11-78 as a Peon. And whereas Sh. G. D. Sharma was not confirmed in bank's service and was informed vide letter dt. 2-5-79 to that effect.

And whereas Sh. G.D. Sharma raised an industrial dispute on his nonconfirmation which was subsequently referred to Central Govt. to CGIT, Bombay for adjudication which is still pending.

Whereas Sh. G. D. Sharma has represented to the bank vide his letter dt. 20-10-82 and has requested for a fresh employment in the Bank. The parties have mutually agreed to settle the dispute in the following terms.

Terms of Settlement :

1. That the management has agreed as a gesture of goodwill to offer fresh appointment as a Peon to Sh. G. D. Sharma on probation for a period of six months at branch office.

2. That Sh. G. D. Sharma will make an application for fresh appointment on probation as a Peon with the Bank.

3. That Sh. G. D. Sharma has agreed that his fresh appointment will be new and he will not be entitled to for any claim/benefit monetary or otherwise for the past service rendered by him with the bank.

4. That Sh. G. D. Sharma has agreed that he will not claim any back wages or claim any compensation nor the continuity of service with the bank for his service rendered previously i.e. prior to 10-11-82.

5. That in view of this settlement the employees has agreed not to raise any dispute of whatsoever in nature about his past service with the bank and will not claim any relief whatsoever from civil courts, Labour Courts/Tribunal/Conciliation Office or any other authority.

6. That the CGIT Bombay where the dispute is pending would be requested by the parties to give an award in terms of this settlement.

For the Workmen :

For the Management :

Witness :

1. Sd|- illigible

2. Sd|- illigible

Sd|- illigible

[No. L-12012(214)/81-D. II (A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982

का० आ० 4222.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि हेमाटाइट खानों के नियोजन की बाबत मजदूरी की दरें, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन नियत की जानी चाहिएं ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियोजन को उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग I से जोड़ने के अपने आशय की सूचना देती है ;

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व उक्त परिवर्धन की बाबत किसी व्यक्ति से जो भी सुझाव या आक्षेप प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

[एस० 32017/3/82-डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू०)]

एम० एल० मेहता, अवर सचिव

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 4222.—Whereas the Central Government is of opinion that the minimum rates of wages should be fixed under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in respect of the employment in Hematite mines;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 27 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to add the said employment to Part I of the Schedule to the said Act.

Any suggestions or objections which may be received from any person in respect of the said addition on or before the expiry of a period of three months from the date of publication of this notification in the official Gazette, will be considered by the Central Government.

[No. S-32017/3/82-WC(MW)]

M. L. MEHTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982

का० आ० 4223.—केन्द्रीय सरकार, लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 10 के अनुसरण में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उक्त अधिनियम के अधीन वित्तपोषित क्रियाकलापों की निम्नलिखित रिपोर्ट उस वर्ष के लेखा विवरण के साथ इसके द्वारा प्रकाशित करती है।

भाग I

(क) साधारण :—लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 लौह अयस्क पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का तथा लौह अयस्क खान उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलाप के वित्त पोषण का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम पहली अक्तूबर, 1963 को प्रवृत्त हुआ था और पहली अक्तूबर, 1964 को उसका विस्तार गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र को कर दिया गया। पूर्वोक्त अधिनियम लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 (1976 का 55) और लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। नए अधिनियमों में निर्यात किए गए और अन्तर्देशीय उपयुक्त लौह अयस्क के प्रति मीटरी टन पर अधिक से अधिक एक रुपया और मैंगनीज अयस्क के प्रति मीटरी टन पर छह रुपया की दर से उपकर उद्ग्रहण करने का उपबंध किया गया है। 1-7-81 से लौह अयस्क पर उद्ग्रहण की दर को 25 पैसे प्रति मीटरी टन से बढ़ाकर 50 पैसे प्रति मीटरी टन कर दिया गया है मैंगनीज अयस्क पर उद्ग्रहण की वर्तमान दर एक रुपया प्रति मीटरी टन है। उपकर के आगमों का उपयोग मुख्य रूप से लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार, रोग निवारण, शैक्षिक सुविधाओं और चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था और उनमें सुधार और जल प्रदाय योजनाओं, सामाजिक दशाओं में बेहतरी और आमोद-प्रमोद आदि की सुविधाओं के उपबंध आदि के लिए किया जाता है। कल्याण सुविधाएं सीधे नियोजित कर्मकारों या ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित कर्मकारों को दी जाती हैं।

2. उपकर, निर्यात किए गए लौह मैंगनीज अयस्क पर सीमा शुल्क के रूप में और अन्तर्देशीय रूप से उपयुक्त लौह/मैंगनीज अयस्क उत्पाद-शुल्क के रूप में उपभोग उपकर उद्ग्रहीत किया जाता है। कल्याण आयुक्तों को भी अन्तर्देशीय उपयोग उपकर के संग्रहण के प्रयोजनार्थ उपकर आयुक्तों के रूप में घोषित किया गया है और उनकी अधिकारिता भी अधिसूचित की गई है। सीमाशुल्क के रूप में कल्याण उपकर का संग्रहण सीमा-शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है जिसे संग्रहण प्रभार के रूप में 1/2 प्रतिशत दिया जाता है।

(ख) कल्याण कार्य :—विभिन्न शीर्षों के अधीन कल्याण कार्य नीचे दिए गए हैं, जिन पर वर्ष के दौरान कल्याण निधि से पूंजी लगाई गई है।

(i) चिकित्सा सुविधाएं :—

1000 रुपये प्रतिमास मूल वेतन पाने वाले लौह अयस्क मैंगनीज अयस्क श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं संगठन द्वारा मुफ्त दी जा रही थी। कर्मकारों और उनके आश्रितों को संगठन द्वारा लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क उत्पादक राज्यों में स्थापित निम्नलिखित अस्पतालों/औषधालयों आदि में चिकित्सीय सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं :—

बिहार

1. केन्द्रीय अस्पताल, बड़ाजामदा (50 शैयाएं)।
2. चल चिकित्सा औषधालय, बड़ाजामदा।
3. स्थिर एलोपैथिक औषधालय, करमपाड़ा।
4. स्थिर एलोपैथिक औषधालय, नुआमुंडी।

उड़ीसा :

1. केन्द्रीय अस्पताल, जोड़ा (50 शैयाएं)।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाजरी।
3. चल चिकित्सा औषधालय, बारबिल।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुआगांव।
5. बाम पहाड़ स्थिर व चल अस्पताल यूनिट।
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोमका।
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिगोरा।

महाराष्ट्र

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेडी।

मध्यप्रदेश

1. चल चिकित्सा औषधालय, राजहारा।
2. चल चिकित्सा औषधालय, बैलाडिला (डिपोजिट सं० 5)।
3. चल चिकित्सा औषधालय, बैलाडिला (डिपोजिट सं० 14)।

कर्नाटक

1. केन्द्रीय अस्पताल, करीगनूर (25 शैयाएं)।
2. चल चिकित्सा औषधालय, करीगनूर।
3. स्थिर व चल चिकित्सा औषधालय, सन्डूर।

गोवा :

1. केन्द्रीय अस्पताल, पिल्लियम, दर बंदोरा टिस्का गोवा (20 शैयाएं)
2. चल चिकित्सा औषधालय, सिरगुन्दरम।

इसके अतिरिक्त लौह अयस्क/मायस्कर मैंगनीज खनिजों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के प्रयोग के लिए टी बी० सैनेटोरियमों और अन्य अस्पतालों में शैयाओं का आरक्षण जारी रखा गया। बिहार क्षेत्र के लिए ऐसी 45 शैयाएं और उड़ीसा क्षेत्र के लिए 32 शैयाएं, महादेवी बिड़ला सैनेटोरियम, रांची में उपलब्ध है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में सेंट ल्यूक्स अस्पताल, वेन्गुरला में भी 2 शैयाएं आरक्षित रखी गई है। मध्य प्रदेश में खनिकों और उनके आश्रितों के प्रयोग के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के भिलाई स्थित मुख्य अस्पताल में 4 शैयाएं और जिला मुख्यालय अस्पताल क्योंझर में 5 साधारण शैयाएं आरक्षित की गई हैं।

आन्ध्र प्रदेश में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क खनिकों को चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक डाक्टर की अंशकालिक सेवाएं जारी रखी गई।

बालाघाट, मध्य प्रदेश में 50 शैयाओं वाला अस्पताल स्थापित करने के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया है।

लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खानों के ऐसे मालिकों को, जो निर्धारित मानक तक औषधालय और अस्पताल चला रहे हैं। वार्षिक सहायता अनुदान दी गई है।

आलोच्य वर्ष के दौरान लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 57.81 लाख रुपये खर्च हुए।

(ii) आवास सुविधाएं :

लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क खनिकों के लिए आवास की व्यवस्था करना संगठन के मुख्य कार्यकलापों में से एक कार्यकलाप है। तीन योजनाएं है अर्थात्— (1) कम लागत आवास योजना (टाइप I) (2) नई आवास योजना टाइप II और (3) अपना मकान बनाओ योजना (टाइप I)। मकान की अनुमानित लागत 6825 रुपये है। काली कपास वाली या उभार वाली मिट्टी वाले क्षेत्र में 7915 रु० है जबकि टाइप-II मकान की अनुमानित लागत 11,325 रुपये है। काली कपास वाली या उभार वाली मिट्टी वाले क्षेत्र में 13,425 रुपये है। अपना मकान बनाओ योजना के अन्तर्गत मकान की अनुमानित लागत 1500 रु० है। 600 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में और 900 रुपये बिना ब्याज के ऋण के रूप में दिए जाते हैं।

2. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने आवास कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करने के लिए उप समिति गठित की है। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है।

3. निधि के स्थापन से विभिन्न आवास स्कीमों के अधीन 2,980 मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी। अब तक 11,549 मकान तैयार हो चुके है और 420 मकान निर्माणाधीन है। आलोच्य वर्ष में आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए निधि से कुल 2,427 लाख रुपये व्यय हुआ।

(iii) जल प्रदाय सुविधाएं :— निधि के स्थापन से विभिन्न क्षेत्रों में मंजूर की गई 43 जल प्रदाय स्कीमों में से 33 जल प्रदाय स्कीमें चल रही है जिससे यह सूचित किया जाता है कि शेष योजनाएं प्रगति पर है। अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 45 कुएं खोदे गए है। आलोच्य वर्ष के दौरान जल प्रदाय स्कीमों पर कुल 18.09 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। आलोच्य रिपोर्ट की अवधि के दौरान, उड़ीसा में बार्इलगोल क्षेत्रों में 2.08 करोड़ रुपये की लागत से एक समेकित जल प्रदाय योजना की मंजूरी दी गई है। इस योजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि में से केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 1981-82 के दौरान राज्य सरकार को 16.50 लाख रुपये दिए गए है। राज्य सरकार इस योजना को पूरा करने के लिए एजेंसी का कार्य करेगी।

(iv) शैक्षणिक और आमोद-प्रमोद की सुविधाएं: लौह/मैंगनीज अयस्क खान कर्मकारों और उनके परिवारों के लिए शैक्षणिक और आमोद-प्रमोद सुविधाओं में, जिनका खर्च निधि से किया जाता है, 40 बहु उद्देशीय संस्थानों, 2 कल्याण केन्द्रों, 6 महिला बाल कल्याण केन्द्र, 13 चल चित्र एकक, एक अवकाश गृह, 159 रेडियो केन्द्र तथा तीन परिवहन बसें सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्र में खानों के मालिकों को खेल-कूद, खेल टूर्नामेंट आदि के आयोजन के लिए सहायता अनुदान मंजूर किए गए हैं। अनुमोदित योजना के अनुसार लौह/मैंगनीज अयस्क खान श्रमिकों के उन बालकों को छात्रवृत्ति देने की सुविधा जारी रखी गई, जो विद्यालयों/महाविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, गोवा, उड़ीसा और बिहार क्षेत्रों के स्कूलों के बच्चों को मध्याह्न भोजन देने की स्कीम जारी रखी गई। इस स्कीम को महाराष्ट्र क्षेत्र में शुरू किया गया है। मध्याह्न भोजन की दर 75 पैसे प्रति बालक प्रतिदिन है। कुछ क्षेत्रों में लौह अयस्क खनिकों के प्राथमिक स्कूल में जाने वाले बालकों के लिए वर्दियां भी दी गई है। आलोच्य वर्ष के दौरान इन सुविधाओं पर कुल 20.71 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी।

(v) घातक और गम्भीर दुर्घटना लाभ योजना

दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों की विधवाओं और बच्चों को वित्तीय सुविधाएं देने की योजना को आलोच्य वर्ष के दौरान जारी रखी गई।

भाग-II

पहली अप्रैल, 1981 को अवशेष	1,83,63,860.98
वर्ष 1981-82 के दौरान प्राप्तियां	1,85,56,116.36
वर्ष 1981-82 के दौरान व्यय	1,34,08,884.17
31 मार्च, 1982 को अवशेष	2,35,11,093.17

भाग-III

1982-83 के लिए प्राप्तियां और व्यय का प्राक्कलन।

1. प्राक्कलित प्राप्तियां	1,80,00,000.00
2. प्राक्कलित व्यय	2,06,13,000.00

[फाईल सं० एच-12015/2/82-एम० 4/WII]

टी० डी० मल्होत्रा अवर सचिव

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 4223.—In pursuance of section 10 of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976), the Central Government hereby publish the following report of the activities financed under the said Act, during the year ending the 31st March, 1982 together with a statement of accounts for that year.

PART I

(a) General.—The Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961 was enacted to provide for levy and collection of cess on Iron Ore for financing activities to promote the Welfare of the labour working in the Iron Ore Mining industry. The Act came into force on the 1st October, 1963 and was extended to the Union Territory of Goa, Daman and Diu on the 1st October, 1964. The aforesaid Act has been replaced by the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1976 (55 of 1976) and the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976). The new Acts provide for the levy of a cess at a rate not exceeding one rupee per metric tonne of iron ore and rupees six per metric tonne on manganese ore exported or consumed internally. The rate of levy on iron ore has been increased from 25 paise per metric tonne to 50 paise per metric tonne with effect from 1-7-81. The present rate of levy on manganese ore is Re. 1 per metric tonne. The proceeds of the cess are utilised mainly for improvement of public health and sanitation, prevention of diseases, provision and improvement of

educational facilities, medical facilities, housing and water supply schemes, amelioration of social conditions, provision of recreational facilities etc. The Welfare facilities cover workers employed directly or through contractors.

2. The cess is levied as a duty of customs on the iron ore and manganese ore exported, and as a duty of excise on iron ore and manganese ore consumed internally. The Welfare Commissioners have also been declared as Cess Commissioners and their jurisdictions have been notified for purposes of collections of cess on internal consumption. The collection of welfare cess as a duty of customs is made by the Departmental of Customs who are paid half per cent towards collection charges.

Welfare activities.—The Welfare activities under different heads financed during the year from the welfare funds are indicated below :—

(i) Medical facilities.—Medical facilities to iron ore and manganese ore workers getting a basic pay of Rs. 1,000 per month and their dependents were provided free by the organisation. Facilities were made available to the workers and their dependents in the following hospitals/dispensaries etc. established by the Organisation in different iron ore/manganese ore producing states.

BIHAR.—(1) Central Hospital, Barajamda (50 beds).
(2) Mobile Medical Dispensary, Barajamda.
(3) Static Allopathic Dispensary, Karampada.
(4) Static Allopathic Dispensary, Nuia.

ORISSA.—(1) Central Hospital, Joda (50 beds).
(2) Primary Health Centre, Jaruri.
(3) Mobile Medical Dispensary, Barbil.
(4) Primary Health Centre, Nuagaon.
(5) Static-cum-Mobile Medical Unit at Madampur.
(6) Primary Health Centre, Tomka.
(7) Primary Health Centre, Siljore.

MAHARASHTRA.—(1) Primary Health Centre, redi (Distt. Sindhudurg).

MADHYA PRADESH.—(1) Mobile Medical Dispensary, Rajhara.
(2) Mobile Medical Dispensary, Bailadila (Deposit No. 5).
(3) Mobile Medical Dispensary, Bailadila (Deposit No. 14).

KARNATAKA.—(1) Central Hospital, Kariganur (25 beds).
(2) Mobile Medical Dispensary, Kariganur.
(3) Static-cum-Mobile Medical Dispensary, Sandur.

GOA.—(1) Central Hospital, Pilliem, Darbandora, Tiska Goa (50 beds).
(2) Static-cum-Mobile Medical Dispensary, Curchorem.

Besides, beds were continued to be reserved for the exclusive use of Iron/Manganese Ore mines and their families in T. B. Sanatoria and other hospitals. 45 such beds for Bihar region and 32 beds for Orissa region are available in the Mahadevi Birla Sanatorium, Ranchi. Similarly, 2 beds have also been reserved at St. Lukes Hospital, Vengurla in Maharashtra. In Madhya Pradesh, 4 beds were reserved in the Bhilai main hospital of the Hindustan Steel Ltd. and 5 general beds were reserved in the Distt. Headquarters Hospital at Keonjhar for the use of miners and their dependents.

The services of a part-time doctor were continued providing of medical facilities to the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Workers in Andhra Pradesh.

A proposal to set up a 50 bedded hospital at Balaghat, Madhya Pradesh has been approved in principle.

The owners of the iron ore mines or manganese ore mines who maintain the dispensaries and hospitals up to the prescribed standard have been paid annual grants in-aid.

A total expenditure of Rs. 57.81 lakhs was incurred on the provision of medical facilities to the iron ore mines and manganese ore mine workers and their dependents during the year under report.

(ii) Housing Facilities.—Provision of housing accommodation for iron ore and manganese ore miners is one of the main activities of the organisation. There are three scheme viz. :—

(i) Low Cost Housing Scheme (Type I).
(ii) New Housing Scheme (Type II).
(iii) Build Your Own House Scheme.

The estimated cost of Type I house is Rs. 6,825—Rs. 7,925 in black cotton or swelly soiid area) while the estimated cost of Type II house is Rs. 11,325—Rs. 13,425 in black cotton or swelly soil area. The estimated cost of house under Build Your Own House Scheme is Rs. 1500—(Rs. 500 is paid as subsidy and Rs. 900 as interest-free laon).

2. The Central Advisory Board had constituted a Sub-Committee to review the Housing Programmes. The report has been received and is under examination.

3. Under the various housing schemes, a total number of 12,980 houses had been sanctioned for construction from the inception of the Fund. Out of these 11,549 houses have so far been completed and 420 houses are under construction. The total expenditure from the Fund for providing housing facilities in the year under report was Rs. 24.27 lakhs.

(iii) Water supply facilities.—Out of 43 water supply schemes sanctioned in various regions since the inception of the Fund, 33 water supply schemes are in operation. The rest were reportedly in progress. 85 wells have so far been sunk in the different regions. The total expenditure on water supply schemes during the year under report was Rs. 18.06 lakhs.

During the period under report, an integrated Water Supply Scheme costing a total of Rs. 2.08 crores on Vaitrani Valley in Orissa has been sanctioned. 50 per cent of the total cost on this scheme will be borne by the Central Government out of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund. A sum of Rs. 16.50 lakhs have been released to the State Government during 1981-82. The State Government will be the agency for execution of the scheme.

(iv) Educational and recreational facilities.—The educational and recreational facilities provided to the iron/manganese ore mine workers and their families which were financed from the Fund included 40 Multipurpose Institutes, 2 Welfare Centres, 6 Women-cum-Children Welfare Centres, 13 Cinema Units, 1 Holiday Home, 159 Radio Centres and three Transport Buses. Grants-in-aid were sanctioned to mine owners for organising sports, games, tournaments etc. in the Madhya Pradesh region. Scholarships continued to be given to the children of iron/manganese ore mines workers studying in schools, colleges and technical institutions in accordance with the approved scheme. The mid-day meals scheme for the school children was continued in Madhya Pradesh, Goa, Orissa and Bihar regions. This scheme has also been introduced in Maharashtra region. The rate for supply of mid-day meals is 75 paise per child per day. Uniforms were also supplied to the Primary school going children of iron ore miners in some regions. The total amount spent on these facilities during the year under report was about Rs. 20.71 lakhs.

(c) FATAL AND SERIOUS ACCIDENT BENEFIT SCHEME

The scheme for financial benefits to widows and children of victims of accidents was also continued during the year under report.

PART II

Opening balance as on 1st April, 1981	1,83,63,860.98
Receipt during the year 1981-82	1,85,56,116.36
Expenditure during the year 1981-82	1 34,08,884.17
Closing balance as on 31st March, 1982	2,35,11,093.17

PART III

Estimates of receipts and expenditure for the year 1982-83

1. Estimated receipts	1,80,00,000.00
2. Estimated expenditure	2,06,13,000.00

[F. No. H. 12015/2/82-M. IV/W II]
T. D. SALHOTRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर 1982

का० आ० 4221.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चौ० सत्या नारायण (बी० ई०) कान्ट्रेक्टर 45-35-29, जगनाथपुरम विसाखापत्तनम-16, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/473/83-पी०एफ-2]

New Delhi, the 25th November, 1982

S.O. 4224.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ch. Satyanarayana (B.E.) Contractor, 45-35-29, Jagannadhapuram, Visakhapatanam-16, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(473)/82-PF. II]

का० आ० 4225—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मोन्टगोमरीज होटल 108, सरोजनी देवी रोड, सिकन्दराबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/472/82-पी०एफ-2]

S.O. 4225.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Montgomery's Hotel, 108, Sarojini Devi Road, Secunderabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(472)/82-PF. II]

का० आ० 4226.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स के० एल० एम० इंजीनियरिंग इन्टरप्राईजेज सी-13, इन्डसट्रियल स्टेट, बेलगाम-590008. नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/471/82 पी एफ-II]

S.O. 4226.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs K.L.M. Engineering Enterprises, C-13 Industrial Estate, Belgaum-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of ection 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019 (471)|82-PF. II]

का० आ० 4227.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एग्रीकलचरल इमप्लिमेन्टस मैनूफैक्चरर्स एंड सप्लायरस विरुपाक्षा कृपा विद्यानगर हुबली-21, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/470/82-पी० एफ-2]

S.O. 4227.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Agricultural Implements Manufacturers and Suppliers, Virupaksha Krupa, Vidya Nagar, Hubli-21, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019-(470)|82-PF. II]

का० आ० 4228.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हैमासवेनी स्पिनरस गोरमेन्ट ऑफ इण्डिया प्रेस कालोनी, मेटटपलायम रोड, कोयमटूर-19, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/469/82 पी० एफ-2]

S.O. 4228.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hamsaveni Spinners, Government of India Press Colony, Mettupalayam Road, Coimbatore-19, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019 (469)|82-PF. II]

का०आ० 4229.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कनफैब इंजीनियरस, 73 लेटिस ब्रिज रोड थिरुवनमीयुर मद्रास-41, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/468/82 पी० एफ-2]

S.O. 4229.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Confab Engineers, 73, Lattice Bridge Road, Thiruvanmiyur, Madras-41, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefort, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S. 35019(468)/82-PF. II]

का०आ० 4230.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कोरवेट विबरो स्क्रीनस प्र० लि० कारापक्कम विलेज महाबली पुरम हाई रोड, मद्रास-600096. नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/463/82 पी० एफ-2]

S.O. 4230.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Korvette Vibro Screens (Private) Limited, 137-A|1D, Karapakkam Village, Mahabalipuram High Road, Madras-96, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applits the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(463)|82-PF. II]

का० आ० 4231.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स क्विन इंडिया लि० 3-6-307/1 हेदरगुडा, हैदराबाद-50001, जिसमें उसकी 17, ओरमेस रोड, किलपाक, मद्रास-600010 स्थित शाखा भी है, नामक स्थापन से सबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/467/82-पी० एफ-2]

S.O. 4231.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Quinn India Limited, 3-6-307|1, Hyderaguda, Hyderabad-1 including its branch at 17, Ormes Road, Kilpauk, Madras-10, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsiction (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(467)/82-PF. II]

का० आ० 4232.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सेन्ट्रल इंजीनियरिंग वर्क सेन्ट्रल स्टुडियोज कालोनी सिंगानल्लोर पी० ओ कोयमबटूर-5, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/466/82-एफ-2)]

S.O. 4232.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Central Engineering Works, Central Studios Colony, Singanallur Post Office, Coimbatore, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(466)/82-PF.II]

का०आ० 4233.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बालाजी फैबरिकेटरस प्रा० लि० 144 शिवाराम विलेज, पेरुंगुडी, मद्रास-600096, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[एस० 35019/465/82-पी० एफ-2]

S.O. 4233.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Balaji Fabricators (Private) Limitd, 144, Seevaram Village, Perungudi (Post Office), Madras-96, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central

Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(465)/82-PF.II]

का० आ० 4234.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स संकरागिरी स्टेट चेनकारा परिमेड टोलुक इडुक्की डि० केराला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० ए 35019/464/82-पी०एफ-2]

S.O. 4234.—Whereas it appears to the Central Govtrnment that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sankaragiri Estate, Chenkara, Peermade Taluk, Idukki District, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(464)/82-PF.II]

का० आ० 4235.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंडीपेन्डेन्ट टैस्टिंग कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड, 1, वेंनियर स्ट्रीट मद्रास-1, जिसमें उसकी (1) न० 21 डा० वी० बी० गांधी मार्ग बम्बई-23 (महाराष्ट्र), (2) "शांति" प्लाट नं० 66, रंजीत नगर, बेदी रोड, जामनगर-2 (गुजरात) और (3) नं० 66 थियेटर रोड, फ्लैट नं० 2, कलकत्ता-17, (प० बंगाल) शाखाएं भी शामिल हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019 / 460 / 82 -पी० एफ० -2]

S.O. 4235.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Independent Testing Company (Private) Limited, 1, Vannier Street, Madras-1 including its branches at (1) No. 21, Dr. V. B. Gandhi Marg, Bombay-23 (Maharashtra), (2) "Shanthi", Plot No. 66, Ranjit Nagar, Bedi Road, Jamnagar-2 (Gujarat) and (3) No. 66, Theatre Road, Flat No. 2, Calcutta-17 (West Bengal) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Micellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(460)/82-PF.II]

का० आ० 4236.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री मपिल्लाई विनयगार स्वीट ड्रिन्कस जी० एस० टी० रोड, पैकारा मदुराई-17 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019 / 459 / 82 -पी० एफ० 2]

S.O. 4236.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Mappillai Vinayagar Sweet Drinks, G.S.T. Road, Pykara, Madurai-17, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(459)/82-PF.II]

का० आ० 4237.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ओवरसीज शिपिंग ऐजेन्सीज, 50 मूर स्ट्रीट मद्रास और उसकी (1) 43-7-1 ओल्ड पोस्ट आफिस रोड, काकिनाडा 1 आन्ध्र प्रदेश (2) 34 भारत बिल्डिंग पाजे मगशे राओ रोड, मंगलौर (कर्नाटक) स्थित शाखाएं भी शामिल हैं नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/450/82 पी० एफ-2]

S.O. 4237.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Overseas Shipping Agencies, 50, Moore Street, Madras including its branches at (1) 43-7-1-, Old Post Office Road, Kakinada-1 (Andhra Pradesh), (2) 34, Bharath Building, Panje Mangesh Rao Road, Mangalore-1, (Karnataka), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(458)/82-PF.II]

का० आ० 4238.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्रीयल कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड बी-6, इलेक्ट्रानिक इंडस्ट्रीयल स्टेट, कुशैगुडा हैदराबाद 762, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं:

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/457/82 पी०एफ०-2]

S.O. 4238.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Electronic Components Manufacturing Industrial Co-operative Society Limited, B-6, Electronic Industrial Estate, Kushaiguda, Hyderabad-762, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(457)/82-PF.II]

का० आ० 4239.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हनुमान सेक्यूरिटी सरविसेज एडमिनिस्ट्रेटिव आफिस, न० 4 आश्रम स रबर्तो पुर धरवाड करनाटक जिसमें उनका पंजीकृत कार्यालय मार्फत राजा रेड्डी उडयाकोटम, छठी मजिल सागर कम्पलेक्स केम्पागोवडा रोड, बंगलौर-9 भी शामिल है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस 35017/456/82 पी एफ-2]

S.O. 4239.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hanuman Security Services, Administrative Office, No. 4, Ashram, Saraswathipur, Dharwar (Karnataka), including its Registered Office Care of Raja and Reddy, Advocates, 6th Floor, Sagar Complex, Kempegowda Road, Bangalore-9, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(456)/82-PF.II]

का० आ० 4240.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वडसेरि परियारिसन्गन स्ट्रीट हैंडलूम वीवर्स सेल्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सं० 3461, वान्चीअथन न्यू स्ट्रीट वडसेरि नागरकोइल-1 जिसके अन्तर्गत (1) स० 3461, विक्रय डिपो नगरपालिका बस स्टैंड के सामने दुकाले डाकघर कन्याकुमारी जिला, और (2) सं० 3461, द्वार सं० 7-75 ए आर सी पार्सल कार्यालय के निकट, मंडे मार्किट न्यूर डाकघर कन्याकुमारी जिला स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/235/82-पी एफ 2]

S.O. 4240.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vadasery Pirraiasingan Street Handloom Weavers Sales Co-operative Society Limited, No. 3461, No. 26, Vanchiathuthan New Street, Vadasery, Nagercoil-1 including its branches at (1) No. 3461, Sales Depot, Opposite to Municipal Bus Stand, Thuckalay, Thuckalay Post, Kanyakumari District and (2) o. 3461, Door No. 7-75, Near A.R.C. Parcel Office, Monday Market, Ntyyoor Post, Kanyakumari District, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(235)/82-PF.II]

का० आ० 4241:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एस० सन्यासी राव एंड कम्पनी इंजीनियर कान्ट्रेक्टर्स एंड मैटीरियल सप्लायर्स नथयापालेम बी० एच० पी० वी० डाकघर विशाखापटनम, (आन्ध्र प्रदेश), नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/394/82-पी० एफ-2]

S.O 4241.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs S. Sanyasi Rao and Company, Engineers, Contractors and Materials Suppliers, Nathayyapalem, B.H.P.V. Post, Visakhapatnam. (Andhra Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(394)/82-PF.II]

का० आ० 4242:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि तालुक मैसर्स राइथारा सेवा सहकारी संघ लिमिटेड, होम्नावेली टिप्तुर जिसके अन्तर्गत कोनेनहल्ली, टिप्तुर तालुक, टुमकुर जिला, (कर्नाटक) स्थित उसकी शाखा भी है । नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/198/82-पी० एफ०-2)]

S.O. 4242.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rythara Seva Sahakari Sangha Limited, Hommavally, Tiptur Taluk, *including its branch at Konenahally, Tiptur Taluk*, Tumkur District (Karnataka), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Misscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to tht said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Cental Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(198)/82-PF. II]

का० आ० 4243:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ड्रिल राक इंजीनियरिंग (प्राइवेट) लिमिटेड, 5-4/187/324, करबला मैदान, सिकन्दराबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/152/82-पी एफ-2]

S.O. 4243.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Drill Rock Engineering (Private) Limited, 5-4, 187/324, Karbala Maidan, Secunderabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(152)/82-PF. II]

का० आ० 4244.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एन वी जी बी आटोमोबाइल्स सं० 104 ब्रिज स्टेशन मार्ग मदुराई-6250002, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/151/82-पी० एफ-2]

S.O. 4244.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs N.V.G.B. Automobiles, No. 104, Bridge Station Road, Madu-

rai-625002, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S. 35019(151)/82-PF. II]

का०आ० 4245 :— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री लक्ष्मी स्पिनर्स, 545 सथी मार्ग गणपति, कोयम्बटूर 641006 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/149/82-पी० एफ-2]

S.O. 4245.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shree Laxmi Spinners, 545, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore-641006, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(149)/82-PF. II]

का०आ० 4246 :— केन्द्रीय सरकार को प्रतीत होता है कि मैसर्स नारायण एन्टरप्राइसेस ठेकेदार ऑडको साइकल स्टैण्ड 114, बट्ट मार्ग, सेंट थामस माउन्ट, मद्रास-16, नन्दमबक्कम के निकट, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है

[सं० एस-35019/148/82-पी० एफ-2]

S.O. 4246.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Narayanan Enterprises, Contractor, Audco Cycle Stand, 114, Butt Road, St. Thomas Mount, Madras-16 (Near Nandambakkam), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(148)/82-PF. II]

का०आ० 4217 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स व्यवसाय सेवा सहकारी संघ नियमित शिकारीपुर, जिला : शिमोगा कर्नाटक, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35519/147/82-पी० एफ-2]

S.O. 4247.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vyavasaya Seva Sahakari Sangha Niyamita, Shikaripur Shimoga District (Karnataka), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(147)/82-PF. II]

का० आ० 4248 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बाचा सन्स, पीस गुड्स मरचेन्टस, 166-ए, ईस्ट मासी स्ट्रीट, मदुरई-625001, इसके अन्तर्गत रोजरी बिल्डिंग, टाउन हाल मार्ग, मदुरई-625001, स्थित उसका शोरूम भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-36019/146/82-पी० एफ-2]

S.O. 4248.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Batcha Sons, Piece Goods Merchants, 166-A, East Masi Street, Madurai-625001 including its Show Room at Rosary Building, Town Hall Road, Madurai 625001 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(146)/82-PF. II]

का० आ० 4249 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री खिमिजी भाई मिल्स, पोस्ट बाक्स नं० 120, रविवारपेट, बेलगाम, कर्नाटका राज्य, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/145/82-पी० एफ 2]

S.O. 4249.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Khimijibhai Mills, Post Box No. 120, Raviwarpet, Belgaum, Karnataka State, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(145)/82-PF. II]

का० आ० 4250 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पायोनियर मुथू थीएटर, ओझूगिनासेरी, नागेरकोइल-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/144/82-पी० एफ-2]

S.O. 4250.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Pioneer Muthu Theatre, Ozhuginaseri, Nagercoil-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(144)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1982

का० आ० 4251—मेसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर काम्पलैक्स-बंगलौर-560017 (के०एन०/24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/29/82-पी०एफ-2]

New Delhi, the 26th November, 1982

S.O. 4251.—Whereas Messrs Hindustan Aeronautics Limited Bangalore Complex, Bangalore-560017 (KN/24) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of

accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nowithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(29)/82-PF. II]

का०आ० 4252.—मैसर्स दि आल्विन्स एण्ड कम्पनी, आन्ध्र ब्रुअरीज एण्ड डिस्टिलरीज, मलकाजगिरि हैदराबाद-500047 (आ०प्र०/3103) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में, असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस० 35014/246/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4252.—Whereas Messrs Shaw Wellance and Company Ltd., Andhra Winery and Distillary, Malkajgri, Hyderabad-500047 (AP/3103) (hereinafter referred to as the said establishment) have applitd for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh maintain such accounts and Provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014(246)/82-PF. II]

का०आ० 4253.—मैसर्स इस्टर्न एग्रो प्राडक्ट्स (प्रा०) लिमिटेड, 1 एण्ड 2 गोविन्दपुरा इण्डस्ट्रियल एस्टेट भोपाल-462023 (मध्य प्रदेश/1528) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त

अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, सेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन से नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उसके सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/247/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4253.—Whereas Messrs Eastern Air Products (P) Ltd., 1&2 Govindpur, Industrial Estate, Bhopal-462023 (MP/1528) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenace of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an empolyee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(247)/82-PF. II]

का० आ० 4254.—मैसर्स मैनन एण्ड मैनन प्राईवेट लिमिटेड, विक्रम नगर कोलहापुर –416005(महाराष्ट्र/2191) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों के संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी विलम्ब की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस 35014/250/82-पी०एफ II]

S.O. 4254.—Whereas Messrs Menon and Menon Private Limited, Vikram Nagar, Kolhopur-416005, Maharashtra India (MH/2191) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment scheme do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(250)/82-PF. II]

का० आ० 4255.—मैसर्समे दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लिमिटेड, बाड़ा हिन्दू राव, दिल्ली-110006, (दिल्ली/2294) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अत, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस० 35014/198/82-पी०एफ०-2]

S.O. 4255.—Whereas Messrs The Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd., Bara Hindu Rao, Delhi-110006 (DL/2294) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the *Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952* (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The *employer in relation to the said establishment* shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Where is the employee who is already a member of the *Employees' Provident Fund* or the *Provident Fund* of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(253)/82-PF. II]

का०आ० 4256—मैसर्स दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग, शक्ति सदन, कोटला रोड, नई दिल्ली (डीएल/138) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिकानुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में, उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/257/82 पी०एफ०-2]

S.O. 4256.—Whereas Messrs Delhi Electric Supply Undertaking Sakti Sadan, Kotta Road, New Delhi (DL/138) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance scheme of the

Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and here any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(3257)/82-PF. II]

का० आ० 5257.—मैसर्स मुकन केमिकल्स प्लाट 10/3, जी०आई०डी०सी० एस्टेट वास्त्र अहमदाबाद (जी०टी०/5295) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा या अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/258/82-पी० एफ०-II]

S.O. 4257.—Whereas Messrs Sukan Chemicals, Plot No. 10/3, G.I.D.C. Estate, Vatva, Ahmedabad (GJ/5295) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case with 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014(258)/82-PF.II]

का० आ० 4258.—मैसर्स ए० पी० स्टेट अग्रो इण्डस्ट्रीज, डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद-500004 (आ०प्र०/3300) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने सर्वेक्षारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही,

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/230/82-पी० एफ-II]

S.O. 4258.—Whereas Messrs A.P. State Agro Industries Development Corporation Ltd., Hyderabad (AP|3300) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurace which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme

appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(2960)/82-PF. II]

का० आ० 4259.—मैसर्स मादर्न टैक्सटाईल्स लिमिटेड पोस्ट बाक्स नं० 1117 59 बी० वेल्कटा स्वामी रोड आर एस० पुरम कोयम्बतूर-641002 (तमिलनाडु (जिसेइसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/261/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4259.—Whereas Messrs The Southern Textiles Limited, P.B. No. 1117, 59-B, Venketasamy Road R. S. Puram, Coimbatore-(TN/937) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution on payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(261)/82-PF. II]

का० आ० 4260.—मैसर्स भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि० विशाखापत्तनम (आ०प्रा०/3495) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्रप्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा या अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसका बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्रप्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकेगी ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35011/262/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4260.—Whereas Messrs Bharat Heavy Plate and Vessels Ltd., Visakhapatnam (AP/3495) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurace which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities of inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(262)/82-PF. II]

का०आ० 4261.—मैसर्स तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० करूर (टी० एन०/5562) त्रिची जिला (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अत:, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(263)/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4261.—Whereas Messrs The Tiruchirapalli District Co-operative Spinning Mills Ltd. Karur, Trichy Distt. (TN/5562) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurace which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts **the said establishment from the operation of all the provisions of the said** Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamilnadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(263)/82-PF. II]

का०आ० 4262—मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यूनिट एच०पी० ई०पी० रामाचन्द्रापुरम हैदराबाद 500032(आ०प्र/2932) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किसूर या किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/264/82-पी० एफ०-II]

S.O. 4262.—Whereas Messrs Bharat Heavy Electricals Ltd., Unit, HFEP, Ramchandra Puram, Hyderabad-500032 (AP/2938) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Hyderabad, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, (Hyderabad), Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium etc. the responsibility for payment of insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(264)/82-PF. II]

का०आ० 4263.—भैसर्स हिमान्शु कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नं० 10/3, जी०आई०डी०सी० एस्टेट, नरोडा, अहमदाबाद (गुजरात/6895), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार को समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन

बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा मे उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो मे समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने मे असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय मे किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/265/82-पीएफ-II]

S.O. 4263.—Whereas Messrs Himansu Chemicals Private Limited, Plot No. 10/3A, GIDC Estate, Vatva, Ahmedabad (GJ/6895) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurace which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(265)/82-PF. II]

का० आ० 4264.—मैसर्स आर्ती पैट्रोकेमिकल्स इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात/1113) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना, नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को

जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस. 35014/266/82-पी.एफ.-II]

S.O. 4264.—Whereas Messrs Aarti Petro Chemical Industries Private Limited, Ahmedabad (GJ1113) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibilty for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(266)/82-PF. II]

का० आ० 4265.—मैसर्स कॉपर इंजीनियरिंग लिमिटेड, पूना-19 जिसमें उसकी (1) चिन्चवाड़, पूना-19 और (2) 654 जे०एम० रोड, पुणे-111004 पर स्थित शाखायें सम्मिलित हैं तथा चिन्चवाड़, पुणे-19 में स्थित कम्पनी (महाराष्ट्र/2814) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, (महाराष्ट्र) बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन सभी सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/301/82-पी०एफ-II]

S.O. 4265.—Whereas Messrs Cooper Engineering Limited, Poona-19 including its branches at (1) Chinchwad, Poona-19 and (2) 654 J. M Road, Pune-411004 and the concern at Chinchwad, Pune-19, (MH/2814) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

1042GI/82—10

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employer been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employee, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of

deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (301)/82-PF.II]

का०आ० 4266.— इलप्रो इंटरनेशनल लि०, चिंचवाडगांव, पूना-411033, जिसमें इसकी निम्नलिखित शाखाएं भी शामिल हैं - (1) नारीमन प्वाइंट, बम्बई (रजिस्टर्ड आफिस (2) दुबास चेम्बर्स, कुमटा स्ट्रीट, बम्बई (3) वेलसले हाउस कलकत्ता और (4) अर्चना आफिस कम्पलेक्स, ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/311/82-पी० एफ-II]

S.O. 4266.—Whereas Messrs Elpro International Limited, Chinchwadgaon, Poona including its registered office at Nariman Point, Bombay and branches at Dubash Chembers, Kampta Street, Bombay (ii) Wellesley House, Calcutta and (iii) Archna Office Complex, Greater Kailash-1, New Delhi (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (311)/82-PF. II]

का०आ० 4267—मैसर्स जय हिन्द सायकी लिमिटेड, डी-1 ब्लाक प्लाट न० 18/1 चिनचिवाड़, पूना—411019, (एम एच 14766) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त (बम्बई) महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को

प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन सभी सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदा के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस० 35014/314/82-पी०एफ० II]

S.O. 4267.—Whereas Messrs Jay Hind Sciaky Limited, D-1 Block, Plot No. 18/1, Chinchwad, Poona-411019 (MH/14766) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (314)/82-PF. II]

का०आ० 4268—मैसर्स बालचन्द्रनगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड पो० को० बालचन्द्रनगर (जिला पूना) (महाराष्ट्र/9128) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसा विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने का व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे, उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यथोचित अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/320/82-पी०एफ० II]

S.O. 4268.—Whereas Messrs Walchandnagar Industries Limited, P.O. Walchandnagar (District Pune) (MH/9128) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said estabilshment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the aid Act, is employed in

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No. S-35014 (320)/82-PF. II]

का० आ० 4269.—मैसर्स बालचन्दनगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (मुद्रणालय) डाकघर बालचन्दनगर, जिला पूणे (महा/91129) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/321/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4269.—Whereas Messrs Walchandnagar Industries Limited (Mudranalaya), P.O. Walchandnagar, District Pune (MH/9129) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (321)/82-PF.II]

फा०आ० 4270.—मैसर्स पीको इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, लोनी फैक्ट्रीज, लोनी कालभोई, पुणे-412201 (महा/2608), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र बम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उन सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एफ 35014/329/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4270.—Whereas Messrs Pelco Electronics and Electricals Limited, Loni Factories, Loni Kalbhoe, Pune-412201, (MH/2608) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government herbey exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) maintain, such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses invoved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect

adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the repsonsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (329)/82-PF. II]

का० आ० 4271.—मैसर्स पीको इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, पिम्परी फैक्ट्रीज, प्लाट 80, भोसारी इण्डस्ट्रियल एस्टेट पुणे-411026 (एम एच 9599) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र, बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र, बम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/330/82-पी० एफ-II]

S.O. 4271.—Whreas Messrs Pelco Electronics and Electricals Limited, Pimpri Factories, Plot 80, Bhosari Industrial Estate Pune-411026 (MH/9599) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (330)/82-PF. II]

का० आ० 4272.—मैसर्स पेंका इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कालवा फैक्ट्री, 3 एम० आई० डी० सी० इण्डस्ट्रियल एरिया, थाने बेलापुर रोड थाने 400601 एम०एच०/9340, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अत, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र बम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/331/82-पी० एफ-II]

S.O. 4272.—Whereas Messrs Pelco Electronics and Electricals Limited, Kalwa Factory, 3 MIDC Industrial Area, Thane-Belapur Road, Thane-400601, (MH/9349) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the, Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (331)/82-PF. II]

का० आ० 4273—मैसर्स महाराष्ट्र स्टेट हैण्डलूम्स कार्पोरेशन लिमिटेड 50, सेन्ट्रल एवेन्यु रोड, नागपुर-18 (महा/2893) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे, उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद; स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र बम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/331/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4273.—Whereas Messrs Maharashtra State Handlooms Corporation Limited, 50, Central Avenue Road, Nagpur-18 (MH/2893) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund, of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (332)/82-PF II]

का० आ० 4274—मैसर्स हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड, नासिक डिविजन, नासिक, डाकघर ओझार टाउनशिप नासिक जिला-महाराष्ट्र/8266 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन

देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/333/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4274.—Whereas Messrs Hindustan Aeronautics Limited, Nasik Division, P.O. Ojha Township, Nasik (MH/8266) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said(Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the sailent features threof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of Indi i as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (333)/82-PF. II]

का० आ० 4275:—मैसर्स हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स, पिम्परी, (पूना-411018) (महाराष्ट्र राज्य) (महाराष्ट्र/1459) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/339/82-पी० एफ०-II]

S.O. 4275.—Whereas Messrs Hindustan Antibiotics, Pimpri, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the emyloyers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (339)/82-PF. II]

का० आ० 4276—मैसर्स महाराष्ट्र स्टेट हेन्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड, 50-सैन्ट्रल एवेन्यू, नागपुर-18 (महाराष्ट्र/14704) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, निर्दिष्ट करे ;

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन से, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय अंतर्वलित है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4 निरासक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में तदनुरूप रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/340/82-पी० एफ०-2]

S.O. 4276.—Whereas Messrs Maharashtra State Handlooms Corporation Limited, 50, Central Avenue Road, Nagpur-18 (MH/14704) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their points of view

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(340)/82-PF. II]

का० आ० 4277—मैसर्स महाराष्ट्र स्टेट हैण्डलूम्स कार्पोरेशन लिमिटेड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, कुर्ला, बम्बई-400070 (महाराष्ट्र-5191) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अंशदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन ; प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/341/82-पी०एफ०2]

S.O. 4277.—Whereas Messrs Kamani Tubes Limited, Lal Bahadur Shastri Marg, Kurla, Bombay-70 (MH/5291) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Link Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the emplovers under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for anv reason, the emplover fails to pav the premimum within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in anv case within 7 days of the interest of the employees, the Regional Provident Fund Corporation of India.

[No. S-35014 (341)/82-PF. II]

का० आ० 4278.—मसर्स सलेम टेक्सटाइल्स लिमिटेड, सन्निपालायाम, नारसिंगापुरम, वाकयर अयूर, सलेम, जिला (तमिलनाडु/6517) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम, की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/342/82-पी एफ-2]

S.O. 4278.—Whereas Messrs Salem Textiles Limited, Sallipalayam, Narasingapuram Post Office, Attur Salem District (TN/6517) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including Maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, to that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to

the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (342)/82-PF. II]

का० आ० 4279—मैसर्स होचस्ट डाइज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, होइजन्ट हाऊस, नारीमन प्वाइन्ट बम्बई-21, (महाराष्ट्र/4527), जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसा विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र (बम्बई) के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं०एस-35014/343/82-पी०एफ-2]

S.O. 4279.—Whereas Messrs Hoechst Dyes' and Chemicals Limited, Hoechst House, Nariman Point, Bombay-21, (MH/4527) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than

the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bangalore, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (343)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1982

का० आ० 4280.—मैसर्स [illegible] टावर्स, नरीमन प्वाइण्ट बम्बई-21, (महाराष्ट्र/15448), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा

जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/389/82-पी० एफ-2]

S.O. 4280.—Whereas Messrs Hotel Oberoi Towers, Nariman Point, Bombay-2, (MH/15448) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the the said Scheme are enhanced, so that the benefits available Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominees of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased the exemption to liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(389)/82-PF.II]

का० आ० 4281.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 5 दिसम्बर, 1982 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 41 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"कन्नानोर जिले के तेलिचेरी तालुक में पाप्पासी राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

[संख्या एस-38013/38/82-एच० आई०]

S.O. 4281.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Ctntral Government hereby appoints the 5th December, 1982 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala namely :—

"The areas within the Revenue village of Pazhassi in Tellicherry Taluk of Cannanore District."

[No. S-38013/39/82-HI]

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1982

का० आ० 4282.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के पुनर्वास और कृत्रिम अंग विभाग, केन्द्रीय कर्मशाला और लांड्री के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 10 मार्च, 1977 से 30 सितम्बर, 1982 तक की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छूट देती है ।

2 पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाए जाएंगे ;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व सन्दत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों तो वे वापस नहीं किए जाएंगे ;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अवधि" कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी —

(i) धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों की सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये थे या नहीं ; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिये गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफल स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं , या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे, उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ,

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उसकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे, जिसे वे आवश्यक समझते है ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक का, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना , या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबहीं या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उसमें उद्धरण लेना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र विलम्ब से प्राप्त हुआ, तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० ए-38014/26/80-एच०आई०]

ए० के० भट्टाराई, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 1982

S.O. 4282.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the Central Workshop, Laundry and the Department of Rehabilitation and Artificial Limbs of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi from the operation of the said Act for a period with effect from 10th March, 1977 upto and inclusive of the 30th September, 1982.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations 1950;

(5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or

other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/26/80-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd December, 1982

S.O. 4283.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2599 dated the 21st June, 1982 published at page 2672 of the Gazette of India Part II, Section 3 Sub-section (ii) dated the 17th July, 1982, in line 3, for "Joyti" read "Jyoti"

[No. S-35019(98)/82-PF.II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982